हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 2022 (द्वितीय बैठक)

खण्ड–1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 2022

पृष्ठ संख्या

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

वॉक–आउट

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 2022 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न पश्चात् 2.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ होगी। अब डॉ. अभय सिंह यादव अपनी बात रखेंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसके बारे में बोलने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं । इस वर्ष को हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारे प्रजातंत्र की काफी एडवांस स्टेज पर ग्रोथ हो चुकी है और ज्यों ही हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र बढ़ा है वहां पर प्रजातंत्र की बढ़ती उम्र के साथ–साथ दो चीजों में और बढ़ोतरी हुई है, पहली तो सरकार के प्रति लोगों की अपेक्षा बढ़ी है। तदानुसार सरकार की जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं। हर सरकार हमेशा जिस मैनडेट के साथ सत्ता में आती है उस मैनडेट के अनुरूप लोगों की सेवा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर करती है। वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई थी तो हमारे समक्ष भारतीय जनता पार्टी का दर्शन था। उस दर्शन के अनुरूप हमने 'सबका साथ, सबका विकास' को लेकर सारे स्टेट का बराबर विकास करने की बात कही। उसके मुताबिक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि समग्र प्रदेश का पूरा विकास हो और उसी को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ी लेकिन बीच में कोरोना की बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष आ गई। कोरोना काल में बजट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर प्रैशर आया। उस दौरान सरकार ने बड़ी कुशलता से कोरोना महामारी का सामना किया और मुझे यह कहने में संदेह नहीं है कि इस संकट की घड़ी में सारा प्रदेश, पक्ष और विपक्ष सरकार के साथ लगा हुआ था । हमारी सरकार ने बड़ी कुशलता के साथ अपनी जिम्मेवारी महामारी के समय निभाई। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट में सरकार ने प्रदेश के विकास को दोबारा रास्ते पर डालने का प्रयत्न किया है। कोरोना महामारी के बाद किसी भी विभाग के बजट प्रस्ताव को देखा जा सकता है। उसमें सभी विभागों में कोई न कोई नयी योजना का विजन और लक्ष्य परिलक्षित हो रहा है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के बजट में स्पैशलाइज्ड डॉक्टर्स का अलग से कैडर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने रोहतक, पी.जी.आई. एम.एस. में आर्गन ट्रासप्लांट का प्रस्ताव किया है। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश को

टी.बी. मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है और स्वास्थ्य विभाग के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑवरहालिंग करने का भी प्रस्ताव किया है। जोकि बहुत ही सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, किसान हमारे प्रदेश की इकॉनमी की रीड है और किसानों के विकास के लिए जो प्रयत्न किये गये हैं वे वास्तव में सराहनीय हैं। चाहे फसल बीमा योजना हो यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं फसल बीमा योजना की परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं कि कितने किसानों ने इसे अडोप्ट किया है । किसान बीमा योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन से इंट्रोडयूज किया गया है। यह किसानों को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने का काम है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करने के लिए सुनिश्चित होगा और उसका आत्म विश्वास बढ़ेगा तथा स्टेट बजट पर कम भार पड़ेगा। इसी तरह से अटल भू–जल योजना केन्द्र सरकार की पानी के संचय और अंडरग्राउंड वाटर रीसाइक्लिंग के लिए लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। प्रदेश के जो ड्राई इलाके है जैसे हमारा दक्षिण हरियाणा है वहां बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे वहां दोहान और कृष्णावती दो बरसाती नदियां है । इन दोनों नदियों को अलग–अलग जगह से कैनाल पर जोड़ दिया गया है। यदि किसी को शक है तो वे जाकर देख सकते हैं। जहां दक्षिण हरियाणा में चार साल पहले दो–दो फव्वारे टयूबवैल पर चलते थे आज वहां 15 से 18 फव्वारे चल रहे हैं। इस प्रकार के अनेकों कार्य सरकार द्वारा किसानों के लिए किये गये हैं, जो सराहनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे समय का ध्यान है और मुझे आपकी घंटी से डर भी लगता है इसलिए मैं मुख्य बातों पर ही चर्चा करूंगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं हमारे दक्षिण हरियाणा से संबंधित कुछ योजनाओं की मांग मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने जा रहा हूं। एन.सी.आर. क्षेत्र पर यदि नजर डाल कर देखेंगे तो महेन्द्रगढ़ और भिवानी जिले ऐसे हैं जहां औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। अब जो आधारभूत ढांचा महेन्द्रगढ़ जिले में हमारी सरकार ने डाला है वह बहुत मजबूत है और वह औद्योगिक विकास के अनुकुल भी है। महेन्द्रगढ़ जिला नेशनल कैपिटल से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और तीन नेशनल हाईवे इस क्षेत्र से गुजरेंगे। इसके अतिरिक्त एक वेस्टर्न रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है जिसमें 1200 एकड़ पर लॉजिस्टिक हब बन रहा है। इस प्रकार से वहां पर रेलवे की कनेक्टिविटी भी है, नहर का पानी भी है और पढ़े लिखे बच्चे भी हैं। (विघ्न)

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, वहां पानी का तो आज भी अभाव है।

डॉ अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय दान सिंह जी को कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि समय सीमित है?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी एस.वाई.एल. के बारे में भी बतायें कि वह कहां गई?

डॉ अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. तो इनके द्वारा डुबोई हुई है, पता नहीं कब निकलेगी। मेरा निवेदन है विपक्ष के साथी मेरा समय खराब न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज के दिन दक्षिण हरियाणा में औद्योगिक विकास के अनुकुल वातावरण है और शुरूआत कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि महेन्द्रगढ़ जिले में कहीं भी औद्योगिक पार्क बनाया जाये ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। मैं यह नहीं कहता कि मेरे हल्के में ही औद्योगिक पार्क बनाया जाये। जहां भी मुख्यमंत्री जी उचित समझें महेन्द्रगढ़ जिले में एक औद्योगिक पार्क बना दिया जाये। इस विषय पर सरकार गंभीरता से विचार करे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार की स्वामित्व योजना अच्छी चल रही है। इसमें लगभग 80 प्रतिशत मामले ठीक चल रहे हैं, केवल 20 प्रतिशत मामले ऐसे हैं जिनमें अभी डिस्प्यूट है। इनके बारे में मेरा निवेदन है कि जो बचे हुए मामले हैं, उनका अधिकारी मौके पर जाकर, सुनवाई करके निपटान करें ताकि बिना काम का लिटिगेशन आगे न बढ़े। इसके अतिरिक्त नांगल चौधरी को म्युनिसिपल कमेटी बनाया गया था। वहां की कमेटी की तरफ से नांगल चौधरी में सब–डिविजन बनाने का प्रस्ताव रिकमंड होकर सरकार के पास आया हुआ है। शायद नांगल चौधरी एक मात्र ऐसी जगह रह रही है जिसका 45 किलोमीटर पर सब डिवीजन हैडक्वार्टर है । मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जल्दी फैसला करके सब डिवीजन बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, तीसरी और अंतिम बात यह है कि रेलवे लिंक का सर्वे हो रहा है जिसमें झज्जर से कनीना–कोसली और आगे राजस्थान के बहरोड़ अलवर तक रेलवे लिंक देने का सर्वे कम्पलीट हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को रेलवे के साथ टेक अप करके इस काम को जल्दी करवाया जाये ताकि प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिल सके। आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे वित्त वर्ष 2022–23 के बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने बजट को

पढ़ा तो लगा कि इस बजट में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उनसे हरियाणा प्रदेश के किसी भी वर्ग का कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात सोनीपत से ही शुरू करना चाहता हूं। जैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ था कि सोनीपत, पानीपत और करनाल तक हम मैट्रो परियोजना ला रहे हैं लेकिन उस मैट्रो परियोजना पर कितना पैसा खर्च होगा उस बात का जिक्र बजट में कहीं पर भी नहीं किया गया है। वर्ष 2017 में हरियाणा कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था कि दिल्ली से नरेला, कुंडली और नाथूपुर तक मैट्रो चलाई जायेगी। यह खबर अखबारों में भी छपी थी कि सोनीपत तक मैट्रो आ रही है और यह सोनीपत के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है तथा बाद में पानीपत तक भी पहुंचेगी। उस समय इसका समय भी निर्धारित किया गया था कि 2018 से शुरू हो कर 2022 तक इसका काम पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज 2022 आ गया है लेकिन दिल्ली से सोनीपत तक मैट्रो का कहीं पर भी नामोनिशान नहीं है। इस तरह से सोनीपत के लोगों को गुमराह किया गया। सोनीपत के लोग तो बहुत खुश थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको मैट्रो का तोहफा दिया है। जबकि कांग्रेस की हमारी सरकार ने दिल्ली से गुरूग्राम, दिल्ली से पलवल, दिल्ली से फरीदाबाद और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मैट्रो का विस्तार किया था। इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने मैट्रो के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जो कि करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट के प्वायंट नं. 293 मीडिया कर्मियों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है और पत्रकार सरकार व जनता के बीच सेतू के रूप में कार्य करते हैं लेकिन आज एक पत्रकार को उसका पूर्ण हक नहीं मिल रहा है। आज सभी पत्रकारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा नहीं मिल रही है। अगर किसी पत्रकार का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान बजट में रखना चाहिए था। इसके साथ ही साथ मीडिया काउंसिल का गठन भी किया जाना चाहिए। साथ लगते कांग्रेस शासित राजस्थान में पत्रकारों की समस्या के समाधान के लिए पत्रकार समिति का गठन किया गया है उसी प्रकार हरियाणा में भी पत्रकार समिति का गठन किया जाना चाहिए। गम्भीर बीमारी पर पत्रकारों को प्रति पत्रकार सहायता राशि दी जानी चाहिए थी लेकिन उसका भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है।

इसके साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को कैशलैस मैडिकल सुविधा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य पर भी आज पूरे हरियाणा में किसी भी जिले में सरकारी अस्पताल में आम नागरिक के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा नहीं हैं। अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो सोनीपत जिले की जनसंख्या लगभग 20 लाख है और आज तक सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत में कैथ लैब भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब स्थापित की जाये ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। सोनीपत नगर निगम के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि वहां पर कितना बजट दे रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात है उस संबंध में बेराजगार युवाओं के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि उनके लिए सरकार आने वाले समय में क्या सुविधाएं देगी। जैसे हमारे जो बच्चे बी.ए. पास हैं, ग्रेजुएट हैं या जिनके पास मास्टर डिग्री है वे घर पर खाली बैठे हुए हैं। अगर सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है तो उनको बेराजगारी भत्ता देने का प्रावधान तो इस बजट में सरकार को जरूर करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं की बात है उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए सरकार ने 2500 रुपये पैंशन देने का प्रावधान रखा है जबकि एक महिला अगर विधवा हो जाती है तो पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। एक या दो छोटे–छोटे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई का खर्च और उनके रहन–सहन के खर्च के लिए मैं समझता हूं कि उनके लिए इस बजट में कम से कम 10 से 15 हजार रुपये प्रति माह पैंशन देने का प्रावधान रखना चाहिए था जोकि सरकार ने नहीं रखा। इसी तरह दिव्यांग के लिए भी जो 1600 रुपये प्रति माह पैंशन रखी हुई है वह भी कम से कम 10 हजार रुपये होनी चाहिए थी। यहां जे.जे.पी. के विधायक साथी भी बैठे हुए हैं इन्होंने चुनाव से पहले एक नारा दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बुजुर्ग को 5100 रुपये प्रति माह पैंशन देंगे। अब सरकार भी बन गई और अब डिप्टी सी. एम. भी बन गये, जे.जे.पी. के मंत्री भी हैं उनका सरकार में साझा भी है तो वह 5100 रुपये पैंशन कहां गई। मैं निवेदन करता हूं कि इस बजट में कम से कम अपनी कही हुई बात को ही याद रखना चाहिए था और बुजुर्गों को 5100 रुपये प्रति माह पैंशन देनी चाहिए थी। सोनीपत के लिए जो ट्रॉमा सैंटर की वर्षों से मांग की

जा रही है उसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सोनीपत अब बहुत बड़ा जिला हो चुका है और वहां जी.टी. रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं लेकिन वहां पर कोई भी ट्रॉमा सैंटर नहीं है इसलिए उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान होना चाहिए था। सोनीपत सिविल होस्पिटल में कैंसर की जांच के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत में कैंसर जांच केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। सोनीपत में लड़कों के लिए राजकीय मैडिकल कॉलेज नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि इसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। इसी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं समझता हूं कि वह पूरे हरियाणा की ही समस्या है। हरियाणा में कहीं भी किसी भी नगर पालिका में लाईट खरीदने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में यह पता चला है कि आज से दो साल पहले हरियाणा सरकार ने चण्डीगढ़ की किसी कम्पनी को टैंडर दिया हुआ है और वही कम्पनी पूरे हरियाणा में लाईटें मुहैया कराएगी। पहले एक साल तो यही सुनते रहे कि वह कम्पनी पहले सर्वे कर रही है लेकिन अभी तक पूरे सोनीपत में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कहीं भी नई लाईटें लगाने का काम नहीं किया गया है। हम विधायक कोटे से भी वे लाईटें नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि पीछे मैंने 45 लाख रुपये देकर एक टेंडर लगवाया था जिसको सरकार ने कैसिंल करवा दिया था। डी.सी. साहब ने मुझे कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से लाईट्स लगाने का एक टैंडर हो रखा है। मैं बिजली विभाग के संबंध में कहना चाहूंगा कि सोनीपत में ट्रांसफार्मर्ज की समस्या है इसलिए इस बजट में नये ट्रांसफार्मर्ज को बदलने के लिए भी आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी होना चाहिए। मैं बिजली मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि सोनीपत में जहां–जहां नये ट्रांसफार्मर्ज की जरूरत है वहां–वहां नये ट्रांसफार्मर्ज लगवाने का काम करें।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में जहां ट्रांसफार्मर्ज बदलने होंगे, उनको हम बदलवा देंगे।

श्री सुरेन्द्र पंवार : धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे बोलने के लिए पूरा समय देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि ओल्ड पैंशन स्कीम को बहाल किया जाये क्योंकि बिना ओल्ड पैंशन के गवर्नमैंट इम्पलॉईज का

कोई लाभ नहीं है। बिना ओल्ड पैशन स्कीम के तो ये बेचारे बिना बात के ही गवर्नमैंट सर्वेंट बनकर रह जायेंगे। अतः ओल्ड पैंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम किया जाना चाहिए। ओल्ड पैंशन स्कीम को राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू किया है। इसी तरह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में ओल्ड पैंशन स्कीम लागू की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दूसरे विषय पर आता हूँ। हमारे यहां नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु के समय में सिसाय और बास दो म्युनिसिपल कमेटियां बनाई गई थी। सिसाय के अनेकों गणमान्य व्यक्ति मेरे पास आये और बोले कि ये कमेटियों उनको नहीं चाहिए क्योंकि ये कमेटियां उनके लिए नुकसानदायक हैं। मैंने इस संदर्भ में उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाया था और मुख्यमंत्री जी ने औचक निरीक्षण करवाकर कहा कि मैजोरिटी ऑफ पीपल इसको पसंद करते हैं, अतः ये कमेटियां वैसे की वैसे ही बनी रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो बास की अनाज मंडी है, वहां पर सारा गांव इक्ट्ठा हुआ। ये सब लोग चाहते हैं कि यहां पर कमेटी नहीं रहनी चाहिए। अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि पारदर्शी तरीके से सबसे पूछकर इस बारे में निर्णय किया जाये। अगर यहां के लोग कमेटी नहीं चाहते हैं तो यहां से म्युनिसिपल कमेटी तुरंत प्रभाव से खत्म कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह है कि ई.बी.पी.जी.सी. की 2015 में कई पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई थी। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह लिए गए और तमाम प्रकार की औपचारिकतायें पूर्ण करने का काम किया गया। इनमें जी.एस.ओ. 46 पद, ऑक्शन रिकार्डर 27 पद, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 17 पद, मंडी सुपरवाइजर 13 पद, पी.जी.टी. (हिस्ट्री) 19 पद, पुलिस के 18 पद, अकाउंटेंट तथा कई और पद भी शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके मार्फ्त माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि ये पोस्ट्स ठीक से प्लीड नहीं की गई। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का इनमें कोई इंट्रस्ट ही नहीं है। इस संदर्भ में केवल कोर्ट में जाकर सिर्फ एक हल्फनामा देने का ही काम करना था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वह माना जायेगा और सब्जैक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम इनको ड्यूटी ज्वॉयन करवा रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हुड्डा साहब के समय में एक दोहलीदार, बूटीमार, भौंडेदार तथा मुकररीदार बिल पास हुआ था जिसके माध्यम से दान के रूप में जमीन देने के प्रावधान को संभव बनाया गया था। उस समय विनोद शर्मा हाउस के मैम्बर थे, उन्होंने इसकी डिमांड की थी और

तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने इसको मंजूर करके कानून बनाने का काम किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार तथा मुकररीदार बिल जो 2010 में पास हुआ था और उसके बाद इसका कानून बना था, इसमें हुड्डा साहब के समय में थोड़ी सी कमी रह गई थी और वह यह थी कि 20 वर्ष की समयावधि की शर्त पूरी करने पर ही यह कानून लागू हो सकेगा। इसके बाद तो फिर वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अन्य कानून पास करके, इस कानून को खत्म करने का बड़ा जुल्म करने वाला काम किया और कानून बना दिया कि कोई भी आदमी प्राईवेट/पर्सनल प्रापर्टी तो दान कर सकता है लेकिन पंचायत या म्युनिसिपल कमेटी की जमीन दान नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, अनेक जगहों पर और अनेक गांवों में बहुत भारी तादाद में नाजायज कब्जे हैं और सरकार उन कब्जों को छुड़ा नहीं पा रही है और दान की हुई जमीन के 64000 मुकदमे चल रहे हैं। बेचारे गरीब तड़प रहे हैं। तुरंत प्रभाव से इस कानून को हटाने का काम किया जाना चाहिए और सरकार को बयान देना चाहिए कि जिसको जो जमीन दान में मिल गई है, सरकार उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, ग्रुप–डी की भर्ती हुई थी, उसमें बहुत से इम्पलाईज लगे थे और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जींद का बाई–इलेक्शन जीत गई थी। मेरा आग्रह है कि ये जो बच्चे लगे थे कोई हिसार जिले का है उसको मेवात में लगा दिया गया, कोई मेवात का है तो उसको अम्बाला में लगा दिया गया। इन बेचारों की बहुत छोटी सी नौकरी है और ज्यादा सेलरी भी नहीं है, अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनको इनके गृह जिले के आस पास ही पोस्टिंग दे दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की बात है, मैं समझता हूँ कि इसको तो तुरंत प्रभाव से ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह करप्शन का अड्डा बन चुका है। इस डिपार्टमैंट में एक विक्रम सिंह नाम का बहुत ही करप्ट डी. टी.पी. है जिसने जबरदस्त करप्शन किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जोकि छोटे–छोटे नौकर थे लेकिन उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के पदों पर बैठकर लूट मचाने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय बजट काफी घाटे में है और कर्जा भी हमारे ऊपर बे–हिसाब चढ़ा हुआ है। मैं तो यह कहता हूँ कि अगर सरकार करप्शन को कंट्रोल कर लेगी तो प्रदेश के लिये बहुत अच्छा हो जायेगा। मैं यह भी नहीं कहता कि इसी सरकार में करप्शन हुई है, करप्शन तो हर सरकार में

खूब हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि सरकार करप्शन पर कंट्रोल कर लेगी तो सारा घाटा खत्म हो जायेगा और कर्जा भी उतर जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि नये जिले बनाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे–ऐसे हल्के बना रखे हैं, जिसमें एक गांव के तीन–तीन टुकड़े हो रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुंडाय एक गांव है जिसमें दो पंचायते हैं। उसी गांव का दो हिस्सा भिवानी में आता है और एक हिस्सा हिसार में आता है। असल में जो हरियाणा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। परिसीमन में यदि इसको ठीक–ठाक कर दें तो इसका रिजल्ट ही कुछ और होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिसाय, डाटा, मसूदपुर, महैजत, सिंघारा आदि ऐसे कई गांव हैं जिनका कोई वास्ता मेरे से नहीं है क्योंकि वे नजदीक नहीं है। उनकी कोई एक भी यूनिट नारनौंद के साथ नहीं लगती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से तीन गांव खानपुर, सिंघड़ और गुराना है, इन गांवों की सीमा भी बरवाला के आस–पास लगती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को जल्दी से जल्दी लोगों की आवश्यकता को देखते हुए नये जिले बनाने का काम चाहिए और जितनी गड़बड़ी जिलों में हो चुकी है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हैवी रेन की वजह से किसानों की तैयार फसल खराब हो जाती है। हमारे यहां खेड़ी चौपटा गांव में कपास की फसल बिल्कुल नहीं हुई लेकिन सरकार ने अभी तक उसकी कोई गिरदावरी नहीं की जिसकी वजह से किसान दर–दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इस तरह से 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत नारनौंद के किसान भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तो यह कहता हूँ कि सरकार को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे सरकार को तुरंत इस बात का पता चल जाये कि फलां किसानों की फसल ओलावृष्टि या भारी बरसात के कारण खराब हुई है ताकि उसको मुआवजा भी उसी हिसाब से तुरंत मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, एस.सी. बैकलॉग में मुझे डी.एस.पी. का डाटा नहीं दिया गया है लेकिन हैड कांस्टेबल में 224, ए.एस.आई में 133 और सब–इन्सपैक्टर में 175 का बैकलॉग है। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही कहना है कि बी–1 टैस्ट में काफी गड़बड़ी होती है। इसमें जातिगत भेदभाव किया जाता है। मैं तो यह कहता हूँ कि जिस समय जिसने बी–1 का टैस्ट दिया था उनको उस लाईन में ही प्रमोट किया जाये। मेवात के लिये अलग से काडर बना दिया गया, यह सरकार का बहुत ही गलत फैसला था। मैं तो कहता हूँ कि मेवात से उनसे लिखित में एप्लीकेशंज

मांग लो और जो भाई मेवात में रूचि रखते हैं उनकी स्पेशल भर्ती मेवात में कर दो। अध्यक्ष महोदय, एक मैडम अर्चना शर्मा, साईंस की टीचर रोहतक जिले की थी, जिसकी दिनांक 11.09.2021 को कोरोना वैश्विक महामारी का नया स्वरूप ब्लैकफंग्ज की वजह से मौत हो गई। उसके घर वालों को 6 महीने हो गये हैं, अभी तक उसकी देय राशि वगैरह नहीं मिली और सरकार की तरफ से जो वित्तीय सहायता 5 लाख रुपये आदि दी जाती है वह भी नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सदन में उपस्थित नहीं है फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट मंत्री के पास 7 करोड़ रुपये, राज्य मंत्री के पास 5 करोड़ रुपये की स्वैच्छिक ग्रांट का कोटा होता है लेकिन एम. एल.ए. के पास कुछ भी नहीं है। (घंटी) एम.एल.ए. के लिये उसके ड्राईवर और पियन के लिये कम से कम 25–25 या 30–30 हजार रुपये प्रति महीना देने का प्रावधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एम.एल.एज. को अनेक स्टेट्स में डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जाती है । अतः हरियाणा में भी एम.एल.एज. को कम से कम 1 करोड़ रुपये डिस्क्रिशनरी ग्रांट अवश्य दी जानी चाहिए । (विघ्न)

15:00 बजे

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत जरूरी बातें कहनी रह गई हैं । मैं बजट की तारीफ करनी तो भूल ही गया । अध्यक्ष महोदय, इस बजट में सरकार ने बहुत–सी अच्छी बातें की हैं । इस सरकार ने ऐतिहासिक और बढ़िया काम भी खूब किये हैं । अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार के कामों में बहुत–सी कमियां भी हैं । मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं लेकिन आप घंटी बजा देते हो । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं । हाउस में बोलने का टाइम आपने ही तो देना है । आप 4 दिन का और हाउस बढ़ा दीजिए फिर चाहे मैम्बर अपनी बात 20–20 मिनट्स तक कहते रहें । इसमें क्या दिक्कत है ? बाकी स्टेट्स में भी मैम्बर्ज को बोलने का खूब समय मिलता है । अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत जरूरी बातें रह गई हैं ।

श्री बलराज कुण्डू (महम): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को देखा और जितना समझ आया उतना समझने का प्रयास किया । सरकार ने कुल 1 लाख 77 हजार 255 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है । इसमें 1 लाख 6 हजार करोड़ रुपये की आमदन है और 71 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है । इस प्रकार से

सरकार ने कुल 1 लाख 77 हजार 255 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है । मेरे विधायक बनने के बाद हाउस में प्रस्तुत किया गया यह तीसरा बजट है । इसमें हमें यह देखने को मिला कि बजट में हर साल लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का इजाफा हो रहा है । वित्त वर्ष 2022–23 के लिए जो बजट पेश किया गया है उसमें हमें अकेला इंट्रस्ट ही 20,900 करोड़ रुपये पे करना पड़ेगा । इसको घटाने के बाद कुल बजट लगभग 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपये बचता है । इसमें कैपिटल एक्सपैंडीचर जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, सड़कें आदि बनती हैं अर्थात डिवैल्पमैंट के लिए 77 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं । यह सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है । इस बचे हुए बजट में हर विधान सभा क्षेत्र के हिस्से में लगभग 880 करोड़ रुपये आते हैं । अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें से थोड़ा–बहुत बजट काट भी लें तो भी हर विधान सभा क्षेत्र के हिस्से में लगभग 800 करोड़ रुपये आते हैं । अतः मैं इस वित्त वर्ष के समाप्त होने पर सरकार से पूछूंगा कि उन्होंने हर विधान सभा क्षेत्र को कितना बजट दिया और मेरे विधान सभा क्षेत्र को कितना बजट दिया गया है यह भी मैं बताऊँगा । अध्यक्ष महोदय, अब मैं बताना चाहूंगा कि युवाओं के सामने बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है । इस विषय पर सरकार में बैठे लोगों ने अपनी पार्टी के मैनिफैस्टों में बड़े–बड़े वायदे किये थे कि हम प्राइवेट कम्पनियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 परसैंट आरक्षण की सुविधा देंगे । आज हम कार, मोटरसाइकिल, रैफ्रिजरेटर आदि के निर्माण में 70 परसैंट से ज्यादा हिस्सा हरियाणा के उद्योगों का है । आज मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कितनी कुशलता के साथ उद्योगों के विकास के लिए बजट में मात्र 598 करोड़ रुपये का प्रावधान करवाया है । आज मुझे बड़ी हैरानी है । मैं तो कहूंगा कि हमारे पड़ोसी राज्यों को हमारे प्रदेश से सीख लेनी चाहिए कि जहां वे अपने उद्योगों की डिवैल्पमैंट के लिए हजारो करोड़ रुपये लगाते हैं वहीं हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री जी केवल 598 करोड़ रुपये में ही अपने उद्योग जगत की डिवैल्पमैंट कर लेते हैं । अध्यक्ष महोदय, सरकार के सहयोगी लोगों ने अपने मैनिफैस्टो में बुजुर्गों की पैंशन को बढ़ाकर 5100 रुपये करने का वायदा किया था और जनता ने उनकी बड़ी–बड़ी बातों को सुनकर उनको सरकार में बैठाने का काम किया । आज उन बुजुर्गों की पैंशन कटती जा रही है । इस बजट में उनकी पैंशन को बढ़ाने का

कोई प्रावधान नहीं किया गया है । मुझे इस बजट में बुजुर्गों की पैंशन को 5100 रुपये करने का प्रावधान कहीं नजर नहीं आया । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात को कहना चाहता हूं लेकिन उस बात को अदरवाइज मत लेना । आज ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए मेरे पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर बैठे हुए हैं । हमें उनके लिए कोई चिन्ता नहीं है । हम केवल एक दिन के लिए एम. एल.ए. बनकर शपथ लेने पर भी पैंशन के हकदार हो जाते हैं । हमें 60–60 हजार रुपये तो पैंशन के मिलते हैं और अगर दोबारा से एम.एल.ए. बनते हैं तो तनख्वाह भी लेते हैं और पैंशन भी लेते हैं। इस प्रकार अगर कोई 4 या 5 बार विधायक बन जाता है तो वह उतनी ही तनख्वाह और पैंशन लेता है।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, इनमें से प्रजैंट माननीय सदस्य को एक ही चीज मिलती है। चाहे वह तनख्वाह ले या पैंशन ले।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वे 30–35 सालों तक अपनी जिंदगी को देकर सरकार की नीतियों को लागू करते हैं और प्रदेश के लिए काम करते हैं लेकिन उनकी ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करने की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। यह बड़े दुख की बात है कि इस बजट में ओल्ड पैंशन स्कीम का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के हरेक विभाग में 10–15 सालों से जो कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं वे पक्का होने के इन्तजार में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह बात बड़ी दुभाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है जिससे समाज के लोगों को ऊपर उठाया जाता है।

श्री बिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि सभी माननीय सदस्यगण पैंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं। शायद, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है क्योंकि ये पहली बार माननीय सदस्य चुनकर आये हैं। जब कोई माननीय विधायक दोबारा से विधायक बन जाता है और उसको तनख्वाह मिलने लग जाती है तो ऑटोमैटिक उसकी पैंशन बन्द हो जाती है। इस प्रकार दोनों में से एक ही चीज मिलती है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, जब किसी माननीय विधायक का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वह जितनी बार विधायक बना होता है उसको उतनी ही पैंशन मिलती हैं।

श्री बिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के कई माननीय विधायकगण 2 लाख, 2.50 लाख और 3 लाख रुपये तक पैंशन के तौर पर ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की पैंशन बन्द करवाने की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो ओल्ड पैंशन स्कीम लागू करवाने की बात कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करवाना है। मैं तो इस बात से माननीय सदस्यों की आत्मा को जगाना चाहता हूं कि हम सबका फर्ज बनता है कि ओल्ड पैंशन स्कीम के लिए आवाज उठाएं और उसको लागू करवायें। पंजाब की सरकार ने भी इस ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी है। (इस समय घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बोलते हुए सिर्फ 6 मिनट का ही समय हुआ है। शिक्षा विभाग में 38,000 पद खाली हैं और जब तक इनको भरा नहीं जाएगा तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। माननीय मंत्री जी ने उसका लेखा–जोखा दिया है। इसी तरह से दूसरे विभागों में भी बहुत से पद खाली हैं जिनको भरने का सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है और न ही उनको बजट में लिया गया है। अध्यक्ष जी, बजट को पढ़ने और सभी तथ्यों को देखें तो पता चलेगा कि इसमें इतनी लच्छेदार बातें हैं कि जैसे इससे पूरे प्रदेश का कल्याण हो जाएगा। इसमें भी कोई दोराय नहीं है। इस बजट में लच्छेदार, विकास और उत्थान की बातें की गयी हैं और उनको पढ़ते हुए मन गद्गद हो जाता है लेकिन पिछले बजट की बात करें तो उसमें घोषणा हुई थी कि गुरूग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी बनाएंगे। इस पर हमारे प्रदेश के बच्चे भी सपने देखने लग गये थे कि वे भी हीरो बनेंगे लेकिन ये बातें भी हवा– हवाई साबित हुई और कहीं कुछ नजर नहीं आया। इसके अतिरिक्त सोहना में आई.एम.टी. बनाने की बात थी और हर डिस्ट्रिक्ट में मैडिकल कॉलेज बनवाने की बात थी। आठवीं और बाहरवीं के बच्चों को टैबलेट देने की बात थी और वे बच्चे बहुत खुश हो गये थे कि उनको सरकार की तरफ से टैबलेट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी और इस बात को सुनकर किसान बड़ा उत्साहित था। गरीब व्यक्ति को मकान देने की बात थी, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस

बजट के अन्दर सारी बातें हवा– हवाई होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त जो यमुना पार कराने की बातें थी उनमें भी कुछ नहीं है, परन्तु बॉर्डर पर ताऊ देवी लाल जी का पुतला जरूर लग गया कि आपकी जरूरत प्रदेश में नही है बल्कि यहां पर है और अब आप यहां पर विश्राम करें। यह बात जरूर देखने को मिली है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट रह गया है। गेहूं की फसल की प्रोक्योरमैंट अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगी। मेरी जानकारी में आया है कि एफ.सी.आई. के गोदामों में अभी तक बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने प्रोक्योरमैंट की क्या प्लानिंग कर रखी है यह मेरी समझ से बाहर है? चूंकि आने वाले समय में उस गेहूं को कहां पर रखा जाएगा? मेरे पास इसके बारे में एक शिकायत है कि वहां पर बहुत सारा गेहूं खराब हो चुका है और वह काला हो गया है। मेरे पास कल ही इस संबंध में फोन आया था। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। चूंकि नये गेहूं की प्रोक्योरमैंट शुरू होने वाली है और पुराना गेहूं एफ.सी.आई. के गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है। इसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रोक्योरमैंट की बात की है तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जहां तक एफ.सी.आई. की बात है, माननीय सदस्य को इस सदन में आये हुए दो–अढाई साल से ज्यादा का समय हो गया है। फूड कोरपोरेशन गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। उनके गोदाम में अनाज पड़ा है, वह उसको आगे कैसे मूव करेंगे। यह प्रदेश सरकार का काम नहीं है। हमारी सरकार का काम अनाज को प्रोक्योरमैंट करके 4 एजेंसीज के माध्यम से पर्याप्त स्टोरेज के अंदर पहुंचाने का होता है। माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त हो जायें, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले 50–50 लाख मीट्रिक टन खुले में अनाज पड़ा रहता था लेकिन इस बार हमने टारगेट फिक्स किया है कि 20 लाख से भी कम मीट्रिक टन अनाज को कहीं ओपन स्टोरेज में ले जाना पड़ा तो ले जायेंगे अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनाज की खरीद की प्रक्रिया खत्म होते ही हमारी

जो मंडियों हैं, वहां से हम अनाज को व्यवस्थित ढंग से स्टोरेज करने का काम करेंगे जिससे वह अनाज गलेगा भी नहीं और सड़ेगा भी नहीं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि एफ.आई.एफ.ओ. (First in First out) के आधार पर यह व्यवस्था की जाये। माननीय सदस्य भी व्यापार करते है इसलिए इनको भी इस बारे में अच्छी तरह पता है। पहले हमारे यहां 5–5 साल का अनाज पड़ा रहता था। अब एक साल से ज्यादा पुराना अनाज स्टेट गवर्नमैंट के किसी भंडारण में नहीं होगा। अब हम इस साल यह प्रयास कर रहे हैं कि 365 दिन से पुराना गेहूं किसी भी सरकारी गोदाम में न पड़ा रहे। हमारी सरकार एफ.आई.एफ.ओ. के माध्यम से कम्प्युटराइजेशन से मॉनिटरिंग करने का काम भी जल्द शुरू करेगी।

श्री सत्य प्रकाश जरावता (पटौदी) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया मैं इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है। इस बजट का मैं समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा बजट है जिसकी जितनी सराहना की जाये उतनी कम होगी। जब विपक्ष के लोग यह बात कहते हैं कि यह बजट पेश किया है जिस तरह से कोई चुनाव के समय में किया जाता है यह इस प्रकार का लोक लुभावना बजट है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज न कोई चुनाव है और न ही ऐसी कोई और बात है लेकिन हमारी सरकार ने फिर भी इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं इस बजट में दी हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां इसमें वैल्फेयर स्टेट के कंसेप्ट को पूरी तरह असैप्ट करते हुए गरीब कल्याण के लिए काम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बजट में इंकम बढ़ाने के उपाय भी दिये गये हैं। इस बजट के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। रोजगार के रास्ते खोल रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्व घाटे को कम करने का प्रस्ताव भी इस बजट के माध्यम से दिया गया है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक स्थिति मजबूत हो इसीलिए पूंजीगत व्यय का प्रतिशत बजट में बढ़ाया गया है। एक तरफ जहां लोकल सैल्फ गवर्नमैंट के आर्गेनाइजेशन पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडी की पावर को डेलीगेट करके उनको और सशक्त व मजबूत बनकार ज्यादा फाइनैंशियल पावर्ज दी गई हैं। वहीं 60:40 के अनुपात में लोकल गवर्नमैंट के तहत नगरपालिकाओं के अंदर पार्क और लाईब्रेरी के लिए काम करने के लिए फंड का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं और हमारी बच्चियों के लिए पहले हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज और थाने उपलब्ध करवाये

हैं। इसी प्रकार से 50 हजार महिलाओं के लिए 10 हजार सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। जिनको बैंक से लिंक किया जायेगा और इससे स्वयं सहायता ग्रुप्स अपना प्रोडक्शन करके रोजगार के साधन प्राप्त कर सके। इस तरह का यह एक बड़ा लक्ष्य रखा गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं और दो कदम आगे बढ़कर पंचकुला फरीदाबाद और गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि हमारी सरकार द्वारा मातृ शक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार औद्योगिक मजदूरों के लिए ई.एस.आई. डिस्पैंसरी और अस्पताल का प्रावधान किया है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र पटौदी में एक ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के वे गरीब जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है अगर वे अपने पशु पालन, भेड़ बकरी पालन या गाय पालने का कोई काम करना चाहें तो पंचायतों की जमीनें पट्टे पर देकर बाड़ा या शैड बनाने का जो निर्णय लिया गया है, निश्चित तौर पर जो भूमिहीन मजदूर हैं और जो एग्रीकल्चर पर डिपैंड हैं या जो लैंडलैस हैं उनको अपनी इन्कम बढ़ाने का माध्यम इसके मार्फत मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आई.टी. हब गुरूग्राम में इंस्टीच्यूट ऑफ अमरजिंग टैक्नोलोजी का एक बड़ा इंस्टीच्यूट जो आई. टी. का खोलने का निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं । गुरूग्राम के नैशनल हाइवे नं. 8 पर के.एम.पी. एक्सप्रैस वे के नजदीक एक बड़ा बसपोर्ट आर.आर.टी.एस. रेल, ओरबिटल रेल तमाम के.एम.पी. एक्सप्रैस वे को कनैक्ट करते हुए बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे हमारे दिल्ली और गुरूग्राम के व्यापार के अवसर बढ़ेंगे लेकिन इसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बाहर बाहर जो बसों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी वह एक सुगम व्यवस्था परिवहन की उपलब्ध हो जाएगी । आज गुरूग्राम के क्षेत्र में और पंचकूला में एक कर्मचारी और एक मेरे जैसा व्यक्ति 200 गज का प्लाट नहीं ले सकता, एफोर्डेबल में भी नहीं ले सकता लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर 75 एच.एस.वी.पी. के खण्ड डिवैल्प करके 40 हजार प्लाट देने और बनाने का निर्णय लिया है उससे निश्चित तौर पर आम लोगों को

किफायती दर पर रहने का अवसर प्राप्त होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे के.एम.पी. एक्सप्रैस वे के आस पास एक इंटरनैशनल स्तर का स्टेडियम बनाया जाए क्योंकि एयरपोर्ट भी वहां पर नजदीक पड़ता है और वहां पर बहुत सुचारू ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी है इसलिए वहां पर एक बेहतरीन इंटरनैशनल स्तर का एक स्टेडियम बनाया जाए । एडहॉक कमेटी नं. 7 में डिमांड नं. 25 पर जो रिकमैंडेशन नं. 1 और 2 है । वे इस प्रकार हैं:

1. The Committee desired that the provision for allocation of Budget to promote/encourage th new entrepreneurs of SC category in the State should be made.
2. The Committee desired that the freight subsidy given at present to new industries only should be given to both new and old industries in State."

निश्चित तौर पर शिडयूल्ड कास्ट के लिए मैंने पीछे प्रश्न भी लगाया था, उस समय इतेफाक से मेरे प्रश्न का नम्बर नहीं आया था। पूरे हरियाणा के अंदर 90 लाख एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है । उसमें से मात्र एक लाख एकड़ शिडयूल्ड कास्ट के पास है यानि कि एक प्रतिशत । अध्यक्ष महोदय, उद्योग नहीं हैं, खेती नहीं है, रोजगार नहीं हैं इसलिए कमेटी नं. 7 में जो रिकमैंडेशन दी गई है कि एस.सी. इंटरप्रिन्योर को चाहे पदमा स्कीम में चाहे एम.एम.एम.ई. में प्रमोट किया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि यह ठीक है कि बजट में शिडयूल्ड कास्ट के नाम का अलग से उल्लेख नहीं हुआ लेकिन 355 करोड़ रूपये शिडयूल्ड कास्ट के बजट में बढ़ाए गए हैं । पिछली बार 525 करोड़ 51 लाख 40 हजार थे और इस बार 890 करोड़ 52 लाख 54 हजार रूपये हैं । एक बहुत बड़ी राशि शिडयूल्ड कास्ट के लिए बजट में बढ़ाई गई है । मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय वित मंत्री महोदय के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लेकिन इसके साथ मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि शिडयूल्ड कास्ट का जो पैसा है यानि जो रिजर्व फंड है वह शिडयूल्ड कास्ट की वैल्फेयर एक्टीविटीज पर ही खर्च हो तथा उसका यूटीलाइजेशन किसी और एक्टीविटीज पर न हो । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शीश पाल सिंह (कालांवाली)(अ.जा.) : स्पीकर सर, सत्ता पक्ष की तरफ से एक आवाज आई थी मैं सबसे पहले उसी को पूरा करना चाहता हूं कि –

बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था।

हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम–ए–गुलिस्तां क्या होगा।।

श्री अध्यक्ष : शीश पाल जी, ये आप किसके बारे में और क्या कह रहे हैं?

श्री शीश पाल सिंह : स्पीकर सर, यह शेर श्री महीपाल ढांडा जी ने आधा बोला था इसलिए मैंने इसे पूरा किया है। (विघ्न) अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा यह सरकार हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने पर इतराती है। सरकार हर बात पर भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात करती है। अगर हम धरातल पर जाकर देखें तो हर डिपार्टमैंट में होड़ लगी हुई है कि हमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करना है। आज अगर ईमानदारी को ढूंढने लगें तो वर्तमान सरकार के शासनकाल में ईमानदारी कहीं मिलेगी ही नहीं और सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात करते हैं। अगर मैं इस बजट पर बात करूं तो जो वर्ष 2021 में बजट पेश हुआ था उसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकतायें दी थी। यही प्राथमिकतायें इस बार के बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने दी हैं। मैं अपनी बात कृषि से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। हमने इतिहास भी पढ़ा। यह हो सकता है कि हमारे देश को गजनवी ने बहुत लूटा और उसके बाद ब्रिटिश शासकों ने बहुत लूटा परन्तु अगर आजाद भारत की बात करें तो सबसे बड़ी लूट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुई है। यह मैं सरकार को बताना चाहूंगा। मैं आंकड़ों के साथ यह बताना चाहूंगा कि यह कितनी बड़ी लूट है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से दिसम्बर, 2020 तक 1,26,521 करोड़ रूपये का प्रीमियम किसानों से लिया गया और 87,320 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान मुआवजे के तौर पर किसानों को किया गया। इस प्रकार से 31 प्रतिशत राशि बीमा कम्पनियों की जेब में चली गई। इस प्रकार कम से कम 40 हजार करोड़ रूपये हमारे किसानों का बीमा कम्पनियों को देने का काम किया गया। यह वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसका गुणगान करते हुए सरकार कभी नहीं थकती। (विघ्न)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भारत सरकार की बात कर रहे हैं। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है। अगर किसान अपनी

इच्छा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है तो इसको किसी भी प्रकार से लूट नहीं कहा जा सकता। हमारी सरकार ने इसको मैनडैटरी नहीं बनाया है। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जितना पैसा किसानों से प्रीमियम के तौर पर लिया गया है उससे ज्यादा पैसा मुआवजे के तौर पर किसानों को दिया गया है। (विघ्न) हरियाणा में किसान अपनी इच्छा से प्रीमियम का भुगतान करते हैं। किसी भी किसान से जबरदस्ती प्रीमियम नहीं लिया जाता। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि इस प्रीमियम को किसी भी दृष्टि से लूट नहीं कहा जा सकता। हरियाणा प्रदेश का किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल का बीमा करवाता है। इस योजना से किसान को फायदा ही हुआ है। (विघ्न)

श्री शीश पाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं वह रिपोर्ट मेरी नहीं है बल्कि वह कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट है। सरकार के स्तर पर यह कहा जा रहा है कि किसान अपनी इच्छा से बीमा करवा रहा है लेकिन मेरा यह कहना है कि बीमा प्रीमियम की राशि सीधे किसान के खाते से कटवाने का कार्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसकी एडवरटाईजमैंट कौन कर रहा है? (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष जी, लूट तो इनकी पार्टी की सरकार के समय में होती थी जब ये किसान की जमीन को जबरदस्ती एक्वॉयर करवाते थे। मेरा बार–बार यही कहना है कि फसल बीमा का प्रीमियम किसान की मर्जी से ही जमा होता है और बिना किसान की मर्जी के फसल बीमा का प्रीमियम नहीं लिया जाता। (विघ्न) इस प्रकार से यह किसी भी दृष्टि से लूट नहीं है। (विघ्न)

श्री शीश पाल सिंह : अध्यक्ष जी, जब प्रदेश का किसान 13 महीने बाद दिल्ली के बार्डर से थक हार कर अपने घर आया तो उसने यह सोचा कि उसके लिए कुछ अच्छा होगा। उसको डी.ए.पी. और यूरिया खाद के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, श्री जय प्रकाश जी एक मंत्री हैं और ये एक बहुत ही जिम्मेवार पद पर बैठे हैं। श्री शीश पाल जी एक विधायक हैं। एक मंत्री ने हमारी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि हमारी सरकार के समय में किसानों की जमीन लूटी गई है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा था कि यह लूट नहीं है। जैसा हुड्डा जी कह रहे हैं वह मैंने नहीं कहा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा में हमारी सरकार के समय में किसी एक भी किसान की जमीन एक्वॉयर करके किसी प्राईवेट आदमी को दी हो तो ये साबित कर दें। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मेरा बार–बार यही कहना है कि हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है। (विघ्न) सरकार इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करती है। अगर इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है तो फिर यह सरकारी स्तर पर लूट कैसे हो गई? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, ऐसे हाउस नहीं चलेगा। (विघ्न) हम आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। (विघ्न) मंत्री जी को सभी बातों को नोट कर लेना चाहिए और बाद में जवाब देना चाहिए। (विघ्न) किसी भी माननीय सदस्य को यहां पर अपनी बात कहने का पूरा हक है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, "लूट" शब्द गलत है इसलिए माननीय सदस्य को इस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। (विघ्न)

पण्डित मूल चंद शर्मा : स्पीकर सर, "लूट" शब्द को सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप कृपया करके शांत बैठ जायें और श्री शीश पाल जी को अपनी बात कहने दें। शीश पाल जी आप बोलिए।

श्री शीश पाल सिंह : स्पीकर सर, सरकार कह रही है कि उसने इस बजट के अंदर पूरे प्रदेश के सभी वर्गों के विकास की बात की है। मेरा यह कहना है कि इस बजट में वंचित समाज के हित के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जब कोई भी बजट पेश किया जाता है तो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति पर मुख्य तौर से फोक्स रखा जाता है। इस बजट में एक बार भी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और माईनोरिटी को सुविधा देने की बात नहीं लिखी गई है। बजट भाषण में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाये गये बजट का जिक्र किया गया है। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में विभिन्न वर्गों के 38,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार के स्तर पर यह ब्यान दिया जा रहा है कि सरकार ने प्रदेश में आरोही स्कूलों को बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि झीड़ी गांव में आरोही स्कूल की स्थापना की गई है। उसमें कक्षा 5 सें लेकर कक्षा 8 तक एक भी अध्यापक नहीं है। इसी प्रकार से कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक विभिन्न विषयों के 9 अध्यापकों की कमी है। सरकार द्वारा

शिक्षा विभाग का बजट तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन शिक्षकों को नहीं बढ़ाया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक्सटैंशन लैक्चरार, पी.टी.आई. और जे.बी.टी. धरने पर बैठे हैं। सरकार का नई भर्ती की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि हम हरियाणा को शिक्षित करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर स्वास्थ्य की बात की जाये तो प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य के मामले में कोरोना काल में पहले ही जुलूस निकल चुका है। कारोना काल के अंदर सरकार किस प्रकार से नाकाम रही है यह हम सभी के सामने है।

श्री अध्यक्ष : शीश पाल जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है इसलिए अब आप बैठ जायें। (विघ्न)

श्री शीश पाल सिंह : स्पीकर सर, यहां पर सुशासन की भी बात की गई। यहां पर महिला दिवस पर बजट पेश करने की बात की गई। इस पर पूरे प्रदेश की महिलाओं ने सोचा कि बजट में उनको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा लेकिन बजट में प्रदेश की महिलाओं को कुछ नहीं मिला। हमारी सरकार के समय में महिलाओं के नाम होने वाली रजिस्ट्रियों में लगने वाले टैक्स को 7 परसैंट से घटाकर 5 परसैंट किया गया था। इसी प्रकार से हमारी सरकार के समय में रक्षा बंधन के अवसर पर महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का काम किया गया था। वर्तमान सरकार के वर्ष 2022 के बजट में महिलाओं को और विशेषकर अंतिम पंक्ति में बैठी अंतिम महिला को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। अर्थात् जो महिला आखिरी पंक्ति में बैठी है उसको एक भी सुविधा इस बजट के माध्यम से प्रदान नहीं की गई है। बजट में कहा गया है कि कुछ महिलाएं जो अग्रिम पंक्ति में आ कर उद्यमिता के क्षेत्र में काम करेंगी उनको सरकार प्रोत्साहन देगी लेकिन जो आम महिला है उसको सरकार ने बजट के माध्यम से क्या दिया है?

श्री अध्यक्षः शीश पाल जी, आपका समय समाप्त हो रहा है इसलिए आप जल्दी से वाईंड–अप कीजिए।

श्री शीश पाल सिंहः सर, मैं जल्दी ही अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से इस महान सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि 30 नवम्बर, 2021 तक का डाटा मेरे पास है और उसके तहत हरियाणा में 1666 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। इस प्रकार से एक दिन में 5 बलात्कार की औसत है तथा सरकार बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ का नारा दे रही है। इसी

प्रकार से अगर मैं अपहरण की घटनाओं की बात करूं तो 30 नवम्बर, 2021 तक हरियाणा प्रदेश में 2970 अपहरण हुए हैं जबकि दूसरी तरफ सरकार सुशासन की बात कर रही है। अब मैं कर्मचारियों की ओल्ड पैन्शन स्कीम के बारे में बात करना चाहूंगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित प्रदेशों में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पैन्शन स्कीम बहाल की गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ओल्ड पैन्शन स्कीम लागू करके कर्मचारियों को रिटायरमैंट के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती निर्मल रानी(गन्नौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। कोविड 19 के बाद यह बजट बहुत गति देने वाला है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन डॉक्यूमैंट है। हरियाणा के विकास के वज्र मॉडल की दूसरी शक्ति सबसे गरीब वर्ग का आर्थिक उत्थान है। मुख्यमंत्री जी की अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से गरीबों के चेहरे खिले हैं। पी.पी.पी. के सत्यापन से अब आयुष्मान भारत के लिए लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख की पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया है। हरियाणा मातृत्व उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत जिस परिवार की वार्षिक आय 5.00 लाख से कम है उस परिवार की महिला यदि उद्यमी बनना चाहती है तो उसे 3 लाख रुपये तक के आसान ऋण दिये जायेंगे। हमारी सरकार ने शिक्षा पर 17.6 प्रतिशत बजट बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शैक्षणिक सुविधायें बढ़ाते हुए 3 नये महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है जिनमें से एक कॉलेज गन्नौर में भी खोला जायेगा। इसके लिए मैं पूरे गन्नौर की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। सोनीपत जिला 22 दिसम्बर, 1972 में अस्तित्व में आया था। गन्नौर सब–डिविजन 19 फरवरी, 1980 में बना और उसकी बिल्डिंग 1991 में बनी। यह 11 वर्ष का अन्तर यह बताता है कि हमारे काम की गति क्या थी? पर्यावरण पर हमारे बजट में 16.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को बढ़ावा देते हुए हरियाणा के प्रख्यात पर्यावरणविद स्व. श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर एक नये पुरस्कार की घोषणा की गई है जिसमें 2 व्यक्तियों को क्रमशः 3 लाख और 1 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी

जायेगी। इसी प्रकार से महिला एवं बाल विकास के बजट में 33.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार से डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र स्कॉलरशिप स्कीम की राशि 8 हजार रुपये से बढ़ा कर 12 हजार रुपये सालाना की गई है। अगर लोक निर्माण विभाग के बजट की बात की जाये तो इसमें 59.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी गई है। बजट में हर क्षेत्र के लिए चाहे वह किसान हो, गरीब हो कोई भी हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के इस पावन मंदिर में बहुत संघर्ष के बाद पहली बार चुनकर पहुंची हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार चुन कर आये तो इनकी विचारधारा सुन कर यह लगता था कि यह कैसे सम्भव हो पायेगा क्योंकि इन्होंने स्वयं के लिए इतना कठिन सिलेबस तय किया था। यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्या योग्यता के आधार पर नौकरियां दे पाना सम्भव हो पायेगा लेकिन यह सम्भव हुआ। उस समय विपक्ष चुटकियां लेता था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ–सबका विकास के माध्यम से यह सब काम कर दिखाया। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि–

आदमी वह नहीं जिसे हालात बदल दें,
आदमी वह है जो हालात को बदल दे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदा सबका मनोबल बढ़ाया है। आप ऐसी परम्पराएं लाये हैं कि आपने एक दिन महिला दिवस पर हम बहनों से सदन की कार्यवाही भी चलवाई थी। अब आपने बैस्ट लैजिसलेटर अवार्ड की परम्परा भी चलाई है। इस अवार्ड की जो परम्परा है उसका चयन एक पूरी की पूरी समिति करती है। आपने हमारा जो चयन किया है और जिसमें आपने हम सब बहन–भाईयों को ये मौका दिया है जिसमें आपने मुझे भी मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं लेकिन इसके लिए भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो पहले इसी जगह पर बहुत अच्छे पद पर बैठकर गये हैं और जो हमारी ही विधान सभा से आते हैं। वे भी इतनी गलत बात करते हैं। मेरे पास उनकी स्पीच है जो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने अभी गन्नौर में मीटिंग करके यह कहा है कि यह चयन इस आधार पर किया जाता है कि जो एम.एल.ए. न तो अपने हल्के की बात उठाए, न कोई काम मांगे, न सी.एम. साहब से कोई काम करवाए और जो सरकार का एक पैसा भी खर्च न कराए। ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मैंने स्पीकर साहब व मुख्यमंत्री जी से फोन करके पूछा कि क्या यह चयन इसी आधार पर किया जाता है? ऐसे लोगों को यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए। अच्छे काम करने

वालों के लिए कम से कम तारीफ तो कर देनी चाहिए कि माननीय स्पीकर महोदय आज बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। यह पुरस्कार तो मेरे विपक्ष के भाईयों को भी दिया गया है। जब वह इस पद पर रहते हुए खुद ऐसी परम्परा नहीं ला पाए तो उन्हें ऐसी बात कहने से पहले सौ बार सोचना चाहिए। इस प्रकार से किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। माननीय स्पीकर महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसे ही द्रौपदी के एक बोल थे कि अंधे के अंधे, जिसने महाभारत करवा दी थी। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो तीन उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है कि छाज तो बोले सो बोले लेकिन यहां पर छलनियां भी बोलती हैं जिनमें सौ–सौ छेद होते हैं। उस समय की प्रोसिडिंग्ज निकलवाकर देख ली जाए। मेरे से पहले माननीय सदस्य 10–10 साल तक एम.एल.ए. रह कर गये हैं। गन्नौर में गवर्नमैंट कॉलेज पहले तो कभी नहीं आया। उनके समय में गन्नौर में बाई पास नहीं बन पाया और हमारी जो इंटर नेशनल फूड एण्ड वैजिटेबल एग्रीकल्चर मार्किट बनी है यह पहले तो नहीं बनी। गन्नौर में पहले रेल कोच फैक्ट्री नहीं बनी। ये सभी चीजें पहले तो नहीं आ पाई। ट्रॉमा सैंटर व बाई पास आदि चीजें पहले तो नहीं बन पाई। ये सारी चीजें हमारी सरकार लेकर आई है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, गन्नौर में इंटरनेशनल फूड एण्ड वैजिटेबल एग्रीकल्चर मार्किट बहुत पहले से बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, वह केवल कागजों में बनी हुई थी। वह प्रपोज्ड थी।

श्रीमती निर्मल रानी : अध्यक्ष महोदय, उस पर काम अब शुरू हुआ है। हम हर रोज वहीं रहते है। उसमें पहले काम शुरू नहीं हुआ था। उसमें काम अब शुरू हुआ है। आप चाहे वहां जाकर चैक कर लें। मैं तो यह कहती हूं कि सोनीपत के साथ सदैव ही धोखा हुआ है। 10 साल तक हमेशा यह कहा जाता था कि रोहतक का छोटा भाई सोनीपत है और रोहतक की एक आंख सोनीपत है। जब पार्लियामैंट का चुनाव था उस समय जो वहां से कैंडीडेट थे और जो अब माननीय सांसद हैं उनसे पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या एक आंख रोहतक है और एक आंख सोनीपत है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम एक आंख का क्या करोगे जब मैं दोनों आंखों वाला आपके पास खड़ा हूं तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारी एक आंख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उस एक आंख का अब इलाज हुआ है। अब धीरे–धीरे वह

धुंधलापन खत्म होता जा रहा है। जब बिमारी बहुत लम्बी है तो उसके इलाज में समय तो लगेगा। अध्यक्ष महोदय, धीरे–धीरे इलाज होगा और धीरे–धीरे ये सभी चीजें समझ में आएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी के मनोहर कार्यों से सोनीपत की उस एक आंख का इलाज हो चुका है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि मेरी कुछ मांगे हैं। हमारे गन्नौर में एक सत्कुंभा धाम है जो कि सत्युग के राजा चक्वाबेन की राजधानी है और वहां से कभी यमुना निकलती थी। उस सत्कुंभा धाम को कृष्णा सर्किट योजना के साथ जोड़ा जाए। हमारे गन्नौर में जहां रेल कोच फैक्ट्री और इंटर नेशनल फूड एण्ड वैजिटेबल एग्रीकल्चर मार्किट आई है उसके साथ ही बड़ी गांव में पंचायती लैंड खाली पड़ी हुई है। वहां पर अगर एक ट्रॉमा सैंटर और बना दिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत–बहुत मेहरबानी होगी। देखिये कुंए में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वह भरकर ही आएगी। जीवन में यदि किसी का भला करोगे तो लाभ मिलेगा क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है और यदि किसी पर दया करोगे तो वह आपको याद करेगा क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने अन्त्योद्य स्कीम के तहत जो व्यक्ति अन्तिम लाईन में खड़ा है उसको आगे लाने का काम किया है। यहां जिसको जो भी मिला है वह अपने–अपने कर्मों का फल है। कहते हैं कि भगवान न किसी की बनाता है और न किसी की बिगाड़ता है। सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ख्याति उनके अच्छे कर्मों का फल है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।

श्री राम करण (शाहबाद) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तथा उप–मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही बहुत से अच्छे कार्य करवाये हैं लेकिन इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे यहां गांव चढ़ूनी में लड़कियों का कालेज खुल जाये तो यहां के 50–60 गावों के बच्चों को बहुत फायदा होगा क्योंकि हमारे यहां की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर–दूर तक जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यदि बिजली मंत्री जी, बिजली के बिलों में थोड़ी सी छूट देने का काम कर दें तो इससे जमीनदार, फैक्ट्री वालों और आम उपभोक्ताओं अर्थात सभी 36 बिरादरी के लोगों को बहुत फायदा होगा। इस बारे में

मेरा मुख्यमंत्री महोदय, उप–मुख्यमंत्री महोदय तथा बिजली मंत्री से अनुरोध है कि बिजली का बिल कम करने का काम किया जाये। अब मैं हमारे डिवेलपमैंट एंड पंचायत मिनिस्टर जी से अनुरोध करना चाहूंगा जोकि अभी सदन में नहीं बैठे हुए हैं कि जिस प्रकार यह प्रावधान किया गया है कि दो लाख रूपये तक के टैंडर का अख्तियार बी.डी.ओ. के पास है, मैं समझता हूँ कि यह लिमिट दस लाख रूपये तक की होनी चाहिए क्योंकि दो लाख रूपये में क्या काम होंगे। दो लाख रूपये में तो चार हजार ईंटें भी नहीं आती हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इस दो लाख की लिमिट की बढ़ाकर दस लाख रूपये तक के टैंडर की पावर बी.डी.ओ. के पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे तो सारे काम ही रूके रह जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो गरीब आदमी है, मजदूर हैं या किसान हैं या झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इन सबको प्लॉट मिल गए है लेकिन जो सिकलीगर हैं, बाजीगर हैं, बागड़ी लोहार हैं या किसी अन्य जाति के है, वे लोग पिछले 50–60 साल से झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी तो प्लॉट मिलने चाहिए। यह लोग सड़कों पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे शाहबाद में एक बाजीगर कालोनी है। ये लोग जिस जगह पर पिछले 70 साल से बैठे हुए है, उस जमीन को रेलवे की जमीन माना जाता है। सरकार ने यहां पर स्कूल भी देने का काम किया है, यहां पर गलियां भी बनाने का काम किया गया है और सरकार की तरफ से मकान भी बनाकर देने का काम किया गया है। अब इन लोगों को इस जमीन से उठाने की बात कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह रेलवे की जगह नहीं है। यह जगह हमारे हरियाणा प्रदेश की जगह है। अतः हरियाणा सरकार की तरफ से इनको या तो मुआवजे के रूप में पैसे देने का काम किया जाना चाहिए या वे जहां बैठे हैं, उनको वहीं पर बैठे रहने दिया जाये। इन लोगों के बैठे रहने से रेलवे को कोई दिक्कत भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस जगह का रेलवे मंत्रालय की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई को मकान बनाने में लगा रखा है ऐसी हालत में ये लोग बेचारे कहां जायेंगे। इस बारे में सरकार को सोचने की जरूरत है। इन लोगों ने जो अपने जीवन भर की कमाई अपने घरों पर लगाने का काम किया है, इतना पैसा तो मुआवजे के रूप में सरकार भी नहीं दे सकती। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि इन लोगों को बसाने के लिए सैंटर गवर्नमैंट की तरफ से हमारी स्टेट गवर्नमैंट को पैसा दिया जाये और अगर किसी के पास 2–4 किल्ले जमीन भी है तो भी इन लोगों को राहत देने का काम

सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। मेरी अपील है कि जो ये लोग पिछले 50–60 साल से इस जमीन पर बैठे हुए हैं, अगर इनको उजाड़ा गया तो गलत बात होगी। अतः सदन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों को उजड़ने से बचाया जाये। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी आई थी कि मार्किटिंग बोर्ड की सड़कों को बनाने का जिम्मा जिला परिषद को दिया जायेगा, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि सड़कों को बनाने की जो स्ट्रैंथ मार्किट बोर्ड के पास है, वैसी स्ट्रैंथ जिला परिषद के पास नहीं है। अतः मार्किटिंग बोर्ड की सड़कों का निर्माण केवल मार्किटिंग बोर्ड द्वारा ही किया जाये और सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए मार्किटिंग बोर्ड को ही जल्द से जल्द पैसा मुहैया करवाने का काम किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के हर गांव में तालाबों से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तालाबों का पानी ओवर फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा हो जाती हैं। यदि एक बार मशीन से तालाबों की खुदाई कर दी जाये तथा इनकी चारदीवारी बना दी जाये और फिर तालाबों से पाइप लाइन दबाकर, खेतों तक पहुंचा दी जाये चाहे एक किलोमीटर लंबी लाइन दबानी पड़े या दो किलोमीटर लंबी लाइन दबानी पड़े तो इसका फायदा यह होगा कि तालाब न तो ओवर फलो होंगे और न ही हमारी सड़कें टूटेंगी और न ही गलियां व नालियों में पानी खड़ा होगा। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार अच्छे–अच्छे काम कर रही है लेकिन मेरा सुझाव यह भी है कि सरकार को और ज्यादा अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि 36 बिरादरी के सभी लोगों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां त्योड़ा–त्योड़ी गांव में केवल मात्र दसवीं क्लॉस तक का स्कूल है। यदि इस स्कूल को अपग्रेड करके 12वीं तक का कर दिया जाये तो हमारे जो बच्चे हैं जिनको आगे की पढ़ाई के लिए दूर–दूर जाना पड़ता है, उनके लिए यह बहुत ही सहूलियत का काम हो जायेगा। अतः माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे तुरंत प्रभाव से इस स्कूल को अपग्रेड करने का काम करें। मैं उनका बहुत–बहुत धन्यवादी होऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जगदीश नायर (होडल) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, बजट किसी भी

सरकार का एक वित्तीय प्रबंधन होता है। हर सरकार द्वारा अपने वित्तीय प्रबंधन के लिये पैसा जुटा कर हर विभाग में कैसे काम–काज किये जायेंगे, इसका एक मसौदा तैयार किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बत्तौर वित्त मंत्री ने तीसरा बजट प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही सौभाग्य और सम्मान की बात है। यह बजट कल्याणकारी, प्रगतिशील और हर वर्ग को लुभाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022–23 के लिए 177255.99 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है जो संशोधित अनुमान वर्ष 2021–22 के 153384.40 करोड़ रुपये से 15.6 प्रतिशत की वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट परिव्यय में 61057.36 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 116198.63 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय शामिल हैं जो क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, भवन एवं सड़कें, परिवहन, महिला विकास, खेल युवा मामले, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण व शहरी विकास, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सिंचाई और जल संसाधन आदि पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सदन में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में संस्कृति मॉडल स्कूलों के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का रूझान बढ़ा है। इसी को देखते हुए सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। इससे शिक्षा के स्तर में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तीन शहरों में महिला कॉलेज खोलने के लिये बजट में प्रावधान किया है। पढ़ने वाली छात्राओं के लिए अच्छी और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हो, इसका भी जिक्र बजट में किया गया है। जिससे हमारी बेटी व बहन पढ़ने के लिये आगे आयेंगी। इस बजट में सभी कॉलेजों में कम से कम 10 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का भी प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख विद्यार्थियों की वर्ष में दो बार स्वास्थ्य जांच की जायेगी, एक अनूठी पहल की शुरूआत की है। पांचवीं कक्षा से कम्पयूटर की शिक्षा पढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया डिजिटल बनने जा रही है, इसलिए सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022–23 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रों के लिए 8925.52 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सभी पी.एच.सीज. को सी.एच.सीज. में अपग्रेड करने

का प्रावधान किया गया है। सभी उपमंडलों में 100–100 बेडिड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में 10 वैलनेस सैंटर्ज बनाने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा स्नातकों को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों मे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों 40 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को इन सभी सेवाओं के लिये पलवल की जनता की तरफ से तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 20–25 साल तक शासन किया लेकिन हमने अपने क्षेत्र पलवल में इतना विकास कभी नहीं देखा जितना अब हो रहा है । अब हमें अनेक सौगातें दी जा रही हैं । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बिजली में सुधार के लिए बिजली विभाग को बजट में 7203.31 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है । प्रदेश में 24 घण्टे बिजली देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अथक प्रयास रहा है । इसके लिए मैं माननीय बिजली मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा । आज हरियाणा प्रदेश के 5569 गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है । आज इस मामले में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, तारें बिछाई जा रही हैं, खम्बे खड़े किये जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, लगता है कि हरियाणा प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है । इसके बावजूद भी विपक्ष के साथी शोर मचाते हैं । इस बजट में हरियाणा के सभी गांवों को 24 घण्टे बिजली मुहैया करवाने के लिए इस बजट में प्रोविजन किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी गांवों में 24 घण्टे बिजली देने के लिए जनता से वायदा भी किया हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ाने और उसे दोगुनी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिंचाई विभाग के बजट में 6136.36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । आज किसान के हित के लिए बाहर से आते हुए पानी को एंट्री करने से रोकने, नहर की टेल एंड तक पानी पहुंचाने, रजवाहों की सफाई करवाकर उन्हें पक्का करवाने जैसे कार्य करवाये जा रहे हैं । इन कार्यों से सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त होगी जोकि किसान के खेत में पानी पहुंचाने में मदद करेगी । अब मैं लोक निर्माण विभाग के विषय में बात करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश की सड़कें अच्छी होती हैं उस प्रदेश का विकास अपने आप ही दिखाई देने लग जाता है । आज हरियाणा

सरकार ने इस विषय में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है । हरियाणा प्रदेश की जितनी भी सड़कें 11 फुट चौड़ाई की थी सरकार ने उनको 18 फुट चौड़ा करने का निर्णय लिया है । ऐसा नहीं है कि सरकार ने केवल यह फैसला ही लिया है । इसके लिए सभी विधान सभा क्षेत्रों में जाकर देखा जा सकता है । मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं । मेरे क्षेत्र में 18 फुट चौड़ाई की सड़कें बनाई जा रही हैं और बहुत अच्छे मैटेरियल के साथ बनाई जा रही हैं । इसके लिए मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं । प्रदेश में अनेक सरकारी भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बन रहे हैं । हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अनेक राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली से वड़ोदरा राजमार्ग, इस्माइलाबाद से नारनौल, दिल्ली से कटरा राजमार्ग, गोहाना से सोनीपत की सड़क को फोरलेन, नारनौल बाइ पास को सिक्सलेन, रिवाड़ी से नारनौल की सड़क को फोरलेन बनाया गया जोकि राजस्थान की सीमा से जोड़ेगा, पानीपत से दिल्ली के राजमार्ग को एटलेन, रिवाड़ी बाईपास को फॉरलेन, जीन्द से गोहाना की सड़क को फोरलेन, गोहाना से पटौदी की सड़क को फॉरलेन किया जा रहा है । इनके द्वारा विकसित प्रदेश का ढांचा तैयार किया जा रहा है । यह बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच का परिणाम है । अब मैं प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर बोलना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा । प्रदेश में परिवहन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बजट में 2821.83 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है । अब तक प्रदेश में 809 नई बसें, 20 लग्जरी बसें, 150 ए. सी. बसें खरीदी जा चुकी हैं । इसके अलावा सरकार का 2000 नई बसें खरीदने का टार्गेट है और 1000 नई बसें इसी साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय परिवहन मंत्री जी ने खरीदने का फैसला ले लिया है । यह एक सराहनीय कदम है । इससे प्रदेश विकास की ओर दौड़ता हुआ दिखाई देगा । इसी तरह से महिला एवं बाल विकास के लिए बजट में 2017.24 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है । हमारी सरकार का 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा है । सरकार ने बेटियों के लिए अनेक योजनाएं जैसे साथी योजना, मातृ वंदना योजना चलाई है और 4000 प्ले स्कूल खोलने के बारे में बात की है ।

श्री उपाध्यक्ष : जगदीश जी, अब आप बैठिये । आपका समय पूरा हो गया है ।

श्री जगदीश नायर : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने खेल एवं युवा मामलों के संबंध में बजट में 540.50 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है । इसी तरह पुलिस के कल्याण के लिए सरकार ने बजट में 8181.16 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : जगदीश जी, अगर आपकी कोई बात कहनी रह गई हो तो आप उसे हमें लिखकर दे दें । हम उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना लेंगे ।

श्री जगदीश नायरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे रखना चाहता हूं। चूंकि टाईम की कमी है, लेकिन मैं किसी माननीय सदस्य के बोलने का समय खराब नहीं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बिजली घरों की कमी है और उनको खाम्वी, भिडूकी और गढी गांवों में बनाया जाना चाहिए। ये बड़े गांव हैं। औरंगाबाद, बन्चारी, सौन्दह और हसनपुर गांवों में पॉलिटैक्निक कॉलेजिज खोले जाने चाहिए। खाम्वी गांव में कन्या महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। यमुना नदी पर हसनपुर में पुल की लम्बित मांग के लिए पिछले साल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 210 करोड़ रुपये जमा करवाये हैं, इसका काम भी शीघ्र शुरू करवाया जाना चाहिए। मेरे हल्के में मैडिकल कॉलेज खोला गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। हसनपुर के चारों तरफ बाई–पास बनाया जाए। होडल के चारों तरफ बाई–पास बनाया जाए क्योंकि वहां पर बाई–पास की जरूरत है। होडल से हसनपुर सड़क को चार लेन करने की जरूरत है। हसनपुर से वामनी खेड़ा सड़क को चार लेन किया जाए। नयी नहर –7 घासेड़ा से खाम्वी, मरौली सीया, बन्चारी, सौन्दह, लुहेना, डाडका, गढ़ी तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के गांवों के लिए रैनीवल परियोजना बनाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे हल्के के बेठा गढी, भुलवाना, होडल, पैंगलतू, खाम्वी, गौडोवा, बन्चारी, सौन्दह लुहेना, सेवली, सराय, मिन्तरौल, औरंगाबाद विघौट गांवों को रैनीवल व्यवस्था से जोड़कर पानी देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन गांवों को रैनीवल परियोजना से जोड़कर पानी देने का काम किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा बजट है और मैं इसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व

वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है, इसमें 74 पेज हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा प्रदेश की जनता के हक में 74 शब्द भी नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्षः शकुंतला जी, क्या इसमें शब्द भी नहीं हैं ?

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट खोखाला और जनता को अंधकार में ले जाने वाला है। इस बजट में हरियाणा प्रदेश की जनता के किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसमें चाहे किसानों की बात करूं, मजूदर की बात करूं, महिलाओं की बात करूं या युवाओं की बात करूं, ये सभी के सभी वर्ग सरकार का मुंह ताकते रह गये क्योंकि इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं किसानों की बात करूं तो उनके हालात बहुत खराब हैं। किसानों की फसलें कभी जल भराव से खराब होती हैं और कहीं पर ओलावृष्टि से खराब होती हैं। सरकार उनका समय पर कोई भी उचित मुआवजा नहीं देती। जबकि सरकार गिरदावरी करवाकर किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है। सरकार ने वर्ष 2022 में किसानों की दोगुनी आमदनी करने की बात की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि किसानों की खेती पर जो लागत लगती है, वह भी नहीं मिल रही है।

श्री उपाध्यक्षः शकुंतला जी, आप इस बात को तो मानती हैं कि किसानों की फसलें एम.एस.पी. से ऊपर बिक रही हैं।

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को उनकी फसलों का एम.एस.पी. नहीं मिल रहा है जिसके कारण आज वह कर्जे में डूब रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सरकार डिजिटल क्लास रूम की केवल बात ही करती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि धरातल पर असलियत कुछ और है। जिन गांवों में स्कूल्ज की बिल्डिंग सालों से टूटी पड़ी हुई हैं वहां पर बच्चे खुले आसमान में बैठने पर मजबूर हैं। सरकार कहती है कि वहां पर डिजिटल क्लॉस लगवाएंगे। मेरे हल्के के 4–5 स्कूल्ज की बिल्डिंग्ज टूटी पड़ी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई बार कह चूकी हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी कह चुकी हूं। इनमें कलानौर, कलावड़, भाली और गरनावठी गांव शामिल हैं, लेकिन इन गांवों के स्कूल्ज की आज तक बिल्डिंग नहीं बनी हैं। इस प्रकार कहां पर डिजिटल क्लॉसिज लगायी

जाएंगी ? क्या सरकार खुले आसमान में डिजिटल क्लॉसिज लगवाएगी, जहां पर केबल भी नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी को कई बार कह चुकी हूं, परन्तु वह काम नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है। (विघ्न) इनके पास हंसने के सिवा कोई काम नहीं है। माननीय मंत्री जी का शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बेरोजगारी की बात करूंगी। आज हमारा युवा वर्ग बेरोजगारी झेल रहा है और हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नम्बर–वन पोजीशन पर है। इस सरकार ने जो भी भर्ती निकाली है, उनको सरेआम नीलाम करने का काम किया है। इस सरकार से और इनकी नीतियों से हमारा युवा वर्ग बहुत ही तंग है। अब मैं महिलाओं की बात करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला दिवस पर बजट पेश किया था। मैं यह कहती हूं कि हमारी आंगनवाडी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं। आज वे रोड पर घूम रही है। सरकार इन पर लाठियां बरसाने का काम कर रही है। उनका क्या हाल होता होगा, आप इस बात से सहज ही अंदाजा लगा सकते है। क्या महिलाओं की इज्जत यही है। सरकार उन महिलाओं को रोजगार के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण देती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऋण 3 साल के लिए बाउंड कर दिया । मैं कहना चाहती हूं कि 3 लाख रुपये में तो चाय की दुकान ही नहीं खुलती है। (विघ्न)

16:00 बजे

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार सारे देश में महिलाओं को रोजगार के लिए सबसे ज्यादा लोन दे रही है।

श्रीमती शंकुतला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ की बात करूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अस्पताल का नहीं बल्कि मैं प्रदेश के सभी अस्पतालों की बात करूंगी। आज प्रदेश के सभी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। किसी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं है। किसी अस्पताल में सी.टी. स्कैन की मशीन नहीं है। किसी अस्पताल में एल.टी. नहीं है और किसी में डॉक्टर नहीं है और किसी किसी अस्पताल में तो एनिस्थेटिक डॉक्टर्ज भी नहीं हैं। सरकार कहती है कि हम हरेक जिले में मैडीकल कॉलेज बनायेंगे। मैं हाथ जोड़कर यह बात कहती हूं कि सरकार हर जिले में मैडीकल कॉलेज बनाये। शौक से बनाओ लेकिन पहले जो बने हुए अस्पताल हैं उनमें भी सुधार करने का प्रयास करे। आप लोगों का भला होगा क्योंकि दो ही सब्जैक्ट मैन होते हैं पहला हैल्थ और दूसरा एजूकेशन और

इन्हीं दोनों सब्जैक्ट्स का भट्ठा बैठा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एस.सी.बी.सी. कैटेगरी के लोगों की बात करूंगी। बड़े ही शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी ने एस.सी.बी.सी. वर्ग का इस बजट में से नाम ही मिटा दिया। इस बात से साबित होता है कि सरकार को इन लोगों से लगाव नहीं रहा। सरकार उन लोगों की इज्जत नहीं करती, सरकार उन लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रही है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। मैं कहना चाहती हूं कि वोट लेने के लिए तो एस.सी.बी.सी. कहते रहते हैं लेकिन जब इनके उत्थान की बात आती है तो बजट अभिभाषण में से नाम ही गायब मिलता है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे हल्के की बात है तो मेरे हल्के में लड़कियों के लिए स्कूल की बिल्डिंग टूटी पड़ी है। कलावहड़, कलानौर, गरनाउठी भाली में आज तक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। मेरे हल्के के कुछ रोडज भी टूटे पड़े हैं। कनहेली बाई–पास से लेकर वृद्धा आश्रम तक, गरनावहटी मोड से लेकर गरनावहटी तक गढ़ी बलहम से लेकर निगाना तक आई.एम.टी. रोड से लेकर नौनद सरकारी स्कूल तक। अब मैं बिजली की बात करूंगी लेकिन सदन में बिजली मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। हमारा बालंद गांव हैं। बर्रा का मतलब बी.जे.पी. वाले समझते होंगे या नहीं समझते। बर्रे के बीचों बीच 4 पोल लगे हुए हैं। मैं इस बारे में हजार बार कह चुकी हूं लेकिन अभी तक ये 4 पोल हटाये नहीं गये हैं और यहां तक बालंद गांव की जनता कह चुकी है लेकिन अभी तक पोल नहीं हटाये गये हैं। इसी तरह से रिटोली में रोड के बीचों बीच दो पोल लगे हुए हैं। मैंने भी इस बारे में कहा और हल्के वालों ने भी इस बारे में कहा था लेकिन अभी तक पोल नहीं हटाये गये हैं। वहां पर इस बात को लेकर कितनी बार इंसीडैंट हुआ है और वहां पर न जाने कितनी ही डैथ्स हो चुकी हैं।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि ये पोल कब लगाये गये थे?

श्रीमती शंकुतला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि इनकी सरकार के समय में हमारे बर्रे पर और रोड पर भी पोल लगाये हैं। मेरे हल्के की 65 कॉलोनियां रोहतक नगर निगम में लगती है। उन कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। उनमें न तो सीवर की व्यवस्था ठीक की गई है और न ही पानी और बिजली इत्यादि की व्यवस्था ठीक की गई है। अगर वहां के लोग उस पानी को पीते हैं तो सीवर का मिक्स पानी पीते हैं। मैंने पहले भी इस बारे में कहा था। उन लोगों ने मुझे यह कहा कि बहन जी आप एक बोतल

इस पानी की भरकर ले जायें और सत्ता पक्ष के लोगों को इस पानी की एक–एक घूंट पिला देना कि हम कैसा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं।

श्री कंवर पाल : बहन जी, आप क्या पानी की बोतल लेकर आई हैं?

श्रीमती शंकुतला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अगली बार वहां से पानी की बोतल भरकर ला दूंगी। मैं अपने हल्के के अस्पताल की बात करूं तो वहां की बिल्डिंग टूटी पड़ी है। उसको दोबारा से बनाने का काम करें। हमारे किसानों की बेमौसमी बरसात से और ओलावृष्टि के कारण जो फसल खराब होती है उसकी प्रोपर गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने का काम किया जाये। कलानौर को सब–डिवीजन बनाने का काम करें। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के लिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वे रोड पर धक्के खा रही है। सरकार अपनी जुबान से की गई बातों को मुकर जाती है। कम से कम कहीं तो जुबान पर रहो । महिला दिवस पर सरकार बजट पेश कर रही थी और महिलाएं रोड पर हैं। कर्मचारियों की पुरानी पैंशन जल्दी लागू करनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहती हूं कि हमारे एस.सी.व बी.सीज. भाइयों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया गया है । अपने एस.सी. व बी.सीज. भाईयों के लिए बजट में कुछ न देने के लिए और इस बजट से उनका नाम मिटाने पर मैं वॉक–आउट करती हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, हम सारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्रीमती शुकंतला खटक जी के साथ सदन से वॉक–आउट करते हैं।

वॉक–आउट

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एस.सीज. और बी.सीज. के लिए बजट में कुछ न देने और उनका बजट से नाम मिटाने के विरोध में एज ए प्रोटैस्ट सदन से वॉक–आउट कर गए ।)

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद । माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022–2023 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गो का ख्याल रखा है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य तो शिडयूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासिज के नाम पर ऐसे ही हाउस से चले गए हैं जबकि एस.सी. और बी.सी. के लिए बजट में पूरा इंतजाम किया गया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का

धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भिवानी में दो तीन प्रोजैक्ट नए दिए गए हैं । नर्सिंग कालेज के लिए भिवानी को चुना गया है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं । रिंग रोड न्यू बाई–पास का प्रोजैक्ट भी मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया है, मैं आशा करता हूं कि कुछ समय बाद यह प्रोजैक्ट शुरू हो जाएगा इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, 70 प्रतिशत तक के दिव्यांग व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना में लिया गया है जिसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसी बातें हैं जो इस बजट में नहीं लिखी गई हैं लेकिन हमारी सरकार उसको लेकर चल रही है । गरीब लोग, रेहड़ी, फड़ी वालों के लिए लोन देने की सुविधा, महिलाओं को काम करने के लिए लोन की सुविधा आदि बातें सब बजट के बाहर की बातें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बाल ऋण, किशोर ऋण और युवा ऋण ये तीन टाइप के ऋण हमारी सरकार अधिक से अधिक उपलब्ध करवा रही है । इन स्कीमों के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चाहे वे किसान हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे होस्पिटल की बात हो और चाहे स्कूलों की बात हो इन सबके लिए खुले दिल से बजट में व्यवस्था की है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें कर रहा हूं । 138 स्कूलों को पहले संस्कृति विद्यालय में माइग्रेट करने का काम किया गया है । भिवानी का एक स्कूल पिछली बार संस्कृति विद्यालय मे माइग्रेट हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, 5–6 स्कूल ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है मैं कहना चाहूंगा कि इन स्कूलों को भी आने वाले समय में संस्कृति विद्यालय में बदलेंगे तो हमारे बच्चों का उत्थान होगा । इन स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और इन स्कूलों में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, मैं इसके लिए मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जो हमारे होस्पिटल्ज हैं उनका अच्छी प्रकार से काम चल रहा है । हमारे मैडीकल कालेजिज का काम हो चाहे हमारी यूनीवर्सिटीज का काम हो, सब पर काम चल रहा है । मैडीकल कालेज का काम तो हमने 6 महीने में 30 परसैंट पूरा कर लिया है तथा आने वाले इस साल में उनको एक टारगैट दिया है कि आप इस साल में हमारा मैडीकल कालेज चालू कर दें और उसकी व्यवस्था के लिए बंधु साथ हैं और हमारे ठेकदार इन कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 8 महीने पहले

जून–जुलाई के महीने में कोविड–19 के समय में भिवानी अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत थी जो उपलब्ध करवाना बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय हमें 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। आज वहां आक्सीजन का प्लांट भी बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उन दिनों में दी गई वे बड़ी उत्तम थी और उन सुविधाओं को हरियाणावासियों ने सराहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भिवानी के अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। यदि वहां बाल रोग विशेषज्ञ और चरम रोग विशेषज्ञ लगा दिये जाये तो वहां निकू वार्ड और स्किन रोग की ओ.पी.डी. का काम सुचारू रूप से चल जायेगा। इसी तरह से वहां सिटी रेलवे स्टेशन के पास राजीव कॉलोनी है जिसमें जल की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। वहां जल आपूर्ति करने के लिए बूस्टिंग स्टेशन बनना था जिसके लिए जमीन भी ली गई थी लेकिन उसमें कुछ अड़चन आ गई इसलिए वह बूस्टिंग स्टेशन नहीं बन पाया। मेरी मांग है कि वहां हुड्डा सैक्टर–13 और उससे आगे सैक्टर–23 शहर की तरफ है वहां पर ग्रीन बैल्ट में एक हजार गज जगह बूस्टिंग स्टेशन लगाने के लिए मिल जाये तो राजीव कॉलोनी के लिए पानी का प्रबंध हो जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की जो नीतियां बनाई हैं वे सराहनीय हैं। अगर मैं रोड की बात करूं तो प्रदेश सरकार द्वारा और केन्द्र सरकार द्वारा बहुत सी नयी सड़के हमारे ऐरिया में बनाई गई हैं। हमारे डाहना रोड से रोहतक रोड, रोहतक रोड से महम रोड पर मिनी बाई–पास बनाया गया है जिसके कारण वहां ट्रैफिक जाम में कमी आई है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांग रखना चाहूंगा कि 100 एकड़ जमीन भिवानी के साथ लगती हुई है जिसमें कूड़ा डाला जाता है। वहां पर अभी तक सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजैक्ट नहीं लग पाया है। यदि यह भी जल्द चालू हो जाये तो 20 एकड़ में काम चल सकता है और 80 एकड़ जमीन पर पार्क तथा हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई जायेगी तो अच्छी व्यवस्था हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, भिवानी सब्जी मंडी रोहतक गेट पर है जहां भीड़ रहती है। वहां सैक्टर–31 है जिसकी 450 एकड़ जमीन है उसमें से 100 एकड़ पर ट्रास्पोर्ट नगर बन जाये और 60–70 एकड़ जमीन पर सब्जी मंडी बनाने का प्रस्ताव लिखित में सरकार को दे दिया गया है। इस पर अवश्य विचार किया

जाये। इसके अतिरिक्त वहां 250 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम किया जाये। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मांग करूंगा कि भिवानी शहर का 5 किलोमीटर का सर्कुलर रोड 3 डिवीजन में बटा हुआ है। जिसके कारण उसका काम नहीं हो पा रहा है। उसका कभी एक टुकड़ा बन जाता है तो कभी दूसरा टुकड़ा बन जाता है लेकिन यह कभी पूरा नहीं बनता। मैं चाहता हूं कि एन.एच. –709 ई से बी.एण्ड.आर. और एन.एच. जींद उसमें लगते हैं। यदि यह पूरा क्षेत्र एक डिविजन में कर दिया जायेगा तो कार्य जल्दी होगा और सुंदर भी होगा। ऐसा करने से उसकी सिमिट्री भी एक बन जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, भिवानी शहर में पीने के पानी की पाईप लाईन बहुत पुरानी हो चुकी है। 1970–72 में जो सरकार थी उस समय ये पाईप लाईनें डली थी। आज वहां 10 किलोमीटर पाईप लाईन की आवश्यकता है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाये। इसके अतिरिक्त वहां एल.ई. डी. बल्ब की आवश्यकता है यह आवश्यकता भी जल्द पूरी की जाये।

श्री उपाध्यक्षः घनश्याम जी, आपका समय हो गया है, प्लीज अब आप बैठे।

श्री घनश्याम सर्राफ : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के कुछ मांगें है, मैं लिखित रूप में दे रहा हूं कृप्या आप इनको प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना ले।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है आप लिखकर दे दो इसे प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना लिया जायेगा।

***श्री घनश्याम सर्राफः** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की निम्नलिखित मांगे हैं इन्हें भी पूरा करवाया जाये।

1. शहर में न्यू बस स्टैंड से लेकर आर.ओ.बी. तक एन.एच.–709ई रोड एन.एच. द्वारा आर.सी.सी. का बनाया जाना है इसका कुछ कार्य बाकि रह गया है और ड्रेनेज व इंटर लॉक ब्लाक एक एस्टीमेट हरियाणा सरकार को भेजा जा चुका है उसको जल्द से जल्द पूरा करवायें।

2. तिगडाना मोड़ से लेकर निनान तक बाईपास बनवाया जाये ताकि भारी वाहनों का शहर में प्रवेश रोका जा सके।

3. सब्जी मंडी को सैक्टर–31 में स्थापित किया जाये।

4. घंटाघर का भीड़–भाड़ का इलाका है जहां सर्कुलर रोड पर सभी बैंक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हुड्डा सिटी सैंटर के साथ लगती एच.एस.

***चयेर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

वी.पी.एन. की जमीन पर एक बैंक स्कवायर का निर्माण करवाया जाए।

5. भिवानी से कालका एकता एक्सप्रेस को पुनः शुरू किया जाये।

6. राजीव कॉलोनी में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण करवाया जाये।

7. हनुमान ढानी, पिपली वाली, जोहड़ी रेलवे फाटक पार पेयजल लाइन डाली जाये।

8. लोहारू रोड, शिमन सेंटर के स्थान पर जी.वी.डी. पशु का अस्पताल बनवाया जाये।

9. भिवानी शहर में न्यू ऑटो मार्केट के सामने नगर सुधार मंडल की मार्केट और ऑटो मार्केट के आगे आर.सी.सी. का रोड बनाया जाये । चौधरी देवी लाल की मूर्ति के पीछे आर.सी.सी. का रोड भी बनाया जाये यह सड़क नगर परिषद् के अंतर्गत आती है।

10. एच.एस.वी.पी. की मार्केट और काठ मंडी के आगे की दुकानों के आगे की आर. सी.सी. का रोड बनाया जाये एवं अनाज मंडी गेट न. 2 के साथ लगती ग्रीन बैल्ट को ठीक किया जाये।

11. भिवानी शहर की राजीव कॉलोनी, देव नगर कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी को एम. सी. के दायरे में शामिल किया जाये।

12. बासिया भवन से लेकर डॉ. एम.एल. शर्मा अस्पताल, जू रोड तक एच.एस.वी.पी. की दोनों तरफ के रोड, फुटपाथ, ग्रीन बैल्ट आदि कार्यों को जल्द पूरा किया जाये। वहां पर एक तरफ की सड़क बनाई गयी है दूसरी तरफ की सड़क भी बनाई जाये।

13. शिक्षा बोर्ड से लेकर हांसी गेट, महम गेट, रोहतक गेट तक एन.एच. रोड जो जींद रोड का हिस्सा है इसे कार्पेटिंग किया जाये। फूटपाथ छोटे किये जाये और शिक्षा बोर्ड से हांसी गेट तक बीच में ग्रिल लगाई जाये।

14. शहर के लघु सचिवालय के पीछे भीम स्टेडियम रोप, एल.आई.सी. कार्यालय के सामने एच.एस.वी.पी. द्वारा सभी ग्रीन बैल्ट को नया बनाया जाये।

15. सैक्टर–13 में स्थित जिम खाना क्लब का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है उसको भी पूरा करवाया जाये।

16. नगर परिषद् द्वारा पतराम गेट चौंक से लेकर हालु बाजार चौंक तक सड़क की कार पेंटिंग की जाये।

17. ठाकुर बीर सिंह पार्क में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया जाये।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (अ.जा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हम आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन जिनके कारण हम 75 वीं वर्षगांठ मना रहे है उनको प्रदेश की सरकार भुलाये बैठी है। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का गठन ही नहीं हो रहा है। यह बात मैंने पहले भी रखी थी। यदि आजादी की 75 वीं वर्षगांठ में भी स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का गठन नहीं होगा तो फिर कब होगा ? यह एक मंच है जिसमें वे अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन–सी ताकत है जो इस समिति को बनने से रोक रही है। मेरे साथ–साथ प्रदेश में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन–सी ताकत है जो इस समिति को बनने से रोक रही है और जिसके दबाव में इस समिति का गठन नहीं हो पा रहा है। उस ताकत के बारे में सदन में बताया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, चार साल पहले माननीय मुख्य सचिव द्वारा जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया कि 250 के करीब आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों के परिवारों का पता लगाया जाये लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस पर अभी भी कार्यवाही नहीं होगी तो कब होगी ? सर, यह वर्ष, 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि वर्ष, 2022 में किसानों की आय दोगुनी होनी थी और इसी प्रकार से वर्ष, 2022 में सब के सिर पर छत आनी थी लेकिन इन दोनों विषय पर हमारे बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है। Out put, out come, based on frame work की बात की जाती है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है। जिस वर्ष में किसानों की आय दोगुनी होनी थी, उस वर्ष में प्रदेश में सवा लाख किसानों के टयूबवैल के कनैक्शन पैंडिंग हैं। इसके अतिरिक्त सरकार कहती है कि किसानों के साथ बीज से लेकर मंडी/बाजार तक खड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों के साथ खड़ी तो है लेकिन किसानों की परेशानियां बढ़ाने के लिए साथ खड़ी है । उनकी परेशानियों को घटाने के लिए साथ नहीं खड़ी है। कहीं किसानों को सूरजमुखी की फसल का बीज नहीं मिलता, कहीं किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती, कहीं समय पर गेट पास नहीं मिलता और गन्ने की पेमैंट नहीं मिलती। इस तरह की बहुत सी समस्याएं किसानों के साथ हैं। खाद की कमी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगा और जवाब भी मिला लेकिन किसानों को

समय पर खाद नहीं मिली। किसानों को खेती के लिए समय पर बीज और खाद मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने किसानों की आय दोगुनी हुई और कितने गरीब लोगों के सिर पर छत मिली और कितनों को अभी मिलनी बाकी है। इस बारे में सराकर बताये तो सही ? अध्यक्ष महोदय, बजट में लिखा गया है कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से हरियाणा आगे बढ़ चला है। सर, अधूरे लक्ष्य तो पीछे रह जाते हैं और हरियाणा सरकार तेजी से आगे बढ़े चले जाती है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बजट में लिखा गया है कि रेल कोरिडोर बन रहे हैं, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बन रहे हैं और हमारे जो गरीब साथी हैं जो पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुचते हैं वे ट्रेने बंद हो रही हैं। वे विद्यार्थी, गरीब व्यक्ति और दिहाड़ीदार कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायेंगे जब ट्रेनें ही बंद पड़ी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी को पत्र लिखा जाये कि जो ट्रेनें कोरोना काल से पहले चला करती थी उनको दोबारा चलाया जाये। इसी तरह से अगर डायल 112 की बात की जाये तो उस पर अरबों रुपये खर्च किये गये हैं जैसे कि इससे पहले कोई इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं थी। 100 नम्बर तो पहले भी काम कर रहा था, ऐसा नहीं था कि पहले 100 नम्बर पर कॉल करने पर पुलिस अगले दिन पहुंचती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी थी। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात यह हुई कि अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि डायल 112 पर 60 दिन में 7 लाख से भी ज्यादा कॉल्स आई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह खुशी मनाने की बात है? क्या वे कॉल्स बधाई देने के लिए आई थी, वे कॉल्स अपराध और अपराध से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आई थी। यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े दुख की बात है कि इतना अपराध बढ़ रहा है। आज आउटपुट–आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क की बात की जा रही है तो यह बताया जाये कि ये जो अरबों रुपये इस डायल 112 पर खर्च किये गये हैं तो इससे अपराध कितना घटा है इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। इसी तरह से एस.सी. कम्पोनैंट प्लान के बारे में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। एस.सी. कम्पोनैंट प्लान में कोई खर्च नहीं किया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर कोई प्राधिकरण बनना चाहिए तथा जिला स्तर पर निगरानी समितियां बननी चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020–21 के लिए माइक्रो इरीगेशन स्कीम फॉर एस.सीज.

का बजट 11 करोड़ 84 लाख रुपये था लेकिन उसमें शून्य खर्च हुआ है। इसी तरह से स्कीम फॉर लाइव स्टॉक इंश्योरैंस फॉर एस.सीज. के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट था और उसमें भी शून्य खर्च हुआ है। इसी तरह से एस.सीज. मैम्बर्स के लिए हाउसिंग कोआप्रेटिव लोन के लिए 50 लाख रुपये का बजट रखा गया था लेकिन उसमें से भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयन्ती महाग्राम विकास योजना फॉर एस.सीज. प्रोग्राम के तहत 3.33 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था लेकिन उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। राजीव आवास योजना जिसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया उसके लिए 35 करोड़ रुपये का बजट था लेकिन उसका खर्च भी शून्य रहा है। इसी तरह से एस.सी. कमीशन के गठन के लिए 1 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। बाबू जगजीवन छात्रावास योजना के लिए 80 लाख रुपये का बजट रखा गया था लेकिन उसमें से भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एस.सी. कम्पोनैंट प्लान के लिए अलग से राज्य स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन किया जाये तथा जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जायें ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं नम्बरदारों के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार की तरफ से पत्र निकाल दिया जाता है कि कोई नया नम्बरदार नहीं लगेगा, उसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से फ्रीज कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से इसको लागू करना पड़ा? 60–70 वर्ष की उम्र में उनका मैडिकल करवाया जा रहा है, क्या आप उनको बॉर्डर पर भेजेंगे? हमारे कौन–कौन से मंत्रियों का 60–70 साल की उम्र में मैडिकल हुआ है? उनकी आंखों की जांच करवा ली जाए कि वे किसी को पहचान सकते हैं या नहीं। मैडिकल में उनके कपड़े उतरवाये जा रहे हैं जो कि बहुत शर्म की बात है। हमारी सरकार किस तरफ जा रही है? यह तो बताया जाये कि उन नम्बरदारों से सरकार क्या करवाना चाहती है, क्या उनको बॉर्डर पर भेजना है या उनको कोई नौकरी देनी है? उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ओल्ड पैन्शन स्कीम पर अपनी बात रखना चाहता हूं। सभी कर्मचारी चाहते हैं कि उनको ओल्ड पैन्शन का लाभ मिले। इसी तरह से परिवार पहचान पत्र की बात की जाये तो हमारे बजट में बताया गया है कि 2 लाख 74 हजार रुपये सालाना आमदनी इसमें शामिल हैं और जिन परिवारों की वैरीफिकेशन हुई है अगर उनकी आय का पता लगायें तो

पता चलता है कि उनकी आय 90 हजार के करीब आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके मापदंड क्या हैं और किस तरह से इसका सत्यापन किया जा रहा है? परिवार पहचान पत्र के मुताबिक जिन परिवारों का सत्यापन कर रहे हैं उसके मापदंड क्या हैं? सरकार कहती है कि उसी के तहत सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा तथा उसी के अनुसार उनको नौकरी मिलेगी। अगर बेरोजगारी की बात की जाये तो आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे प्रदेश में हैं। इसी तरह से प्रदेश में नशे का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे थे तो मैंने उनसे कहा था कि जैसे आप फीमेल फोइटिसाइड के लिए जनता से कहते हैं कि अगर कोई शिकायत है तो बताइये इस प्रकार से आप नशे को घटाने के लिए प्रदेश में इस तरह का कोई कार्यक्रम क्यों नहीं चलाते? आप कोई एक हैल्पलाइन नम्बर बनाईये और जनता से पूछिये कि आपको कहीं कोई नशा बेचने या लेने की शिकायत आती है या कहीं आपको दिखाई देता है तो आप उसकी शिकायत करें लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि पिछले बजट में जो–जो घोषणाएं हुई थी उनमें से क्या–क्या पूरी हुई हैं उसी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो अब लिखा गया है इसमें कितनी सच्चाई होगी। पहले आप पिछली घोषणाओं के बारे में तो बताएं। वह कौन बताएगा। स्पीकर सर, लीगल कॉलोनीज की बात की गई, इल्लीगल कॉलोनीज की बात की गई, 7–ए के ऊपर भी बहुत चर्चा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : वरूण जी, वाईंड अप कीजिए।

श्री वरूण चौधरी : सर, मैं वाईंड अप ही कर रहा हूं। जो 7–ए की बात हुई है। मैंने उस संबंध में सवाल भी लगाया था कि पिछले कई सालों में कितनी लीगल कॉलोनीज बनाई गई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पूरी 90 विधान सभा क्षेत्रों में सिर्फ दो लीगल कॉलोनियां बनी हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनी हैं। बाकी लोग कहां जाएंगे। सरकार उन लोगों को इल्लीगल कॉलोनियों में रहने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार पहले लीगल कॉलोनियों का प्रावधान करे उसके बाद ही किसी को लीगल कॉलोनियों में रहने के लिए कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : वरूण जी, अगर कोई और बात है तो आप लिखकर दे दें।

श्री वरूण चौधरी : ठीक है जी, धन्यवाद।

श्री दुड़ा राम (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दो साल में कोरोना महामारी का सामना करते हुए विपरित परिस्थितियों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2022–23 का बजट पेश किया है जिसमें 15.6 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। मैं उसकी बहुत सराहना करता हूं कि बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। इस बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। उसमें चाहे गरीब मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, ग्रामीण विकास व आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई बढ़ौतरी में हमारी सरकार की अन्त्योद्य यानि सबसे गरीब व्यक्ति के कल्याण की नीति का परिणाम हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना महामारी से सीख लेते हुए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देकर पहले भी काफी सुधार किया है। इस बजट में हर जिले में मैडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना तैयार की है जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा इस बजट में खासकर कृषि और ग्रामीण विकास जो कि हमारे देश और प्रदेश के विकास का आधार है पर पूरा ध्यान दिया गया है। कृषि बजट में पिछले साल की बजाए करीब 28 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है और ग्राम विकास के बजट में पिछले साल की बजाए 83 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है जो कि बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष जी, इस सरकार ने सारे हरियाणा में सेमग्रस्त भूमि की तरफ भी पूरा ध्यान दिया है। सरकार ने सेमग्रसत एरिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बजट में भी इसका प्रावधान रखा है। खासकर गांवों में 24 घंटे बिजली देने की बात भी कही गई है तथा बिजली के नये कनैक्शन देने की बात भी कही गई है। इसके अलावा किसानों को जोखिम मुक्त खेती करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर बागवानी और मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना स्कीम सरकार ने शुरू की है जो किसानों की आय बढ़ाने और खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इस बजट में खासकर फतेहाबाद जिले में मैडिकल व नर्सिंग कॉलेज तथा ई.एस.आई. खोलने की घोषणा की है। इसके लिए मैं खासकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैडिकल कॉलेज खुलने के साथ–साथ फतेहाबाद के

साथ–साथ राजस्थान व पंजाब के हरियाणा के साथ लगते इलाकों का भी फायदा होगा क्योंकि फतेहाबाद के एक तरफ राजस्थान बॉर्डर पड़ता है और दूसरी तरफ पंजाब बॉर्डर पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में यह मैडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है उससे इस सारे इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे इलाके की जो जरूरी बातें है, वह भी मैं आपकी मार्फत सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे शहर में हुडा के कुछ सैक्टर हैं। वहां पर अल्फा और सोमा नाम की दो बड़ी कालोनियां हैं। यहां पर पीने के पानी की बहुत दिक्कत है और साथ ही मेरे इलाके में नहरी पानी की भी बहुत दिक्कत है। यहां का ग्राउंड वाटर भी ज्यादा बढ़िया नहीं है और कई बार तो यहां पर टैंकों से भी पानी लाना पड़ता है। हमारे यहां हुडा सैक्टर के अंदर एक जगह है जिसको पब्लिक हैल्थ का वाटर वर्क्स बनाने के छोड़ा हुआ है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यहां पर जल्द से जल्द वाटर वर्क्स बनाने का काम किया जाये और साथ ही मेरे इलाके में नहरी पानी की भी उचित व्यवस्था की जाये। इसके अलावा हमारा जो भूना शहर है वह आजकल बहुत बढ़ चुका है। उसके अंदर से एक सड़क जाती है। मेरी सरकार से मांग है कि यहां पर बाई–पास बनाने का काम किया जाये ताकि लोगों को आने–जाने में कोई दिक्कत न हो। इसी तरह फतेहाबाद के अंदर एक मिनी बाई–पास है। यह दो साल पहले बनाया गया था। मेरा निवेदन है कि इसको भी चौड़ा करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि जब हमारा फतेहाबाद शहर, सब–डिवीजन हुआ करता था, उस समय यहां पर सीवरेज लाइन डाली गई थी जोकि आजकल बहुत ही पुरानी हो चुकी है। बरसात के दिनों में यहां पर सीवरेज के माध्यम से पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोगों को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चूंकि फतेहाबाद जिला हैड क्वाटर बन गया है और यहां पर बहुत ज्यादा आबादी भी हो चुकी है तो यहां पर नए तरीके से तथा नए सिस्टम के हिसाब से सीवरेज लाइन डालने का प्रबंध किया जाये ताकि लोगों को बरसात के दिनों में कोई दिक्कत न हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जो हमारा भूना शहर है वह आजकल नगरपालिका बन चुका है लेकिन यहां का कुछ एरिया ऐसा है जोकि नगरपालिका से बाहर पड़ता है और इस प्रकार के एरिया न तो नगरपालिका का हिस्सा होते हैं और न ही पंचायत का हिस्सा होते हैं। ऐसी अवस्था में इस तरह

के एरियॉज में कोई भी डिवेलपमैंट का काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि तुरंत प्रभाव से यहां नगर पालिका का एरिया बढ़ाने का काम किया जाये और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस एरिया को पंचायत के अधीन लाने का प्रयास किया जाये ताकि इस इलाके का विकास हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां घागड़ गांव से एक बाई पास रोड बनाया गया है जोकि आगे दरियापुर तक जाता है इसलिए अब मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन है कि जो रोड पहले फतेहाबाद के अंदर से होकर निकलती थी, उस रोड को भी वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए चौड़ा करने का काम किया जाये और साथ ही यहां पर डिवाइडर भी बनाया जाये और स्ट्रीट लाइट्स का भी प्रबंध किया जाये। यह सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन आती है, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इससे मेरे एरिया के लोगों को बहुत फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के के कुछ स्कूलों की अपग्रेडेशन करने के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी एक रिक्वैस्ट की थी। इन स्कूलों की अपग्रेडेशन से संबंधित फाईल शिक्षा मंत्री महोदय के पास आई हुई है और ये स्कूल सभी प्रकार की कंडीशंज को पूरा करते हैं और अगर कोई स्कूल कंडीशंज को पूरा नही भी करता होगा तो भी हम उन कंडीशंज को पूरा कराने का काम करेंगें। अतः निवेदन है कि इन स्कूलों को जल्द से जल्द अपग्रेड करने का काम किया जाये। हमारे यहां जो काजल गांव है, सिंगथला गांव है, भट्टू मंडी है, हजूरी जाटी गांव है, मताना गांव है, घारणोपा गांव है और साथ ही कई और भी गांव है, जहां पर स्कूलों की अपग्रेडेशन का कार्य किया जाना अपेक्षित है। ये स्कूल्ज सभी प्रकार की कंडीशंज पूरा करते है। अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी अनुरोध है कि इस विषय पर तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फतेहाबाद हल्के में कुछ रास्ते छह करम के हैं और कुछ रास्ते पांच करम के हैं। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन सभी रास्तों को भी पक्का करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री इंदु राज (बरौदा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने को मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सभी को पता है कि जब बरौदा में उप–चुनाव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय

उप–मुख्यमंत्री महोदय, सरकार के सभी मंत्रीगण व विधायकगण ने बरौदा हल्के में डेरा जमाया हुआ था अर्थात् उस समय सरकार भी वहीं से चलती थी। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय व मंत्रियों ने बड़े–बड़े राजनीतिक मंचों पर उप–चुनाव में घोषणा की थी कि हम बरौदा में यूनिवर्सिटी बनायेंगे। बरौदा में आई.एम.टी. लेकर आयेंगे। बरौदा हल्के में दो–दो महिला कॉलेज बनायेंगे। बरौदा हल्के में राईस मिल्ज लगायेंगे लेकिन इस बजट के अंदर इन चीजों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या बरौदा हल्का हरियाणा के मानचित्र में नहीं आता है, जो उसके साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। बरौदा हल्के के निवासियों की बस यही गलती है कि उन्होंने एक अच्छा विधायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हराकर जिता दिया। बरौदा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने यह कहा था कि मैं आपका विधायक हूँ। श्रीमती निर्मला रानी, सोनीपत जिले के गन्नौर से विधायक चुनकर आई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला है, इसके लिये मैंने उनको बधाई भी दी थी, लेकिन उन्हें चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा सोनीपत में किये गये कार्यों की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गन्नौर में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ एक महिला कॉलेज की ही सौगात दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पांच–पांच यूनिवर्सिटी की सौगात दी थी। खानपुर में महिला यूनिवर्सिटी का काम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। सर छोटू राम यूनिवर्सिटी सोनीपत में देने का काम भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने किया था। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी सोनीपत में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने देने का काम किया था। सरकार तो आनी जानी होती है, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आयेगी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी अनेकों विकास कार्य सोनीपत में ही नहीं पूरे हरियाणा में करवायेंगे। यह तो समय–समय की बात होती है। उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार का बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में पूरे देश में नम्बर–1 पर था। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से निवेश, रोजगार, बुजुर्गों के मान सम्मान में, खिलाड़ियों के मान सम्मान में और विकास के मामलों में हरियाणा प्रदेश नम्बर–1 पर था। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार हो चुका है, इसी कारण वह अपराध व भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा में रोजगार नाम

की कोई चीज ही नहीं है। हरियाणा के युवाओं में रोजगार के नाम पर बहुत ज्यादा निराशा पैदा हो गई है। हमारे हरियाणा के छात्र व छात्राएं चाहे वह एम.ए., बी.एड., एम.फिल या एम.टैक कोई भी डिग्री धारक हो वे आज ग्रुप–डी की नौकरी करने के लिये मजबूर हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो कोई भी हरियाणा का युवक डी.सी. रेट पर भी नौकरी करने को तैयार नहीं होता था। आज बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि जितने भी हम विधायकगण साथी सदन में बैठे हैं, हमारे घरों के बाहर बेरोजगार युवाओं की लम्बी–लम्बी लाइनें लग जाती है कि हमें डी.सी. रेट पर नौकरी पर लगा दो। ऐसा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ क्यों हो रहा है। यह तो युवाओं के साथ धोखा है, जो नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने प्रदेश में अपराध को खत्म करने का काम किया था। अपराधी अपराध करना छोड़ गये या फिर अपराधी जेल के सलाखों में कैद हो गये, यह कारनामा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कर दिखाया था। आज यदि अपराध की बात करें तो हरियाणा प्रदेश नम्बर–1 पर है। हर रोज प्रदेश में चार–पांच बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इस सरकार ने एक नारा 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' का दिया था लेकिन आज आशा वर्क्ज और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। जब भी कोई नौकरी के लिये परीक्षा होती है तो हमारी बहन–बेटी 100–150 किलोमीटर तक बस में लटक कर जाती है, लेकिन सरकार उनके लिये कोई भी इंतजाम नहीं करती है। इस सरकार ने 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' का भी नारा दिया हुआ है। यदि प्रदेश में किसी ने जात–पात का नारा दिया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 36 बिरादरी का भाईचारा यदि किसी ने बिगाड़ा है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बुढ़ापा पैंशन की बात करें तो सरकार में बैठे हुए माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी पार्टी के मैनिफैस्टो में कहा था कि हम बुढ़ापा पैंशन को बढ़ाकर 5100 रुपये कर देंगे । बुजुर्गों की पैंशन बढ़ाने की तो बात छोड़िये इस सरकार ने हजारो बुजुर्गों की पैंशन को काटने का काम किया है । अगर किसी परिवार में 2–3 लड़कें हैं तो उन सबकी कमाई को जोड़कर उनकी इनकम को ज्यादा दिखा दिया गया और बुजुर्गों की पैंशन को काट दिया गया । यह कार्य बी.जे.पी. और जे.जे.पी. की सरकार ने किया है । यह सरकार गरीबों के उत्थान की योजना चलाने की बात करती थी लेकिन कांग्रेस

सरकार में गरीबों को जो तेल, नमक, चीनी आदि कम रेट पर मिलते थे । अगर उस कार्य को बंद करने का किसी ने काम किया है तो वह बी.जे.पी. और जे.जे.पी. की सरकार है । हुड्डा साहब की सरकार में हर उस परिवार को सौ गज का प्लॉट दिया गया था जिसका बी.पी.एल. कार्ड बना हुआ था । इसमें किसी भी जाति या वर्ग का भेद नहीं किया गया था । इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने उन प्लॉट्स पर मकान बनाने के लिए भी पैसे दिए थे । इस बजट में न तो कहीं पर गरीब को प्लॉट देने की बात की गई है और न ही मकान बनाने की बात की गई है । अगर सरकार के इन 7 सालों में किसी भी गरीब को कोई प्लॉट दिया गया हो या मकान बनाया गया हो तो उसके बारे में हमें बता दें । इस सरकार ने कर्मचारियों को पक्के करने का वायदा किया था लेकिन सरकार ने उनको नौकरियों से निकालने का काम किया है । सरकार ने ग्रुप–डी कर्मचारियों को भी नौकरी से निकालने का काम किया है । हजारों की तादाद में कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है । कुल मिलाकर इस सरकार ने अपने कहे हुए कामों से उल्टा ही काम किया है । इस सरकार के लिए मैं एक वाक्या सुनाता हूं । किसी ने पूछा कि क्या तू कुछ बनाना जानता है तो उसने जवाब दिया कि नहीं । फिर उसने पूछा कि मिटाना जानता है तो उसने दिया कि हां । मेरा कहना है कि यह सरकार तो सब कुछ मिटाने में लगी हुई है । इस सरकार में ऐसे लोग है जिन्हें बनाना तो कुछ नहीं आता लेकिन मिटाना सब कुछ आता है । यह सरकार हरियाणा प्रदेश से दुश्मनी निकाल रही है। यह सरकार न तो शहरी लोगों को देखकर खुश है और न ही गांव के लोगों को देखकर खुश है । जब किसान अपने हकों के लिए दिल्ली की ओर चले थे तो इस सरकार ने उन्हें करनाल में रोककर उन पर लाठियां बरसाई थी । अब वर्ष 2022 आ चुका है लेकिन इस बजट में किसान की आय दोगुनी करने का कोई प्रावधान नहीं है । अगर ऐसा कोई प्रावधान हो तो हमें बताया जाए । मेरा कहना है कि किसान की आय दोगुनी कैसे होगी ? आज किसान पूछ रहे हैं कि उनकी आय को दोगुनी करने के वायदे का क्या हुआ ? किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि जीवनदाता भी है । अतः किसान की भलाई के काम किये जाएं । जय हिन्द । धन्यवाद ।

श्री प्रवीण डागर (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा

1,77,255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है । यह बजट वर्ष 2021–22 के 1,53,384.40 करोड़ रुपये से 15.6 प्रतिशत एनहांस्ड है । इस बजट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' सबका प्रयास का स्लोगन चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है । पलवल जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और एक पिछड़ा हुआ जिला है । (विघ्न)

मोहम्मद इलियास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । हाउस में काफी धूआँ और प्रदूषण हो रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हाउस में हमारे लिए आंसूगैस के गोले छोड़े गए हैं ? इसकी भी इंकवायरी करवाई जाए । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : डागर जी, अब आप कंटीन्यू करें ।

श्री प्रवीण डागर : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के सतत् विकास के लिए डायमंड मॉडल को स्पष्ट किया है । इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आर्थिक विकास तथा मानव विकास पर बल दिया है । यह बजट हमारे प्रदेश के विकास में नये आयाम स्थापित करेगा । इसमें सरकार ने गरीबों के विकास तथा विकासात्मक शक्तियों की परिकल्पना की है । ये पांच शक्तियां हैं–समर्थ हरियाणा, अंत्योदय, सतत् विकास, संतुलित पर्यावरण, सहभागिता । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक किसान का बेटा हूं और खुद भी खेती करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस बजट में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 5988.76 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है जोकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि है । इससे प्रदेश के सभी किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है । 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' ऐसा प्राथमिक मंच है जिसके माध्यम से सरकार ने कई पहल की है । मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है । खरीफ, 2021 के दौरान भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561.11 करोड़ रुपये की राशि जारी करना यह दर्शाता है कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है । बजट में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 कलस्ट्र्स में प्रति कलस्टर की कम से कम 25 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा । इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग तथा पहले तीन वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का

धन्यवाद करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र हथीन में लगभग 6000 एकड़ जमीन सेम की समस्या से पीड़ित थी । माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस समस्या को खत्म करने के लिए एक पायलट प्रोजैक्ट तैयार किया गया । इसके लिए वहां पर लगभग 25 ट्यूबवैल्ज लगाए गए जिनके माध्यम से किसानों की लगभग 1000 एकड़ भूमि का सुधार हुआ है । इस प्रोजैक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने पिछले सैशन में भी मांग की थी । पिछली सरकारों ने किसान की अनदेखी की थी और वे किसान हितैषी होने का अब भी केवल ढोंग करते हैं । पिछले 20 वर्षों से हमारी एक मांग थी कि हमारी दुबालू माईनर को गहरा खोदकर उसे ड्रेन में तब्दील किया जाए ताकि सेम की समस्या से पीड़ित जमीन सुधर सके । किसी भी पिछली सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था । 23 फरवरी, 2020 को जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मेरे क्षेत्र में विकास रैली हुई तो उस समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक मांग की थी । आज उस मांग पर काम शुरू हो चुका है और उससे हमारे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं । हमें उम्मीद है कि अब तक हमारी जो हजारों एकड़ जमीन खराब हो रही थी अब उसमें सुधार होगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सेम की समस्या को दूर करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिए बजट में प्रावधान किया है । इससे प्रदेश में जो भूमि सेम की समस्या से ग्रस्त है उसको काफी लाभ मिलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय बिजली मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे हल्के में 66 के.वी. के दो पावर हाउसिज लगाकर मेरे इलाके को बिजली की समस्या से निजात दिलाने का काम किया है । वहां पर पहले बिजली की काफी दिक्कत थी । हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने जैसे अच्छे कार्य तेजी से कर रही है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे मैडीकल कॉलेज की मांग पिछले दो तीन सत्र से हमारे पलवल के विधायक और होडल के विधायक उठाते आ रहे थे । हमारी इस मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के दौरान मैडीकल कॉलेज की जो घोषणा की है उसके लिए मैं समस्त पलवल जिले के वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय

उपमुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे हथीन विधान क्षेत्र में पुरानी बाई–पास की मांग चली आ रही थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया और आज लगभग 59 करोड़ रुपये की लागत से हथीन बाई–पास बनने जा रहा है। जिसकी टैंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज वहां पर किसानों की थोड़ी फसलें खड़ी हैं। जैसे ही फसलों का उठान होगा उसके बाद हमारे बाई–पास का काम शुरू हो जायेगा। मेरे हथीन क्षेत्र के अंदर लगभग 20 सड़कें 6 करम, 8 करम और 9 करम की हैं। उन सबके टैंडर हो चुके है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लगभग 4–5 रास्ते बचे हैं हम उनके एस्टीमेट्स बनाकर सरकार के पास भिजवा देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो हमारी 4–5 सड़कें और बची हुई हैं। उन सड़कों को भी जल्दी मंजूर किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं। 138 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाये हैं और अब इस बजट सत्र में लगभग 500 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। **(घंटी)** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हथीन की सबसे बड़ी और जरूरी मांग है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। समय का अभाव है और मैंने दो मिनट का समय अपने साथी विधायक को भी अपनी तरफ से दिया था। मेरे पास केवल 8 मिनट का टाइम था। मेरी कुछ मांगे हैं जो हमारे हथीन क्षेत्र की है। मेरे पास अभी डेढ़ मिनट का समय बचा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : डागर जी, आप अपनी स्पीच लिखित में दे दीजिए ताकि उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके।

श्री प्रवीण डागर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हथीन क्षेत्र के किसानों की एक लडमाकी माईनर थी, इस लडमाकी माईनर को पीछे अधूरा छोड़ दिया गया था। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि हमारी इस लडमाकी माईनर को पूरा किया जाये। ईरीगेशन विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया था कि यह लडमाकी माईनर यहीं तक के लिए मंजूर की गई थी। पिछले सरकारों ने अधूरे काम किये हैं, हमारी सरकार का सबसे बड़ा अंतर यही है कि सरकारों के जो काम अधूरे पड़े हुए थे, उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हथीन क्षेत्र के गांव मानपुर में एक डिग्री कॉलेज बनवाया जाये। मेरा खुद का गांव मंडकौला है। उसमें अनाज मंडी का

निर्माण करवाया जाये। मेरे गांव मंडकौला में लगभग 50 एकड़ जमीन हमने पीछे कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए पंचायत की तरफ से दी थी और हमने यह जमीन विदआउट कॉस्ट दी थी। मेरा अनुरोध है कि वहां पर जल्दी से जल्दी कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाये। इसी तरह से हथीन ब्लॉक में 76 पंचायतें हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ब्लॉक हथीन ही हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे गांव मंडकौला को ब्लॉक का दर्जा दिया जाये। इसी तरह से किसानों से जुड़ी हुई एक दो समस्या और हैं। पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई जाये। जो किसानों के गन्ने की पिराई होती है, वह अप्रैल और मई के महीने में होती है। उस समय वहां पर लैबर की बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। हथीन नगरपालिका को 10 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाये और हथीन कस्बे में एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पर सब्जी मंडी नहीं है। जितने भी सब्जी विक्रेता है वे सभी रोड पर बैठे रहते हैं। आये दिन वहां पर वाद विवाद खड़ा हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां पर नगरपालिका की जमीन पर सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करताा हूं। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह (इसराना) (अ.जा.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर आवास योजना का जिक्र किया है। यह योजना इस समय केवल बी.पी.एल. परिवारों के लोगो के लिए है। सरकार की तरफ से उन लोगों को 80 हजार रुपये की राशि मकान की रिपेयर के लिए दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि इस राशि को 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाये। जो व्यक्ति अत्यंत गरीब हैं और वे व्यक्ति बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उन पात्र परिवारों को भी इस स्कीम का लाभ अवश्य दिया जाये। मकान मालिकाना हक का प्रमाण पत्र पंचायत सचिव से तफशीस करवाते हैं और इसके लिए लोगों को दिक्कत होती है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तफशीस का यह काम नम्बरदारों या सरपंचों से कराया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके और यह योजना 10 साल की बजाय 8 साल हो जाए तो बहुत अच्छा है । उपाध्यक्ष महोदय, बजट में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का जिक्र किया गया । इसमें एस.सी. व बी.पी.एल. परिवारों को 71 हजार रूपये मिलते

17:00 बजे

हैं । 71 हजार रूपये में से 66 हजार रूपये तो शादी से पहले मिलते हैं और 5 हजार रूपये शादी के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब मिलते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लगभग लगभग यह मानना है कि 98–99 परसैंट लोग शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और 5 हजार रूपये गरीब आदमी के सरकार के पास ही रह जाते हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वे 71 के 71 हजार रूपये इन गरीब परिवारों को शादी से पहले ही दिए जाएं । उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के तहत चाहे बी.सी. बी.पी.एल. हो, चाहे जनरल बी.पी.एल. हो या कोई भी विधवा जिसके घर कोई कमाने वाला नही रह जाता तो उन्हें भी 71 हजार रूपये अनुदान सरकार को देना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं आते और उनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है उनकी भी अनुदान राशि को 31 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये कर दिया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बेटियां जो खेलों में मैडल जीतकर लाती हैं और जो देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करती हैं उन्हें भी 31 हजार रूपये की बजाय 51 हजार रूपये कन्यादान की राशि सरकार को जरूर देनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राशन कार्डो के बारे में बात रखना चाहूंगा । वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है । लगभग सवा़ वर्ष पहले कार्ड बनाने दो महीने के लिए बंद किए गए थे परंतु आज तक ओ.पी.एच., बी.पी.एल. या ए.ए.वाई. किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं बन रहा है । इनको बनाने के लिए साईट बन्द है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस साईट को जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिए तथा यदि इस साइट के चालू होने में कोई देरी है और जब तक ये कार्ड नहीं बनते तब तक जिन व्यक्तियों की आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है, उन सभी पात्र परिवारों को, सरकार की जो स्कीमें चलाई गई हैं उनका लाभ मिलना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बता रही है कि हमने युवाओं को बहुत सी स्कीमें बनाकर रोजगार देने का काम किया है । जब यहां बजट पढ़ा जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि कितनी स्कीमें बनाकर रोजगार दिए जा रहे हैं ताकि हरियाणा में एक भी पढ़ा–लिखा नौजवान बेरोजगार न हो परंतु मैं बताना और पूछना चाहता हूं कि आज जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहनें हैं और जो युवा बेरोजगार है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हर वर्ष दो करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो क्या आज देश और प्रदेश में 16 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट पढ़ा जा रहा था उस समय इसकी पूरी वाह वाही थी कि कोई भी बेरोजगार युवा नहीं रहेगा। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा नम्बर एक की पोजीशन पर है। आज हरियाणा के पढ़े–लिखे भाई–बहनों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मैं शिक्षा विभाग का उदाहरण देना चाहता हूं। स्कूलों में विभिन्न विषयों के 40 से 60 प्रतिशत अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे हालातों में गरीब परिवारों के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा कैसे मिल सकती है? इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि गरीब आदमी अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का सहारा लेता है क्योंकि वह प्राईवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाने में पूरी तरह से असमर्थ है। शिक्षा विभाग की तरह ही स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के गरीब व्यक्ति को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि प्रदेश के गरीब वर्ग की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी कारगर तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। सरकार काती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रख–रखाव की जिम्मेदारी क्रमशः जिला परिषद् और नगर पालिकाओं को दी जायेगी। यह मुद्दा गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा सरकार ग्रामीण अंचल में स्कूल व स्वास्थ्य सेवा को चलाने में नाकामयाब हो गई है। जब सरकार ही ग्रामीण अंचल में शिक्षा संस्थायें व स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में अपने हाथ खड़े कर गई है तो जिला परिषद् व नगर पालिका कितने समय तक इन संस्थाओं का संचालन कर पायेंगी। इसका सीधा–सीधा मतलब यह हुआ कि सरकार इन संस्थाओं को बंद करना चाहती है। दूसरी बात मैं आवास योजना के बारे में कहना चाहता हूं। बजट में यह पढ़ा गया कि प्रदेश के प्रत्येक गरीब व जरूरतमंद के सिर के ऊपर छत होगी। सरकार ने पहले इस बारे में यह घोषणा की थी कि यह सभी कुछ वर्ष 2022 तक हो जायेगा। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, इस समय वर्ष 2022 ही चल रहा है इसलिए मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभी गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकार की आवास योजना के तहत सिर पर छत की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। मैंने पिछले विधान सभा सैशन में यह प्रश्न लगाया था कि मेरे हल्के इसराना और मेरे हल्के के ब्लॉक

मतलौड़ा में तहसील की बिल्डिंग नहीं है। इसी प्रकार से इन दोनों जगहों पर बस स्टैण्ड भी नहीं है। मेरे इस प्रश्न के जवाब में सरकार के दो मंत्रियों ने मुझे विश्वास दिलाया था कि मेरे हल्के के ये दोनों काम जल्दी से जल्दी किये जायेंगे। उस समय मैंने इन दोनों कामों की कम्पलीशन की समय सीमा के बारे में भी जानना चाहा था। इसके जवाब में मुझे सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाया गया था कि मार्च के अंदर मेरे ये काम पूरे कर दिये जायेंगे। मैंने विधान सभा के दिसम्बर, 2021 में चल रहे सत्र में यह कहा था कि मार्च आने में तीन महीने का समय शेष है लेकिन अभी तक वहां पर एक भी बिल्डिंग की नींव तक नहीं रखी गई है। इस प्रकार के हालात में साढ़े तीन महीने में सरकार कैसे इन बिल्डिंग्स को पूरा कर पायेगी? माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस सदन के अंदर भी जब किसी काम को किये जाने का भरोसा सम्बंधित विधायक को दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी वह काम नहीं होता है तो इस प्रकार की स्थिति में हम सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरी सरकार से यह मांग है कि जब तक मतलौडा में नया बस स्टैण्ड नहीं बन जाता तब तक पुराने बस स्टैण्ड पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण अवश्य करवा दिया जाये और एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति भी कर दी जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह घोषणा की थी कि मेरे हल्के में दोनों जगहों पर नया बस स्टैण्ड बना दिया जायेगा परन्तु इसके बावजूद भी इस दिशा में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री लीला राम (कैथल) : डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया सर्वप्रथम इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। 08 मार्च, 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर हमारी सरकार के इस कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का काम किया। इस बजट में पिछले बजट की तुलना में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट को किसान, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार और गृहिणी सभी के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट में प्रदेश के हित में सभी मदों पर अलग–अलग विचार करके आवश्यक धनराशि का आबंटन करने का काम किया गया है। इस बजट में 132 प्रकार की अलग–अलग योजनाओं पर काम किया गया है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ही इस बजट

को प्रस्तुत किया गया है। हमारी सरकार द्वारा छोटे व्यापारी, महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए स्टैण्ड–अप इंडिया कांसैप्ट के तहत मुद्रा योजना के तहत 2078 करोड़ रूपये के ऋणों की व्यवस्था की गई है। इस बजट के ऊपर सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी माननीय साथियों ने अपने विचार रखे। विपक्ष के माननीय साथियों द्वारा अपनी स्पीच में यह दर्शाने का काम किया गया कि उन्होंने ही अपने समय में हरियाणा प्रदेश का समुचित विकास करने का काम किया था लेकिन हमारी सरकार के समय में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर हम सड़क के मामले को ही लें तो मैं अपने साथी बिशन लाल जी और पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के समय में कुरूक्षेत्र से यमुनानगर और अम्बाला से यमुनानगर जाने में कम से कम तीन–तीन घंटे का समय लगता था परन्तु अब हिसार से चण्डीगढ़ की यात्रा में मात्र अढ़ाई से तीन घंटे लगते हैं। बिशन लाल जी यहां पर बहुत बार प्रदेश में सड़कों की बात करते रहते हैं मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि उनको वास्तविकता के आधार पर बात करनी चाहिए। हमारी सरकार द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में अच्छी से अच्छी सड़कों का जाल बिछाया गया है। चाहे तो नारनौल से अम्बाला हाईवे की बात की जाये या फिर हिसार से चण्डीगढ़ हाईवे की बात की जाये इनका निर्माण हमारी सरकार के समय में ही करवाया गया है। मेरे कैथल जिले में भी तीन–तीन हाईवे या तो बनकर तैयार हो चुके हैं या फिर बनने जा रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कहना पूरी तरह से सच है कि अगर रास्ते और सड़के ठीक होती हैं तभी कोई प्रदेश तरक्की करता है। अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी योजना बनाई कि प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में एक गवर्नमैंट कॉलेज का निर्माण किया जायेगा ताकि हमारी किसी भी बहन और बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े। इतना ही नहीं प्रदेश की शिक्षा प्राप्त करने वाली बहन और बेटियों को कॉलेज से लाने और ले जाने के लिए 500 से 600 बसों की भी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। मेरा यह भी कहना है कि यह अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था है। अगर बिजली की बात की जाये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी रणजीत सिंह जैसे कर्मठ व्यक्ति को बिजली मंत्री का कार्यभार ग्रहण करवाकर एक एतिहासिक कार्य किया है और इसी प्रकार से श्री पी.के. दास जैसे

ईमानदार व कर्त्तव्य परायण अधिकारी को बिजली विभाग का ए.सी.एस. लगाकर प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समय बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने का सराहनीय कार्य किया है। मैंने कांग्रेस की सरकार का समय भी देखा है जब पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार को बिजली के घटिया प्रबन्धन के लिए 24 घंटे कोसने का काम करती थी। आज अगर हम देखें तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समय में जो थर्मल पॉवर प्लांट बने थे उसके अलावा इस सरकार ने अगर एक भी पॉवर प्लांट लगाया हो तो माननीय सदस्य बता दें। आज हमारे थर्मल पॉवर प्लांट बंद पड़े हैं तथा बाहर से महंगी बिजली खरीदी जा रही है जिसका असर उपभोक्ता पर पड़ रहा है।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कोविड–19 और अधिक वर्षा के कारण पिछले साल पूरे देश के थर्मल पॉवर प्लांटों में कोयले की भारी कमी देखी गई थी लेकिन हरियाणा पहला राज्य था जहां पर हमने कोयले की कोई कमी नहीं होने दी बल्कि हमने तो थर्मल पॉवर प्लांट्स में ऑक्सीजन का भी उत्पादन किया है। जहां तक थर्मल पॉवर प्लांट की यूनिट बंद करने की बात है तो उसका कारण यह है कि थर्मल को एक बार चला दो तो तीन महीने चलता है और इसके मुकाबले सोलर पॉवर हमें सस्ती पड़ती है इसलिए स्टेट की इकॉनोमी के हिसाब से चलना पड़ता है।

श्री लीला रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सम्मानित बहन गीता भुक्कल जो कि पूर्व मंत्री भी रही हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा में बिजली 24 घंटे ही नहीं मिल रही बल्कि आधे रेट पर देने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। यह एक व्यवस्था होती है और हरेक का काम करने का अपना तरीका होता है। यहां सदन में किसानों की चर्चा हो रही थी तब मैं सुन रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस राज में जब किसानों की जमीन एक्वायर की जाती थी तो बहुत सस्ते रेट पर एक्वायर की जाती थी और किसानों को अपनी जमीन का पूरा रेट प्राप्त करने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। उस समय जिस उपजाऊ जमीन पर 100 मन जीरी और 60 मन गेहूं पैदा होता था उस जमीन को एक्वायर करने के लिए 5–6 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाता था। आज ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अगर कहीं पर नैशनल हाईवे बनना हो, स्कूल या कॉलेज बनना हो तो किसान अपने आप सरकार के पास आता है कि मेरी जमीन

एक्वायर कर लें क्योंकि सरकार ने किसानों की जमीनों के दोगुने और तीन गुणा रेट्स देने का काम किया है। इसी प्रकार से अगर किसानों की खराब फसलों की बात की जाये तो एक–एक सीजन में 12–12 सौ करोड़ रुपये का मुआवजा सीधे किसानों के खाते में डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जब नौकरियों की बात आई तो विपक्ष की तरफ से बड़े–बड़े दावे किये गये परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई कि मैरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। कांग्रेस का राज भी सभी ने देखा है। जब भी कोई वैकेंसी आती थी तो नौकरियों के लिए बोली लगती थी। एक–एक मंत्री और एम.एल.ए. के घर पर नौकरियां पाने वालों के मेले लगते थे और 500–500 कैंडिडेट्स से पैसे ले लिये जाते थे और जब सिलैक्शन नहीं होता था तो वापिस कर देते थे। यहां पर गवर्नर एड्रैस पर चर्चा के दौरान हमारे कांग्रेस के एक सम्मानित साथी बोल रहे थे कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि ये घोटाले क्यों होते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, उनको इस बात को थोड़ा सा गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इन घपलों, घोटालों और क्रप्शन की जननी कौन है? मैं यह बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं वे सभी कांग्रेस राज में ही हुए हैं और आज ये यहां सदन में पाक साफ बन कर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम जनता के बड़े शुभचिन्तक हैं। आज अगर इतिहास उठा कर देखने लग जायेंगे तो पता चलेगा कि सारे बड़े घोटाले कांग्रेस राज में हुए हैं। अगर उनके नाम लेने लग जायें तो उनकी बहुत लम्बी लिस्ट है। अगर जमीन घोटाले की बात की जाये तो हमारी पूर्व मंत्री बोल कर चली गई और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र हुड्डा जी भी जमीन घोटाले की बात पर तिलमिला उठे थे और मंत्री जी से कह उठे कि कोई एक–दो एकड़ जमीन ही बता दो। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक–दो एकड़ नहीं बल्कि 68 से 72 हजार एकड़ जमीन किसानों से कोड़ियों के भाव लेकर बड़े–बड़े ग्रुप्स टाटा, बिड़ला, टी.डी.आई., ओमैक्स, पार्श्वनाथ तथा सुशान्त सिटी को दी गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी सदन में उपस्थित हैं, यह भी अच्छी बात है। बजट की किताब में पेज न. 61 और पैरा नम्बर 243 मे दर्शाया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर

नगरपालिकाओं में बुनियादी नागरिक सुविधायें प्रदान करने और वित्तीय रूप से सशक्त होने तक तथा शहरी स्थानीय निकायों में विकास प्रभावित न हो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास कोष से परिव्यय प्रदान किया जायेगा। यह वास्तव में बड़ी अच्छी बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज न हो तो मैं सदन के माध्यम से उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उनको किसने सलाह दी थी कि रादौर की पंचायत को तोड़कर नगर पालिका बना दिया जाये। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं का कोई भाई होगा जिसने ऐसा करने के लिए कहा होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपको इस बारे में कुछ कहा नहीं है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य ने नहीं कहा होगा तो इनके किसी भाई ने कहा होगा। कहा जो जरूर गया होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, रादौर को नगरपालिका बनाने के बाद यहां पर मेरे टाइम में एक खोटा पैसा भी डिवैलपमैंट के कार्यों पर खर्च नहीं किया गया है और जिस तरह का बजट अब पेश किया गया है, उसमें भी मुझे कही नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र के लिए कुछ बजटीय प्रावधान किया गया हो (विघ्न)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसका उत्तर देने के लिए मुझे अपनी बात कहनी जरूरी हो गई है । जो बजट होता है, वह अगले वर्ष के लिए होता है। जैसाकि अब मार्च के महीने में बजट के माध्यम से कमजोर नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान देने की बात कही गई है, यह बात 01 अप्रैल, 2022 से इंप्लीमैंट होनी शुरू हो जायेगी। अगर किसी बजट में कोई बात कही गई है तो सीधी सी बात है कि वह बात पिछले साल के बजट में कही गई होगी। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह बात माननीय सदस्य को देखने की जरूरत नहीं है और केवल इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि बजट में जो कुछ कहा जाता है वह अगले वर्ष के लिए ही कहा जाता है। अब माननीय सदस्य को सब कुछ क्लीयर हो गया होगा।

श्री बिशन लालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब बातें क्लीयर कर दी अतः मैंने जो बात कहीं है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ लेकिन मैं

मुख्यमंत्री महोदय की तारीफ भी करना चाहूंगा क्योंकि इनके द्वारा मेरे हलके में बहुत से काम भी करवाये गए हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं हैं। मेरे एरिया में डिवैलपमैंट हुई है लेकिन मेरे टाइम में यहां पर कुछ नहीं किया गया है। पता नहीं सरकार को मेरे से क्या खुंदक है और जो बातें मैंने अभी सदन में कही थी, वे बातें मैंने इन्हीं बातों को आधार बनाकर कही थी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मेरे समय में भी यहां पर डिवैलपमैंट का काम करवा दें तो यह बहुत अच्छा कदम साबित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार "सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास" की अवधारणा को मूर्त रूप देने की भावना पर काम करने वाली सरकार है। अतः इस अवधारणा पर काम करते हुए मेरे टाइम में भी मेरे एरिया में डिवैलपमैंट कराने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर आना चाहूंगा। सरकार द्वारा किसान खेत सड़क योजना बनाई गई है। यह बहुत अच्छी योजना है और इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती है। एक विधान सभा क्षेत्र के अंदर 25 किलोमीटर तक खेतों के रास्तों को खड़ोंजे लगाकर पक्का करने की जो यह योजना है, इस योजना को नगरपालिका और नगर निगम के एरिया में भी शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि यहां रहने वाले लोगों के भी अपने खेत हैं, खलिहान हैं और रास्ते हैं, अतः ऐसे लोगों को इस योजना से वंचित करने का काम सरकार के द्वारा न किया जाये और तुरंत प्रभाव से यहां इन एरियाज में भी किसान खेत सड़क योजना लागू कर दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बुढ़ापा पैंशन पर बात करना चाहूंगा। एक साथी अभी बुढ़ापा पैंशन के बारे में बात कर रहे थे। निश्चित रूप से यह अच्छी स्कीम है। यह बुढ़ापा पैशन चौधरी देवी लाल जी ने शुरू की थी और इसलिए शुरू की थी ताकि बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे और इसके लिए कोई शर्त भी नहीं रखी गई थी। मैं सदन के दूसरे सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई शर्त रखी गई थी ? सिर्फ एक उम्र की शर्त थी कि उम्र 60 साल होनी चाहिए और कोई शर्त नहीं थी। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, 1991 के समय में भी शर्त रखी गई थी। माननीय सदस्य रिकार्ड निकालकर देख लें। उस समय भी आमदनी की शर्त हुआ करती थी।

श्री बिशन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई गरीब हो कोई अमीर हो चाहे कोई 50 एकड़ का मालिक हो या 10 एकड़ जमीन का मालिक हो लेकिन बुजुर्गों की पैंशन काटने का काम नहीं होना चाहिए। अब जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र को

बजुर्गों की पैंशन के साथ जोड़कर पैंशन काटने का काम किया जा रहा है यह मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है क्योंकि बुजुर्ग सबके एक बराबर होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बच्चे तो सबके होते हैं हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के तो बच्चे नहीं है।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सारे समाज के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं।

श्री बिशन लालः उपाध्यक्ष महोदय, ये बच्चे अपने बुजुर्गों की कोई देखभाल नहीं करते हैं। (विघ्न) घर में एक बुजुर्ग है और उसकी पैर–टांगों में दर्द है तो उसकी दवाई चलती है, किसी बुजुर्ग को आस्थमा की बीमारी है तो उसकी आस्थमा की दवाई चलती है या फिर किसी को कोई अन्य बीमारी है तो उसकी बीमारी की दवाई चलती है। यदि उसके लिये बुजुर्ग अपने बच्चे की घरवाली से दवाई के लिये पैसे मांग ले तो वह सौ ताने मारती है। मेरे ख्याल से समाज में ऐसे भी आदमी हैं जो मर जायेंगे लेकिन दोबारा से पैसे नहीं मांगेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इसलिए इस शर्त को हटाकर इसका समाधान करना चाहिए अर्थात् सबकी पेंशन दोबारा से लागू करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक कॉओपरेटिव सोसायटी का मामला था, इसके लिये मैं पर्सनली तौर पर संबंधित मंत्री जी के कार्यालय में जाकर उनसे मिला भी था। हमारी मुस्तफाबाद में एक सोसायटी है, उसमें छोटे–बड़े लगभग 6500 किसान हैं। इस बारे में माननीय संबंधित मंत्री जी ने कहा कि लिखकर मुझे दे दें। लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक साल तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। पूरे स्टेट में दो ही सोसायटीज हैं, एक सोसायटी केसरी के अंदर और दूसरी मुस्तफाबाद के अंदर है। ये दोनों सोसायटीज बैंक से लिंकड हैं। कोई भी फायदा सोसायटी को देते हैं तो उन किसानों को नहीं मिलता है। इस प्रकार से न तो कोई फायदा मुस्तफाबाद वाली सोसायटी को मिलता है और न ही केसरी वाली सोसायटी को मिलता है। वहां हमारा किसान अल्प अवधि के लिये 7 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देता है, इसी तरह से केसरी सोसायटी का हाल है। यदि कोई किसान डिफॉल्टर हो जाता है तो वह 12 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देता है। मुझे यह भी पता है कि अल्प अवधि के लिये जीरो प्रतिशत पर ब्याज होता है और यहां पर 7 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में चाहे सत्ता के या विपक्ष के विधायक बैठे हैं, उनके हल्कों की सड़कों की बहुत बुरी हालत है। (विघ्न) उपाध्यक्ष

महोदय, जिन विधायकों के हल्कों की सड़कें ठीक हैं, उनको छोड़ दो और जिन विधायकों के हल्कों की सड़कों की बुरी हालत हैं, उनको बना दिया जाये। माननीय एक सदस्य जो पहले इनैलो पार्टी में मेरे साथ रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। सड़कों का जाल तो चौटाला साहब की सरकार में बिछा था। यह सरकार तो सड़कों की रिपेयर भी नहीं कर पा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि सड़कों की रिपेयर जरूर से जरूर करवा दें क्योंकि प्रदेश में हर रोज सड़क दुर्घटनाओं के कारण काफी संख्या में मौतें हो रही हैं। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर जो चारमार्गीय सड़क हैं, कुरूक्षेत्र से यमुनानगर जो सहारनपुर को जाती है, उसकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, पटियाला से यमुनानगर नैशनल हाइवे घोषित कर दिया गया है।

श्री बिशन लालः उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः सैनी साहब, प्लीज अब आप बैठ जाईये। इसके अतिरिक्त आपकी कोई बात रही गयी है तो उसके बारे में लिखित में दे दें। वह रिकार्ड पर आ जाएगी।

श्री बिशन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो काम ठीक किया है, उसको ठीक बताएंगे। माननीय मंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं। मैं इनके खनन विभाग से संबंधित मामला भी उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः सैनी साहब, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बिशन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने का समय बाकी है। चूंकि मुझे अभी और बातें रखनी हैं, इसलिए मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः सैनी साहब, आपको पहले ही अपनी बात रखने के लिए बहुत समय दिया जा चुका है। आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब श्रीमती सीमा त्रिखा जी अपनी बात रखेंगी।

श्री बिशन लालः उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं खनन के विषय में कहना चाहूंगा कि हमारे एरिया में मनमर्जी से खनन का कार्य किया जा रहा है और 20–20 फुट नीचे तक खुदाई की जा रही है। सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी

भी बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या वहां पर गैर कानूनी खनन हो रहा है या नहीं ? मैं इनकी बात को ही सही मान लूंगा।

श्री उपाध्यक्षः सैनी साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद। वर्तमान में हरियाणा सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी के रूप में बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें मैं सोचती हूँ कि यह बजट हर घर में खुशहाली को दस्तक देता है। जब वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसके नेतृत्व को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने संभाला था और तब से लेकर आज तक हर रोज ही हरियाणा प्रदेश की सूरत बदल रही है। वे एक विश्वास और एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़े थे, उसमें मैं दो बिन्दू मुख्य मानती हूँ। जिसमें पहला ट्रांसपैरेंसी और दूसरा सबको समानता का अधिकार देना है। मैं सोचती हूँ कि इन दोनों चीजों में सरकार बहुत हद तक अपने लक्ष्य में सही साबित हुई है। हरियाणा सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी आयी हैं जिन पॉलिसीज को पूरे देश में अपनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पी0पी0पी0 (परिवार पहचान पत्र) का मॉडल लेकर आये हैं और शायद यह हरियाणा प्रदेश को एक नया आयाम और एक नई सूरत देने वाला है। इसके साथ ही मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि जो 1,20,000 रुपये से बढाकर 1,80,000 रुपये की आय सीमा निर्धारित की है, उसमें लाभार्थियों को अधिक फैसिलिटीज दी जाएंगी। मैं सोचती हूँ कि इससे हरियाणा प्रदेश के लाखों परिवार अधिक से अधिक संबंधित सुविधाओं का लाभ उठा सकेगें। जब वर्ष 2019 में यह सरकार बनी तो उससे अगले दो वर्ष क्रमशः वर्ष 2020 और वर्ष 2021 पूरे देश के लिए ही बहुत बड़े चैलेंजिंग वर्ष रहे। इन वर्षों के दौरान कोविड–19 की पीड़ा को पूरी दुनिया ने भोगा है लेकिन आज इस सदन में इस बात को कहने में मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पहले 20 सिटीज को चुना गया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी बैस्ट सेवाएं दी। मुझे इस बात को बताते हुए हर्ष महसूस होता है कि हरियाणा प्रदेश में पहले नंबर पर आने वाले सिटी का नाम फरीदाबाद है और दूसरे नंबर पर आने वाले सिटी का नाम गुरुग्राम है। मैं यह सोचती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रशासन ने जो काम किया है, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। इसके साथ–

साथ फरीदाबाद की वो तमाम संस्थाएं व आम जनमानस मेरी तरफ से आभार के लायक हैं। मैंने उस कोरोना काल में अपनी 80–80 साल की माताओं/बड़े– बुर्जर्गों को किसी संस्था में, किसी मंदिर में या किसी गुरूद्वारे में रोटी बेलते हुए और दाल देते हुए देखा है जिसके कारण फरीदाबाद नंबर 01 आया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि आज तक न्यूज चैनल का भी एक सर्वे हुआ था और उसमें हमारे फरीदाबाद जिले के प्रशासन को सम्मानित किया गया था। आज तक न्यूज चैनल के सर्वे में कोरोना सर्विसिज में भी फरीदाबाद नंबर 01 पर रहा। कोरोना ने जहाँ हमें बहुत सारे चैलेंजिज दिए तो उसके साथ हमें सॉल्यूशन की तरफ भी लेकर गया है। जितनी जल्दी हरियाणा प्रदेश ने वैक्शीनेशन के कार्य को कवर किया, वह भी काबिले तारीफ है। इसका सारा श्रेय भारत **के** वैज्ञानिकों को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसके साथ–साथ कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहूंगी कि मेरी अपनी विधान सभा में 8 गाँव लगते हैं और उनमें से 7 गाँव गुर्जर समाज के हैं। आज बदलते समय के साथ सभी समाज पढ़ाई को बड़ा महत्व दे रहे हैं और युवा बच्चे पढ़–लिखकर के आगे पहुंच रहे हैं। मेरी उनके साथ भी चर्चा होती है और मेरे बड़े बुर्जुगों की बात भी मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगी कि हमारे युवा गुर्जर समाज के युवा साथी और बड़े बुर्जुर्गों की एक दरखास्त है कि इस सदन की तरफ से गुर्जर रैजिमैंट बनाने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी जाये ताकि उन बच्चों और नौजवानों को अपनी हकदारी निभाने का सुअवसर प्राप्त हो। मैं इसके साथ–साथ यह और जोडना चाहूंगी कि इन 8 गाँवों में कोई न कोई हुड्डा का सैक्टर कटा है। हम आज के समय में इसको एच. एस.वी.पी. का सैक्टर बोलेंगे। जब ये सैक्टर काटे गये थे तो एक कानून है कि जिस गाँव की जमीन पर सैक्टर काटेंगे, उसमें पूरी तरह से बेसिक एमैनिटिज डिवैलप करके देंगे। यानि उन सैक्टर्ज सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। पीने का पानी, सीवरेज, स्कूल, डिस्पैंसरीज के साथ–साथ कम्युनिटी सैन्टर और लाईट्स की व्यवस्था भी करवाई जायेगी। हमें सात साल आये हो गये हैं, लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं पीछे किन कारणों से ये चीजें छूट गयी। मेरे इन 8 गाँवों में से फतेहपुर गाँव, स्मार्ट गाँव बनकर तैयार हो रहा है जिसका काम चल रहा है। इसके साथ–साथ अनखीर और मेवला गांवों में अमृत–2 योजना के तहत काम चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि इनके अतिरिक्त भाखड़ी, नवादा, अन्नतपुर, और लकड़पुर गांव बाकी

बचते हैं। इनके साथ ही साथ लगभग 2,50,000 की आबादी का एक एसजीएम नगर है। मेरी दरखास्त है कि इन सभी को अमृत–2 स्कीम में शामिल किया जाए। चूंकि फरीदाबाद एक ऐसा स्थान है, जिसको हम डार्क जोन कहते हैं। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि मैं जब सन् 2014 में विधायक बनीं तो नवंबर, 2014 में मुझे इसी महान् सदन में अपनी बात रखने का पहला मौका मिला था। उस पहले मौके में मैंने 4 विषय उठाए थे, जिसमें एक विषय यह था कि फरीदाबाद को एक यूनिवर्सिटी दी जाए। दूसरा विषय यह था कि मेरे यहां पर एक इंडस्ट्री की मदर यूनिट लगायी जाए। तीसरा विषय यह था कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती हूं वहां पर फरीदाबाद का लगभग 53 प्रतिशत स्लम और अनएप्रूव्ड कॉलोनीज का बहुत बड़ा एरिया आता है। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है, अगर हम उन लोगों के लिए मकान की व्यवस्था करवा दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसी के साथ मेरा चौथा विषय बड़खल झील को पानी से भरने का था। जिसको सूखे हुए 28 साल से ज्यादा का समय हो गया था। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस काम में भी तेजी आई है और वह झील आगे की तरफ बढ रही है। इसके लिए विशेष तौर से हमारे अधिकारीगण श्री अमित अग्रवाल जी, श्रीमती जी अनुपमा जी और श्रीमती गरिमा मितल जी का विशेष प्रयास रहा। स्मार्ट सिटी के काम को श्रीमती गरिमा मितल जी देखती हैं। मेरी विधान सभा के एक–दो विषय और हैं। जिनमें एक गुरूकुल और लकड़पुर गांव का अंडरपास या फ्लाई ओवर बनवाना चाहती हूं। यह डिपार्टमैंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वे हमारे जिले के ग्रिवैंसिज कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। मैं चाहती हूं कि वे इन कार्यों को जल्द से जल्द करवायें। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जे.सी. बोस यूनिवर्सिटी के लिए भाखड़ी गांव की जमीन प्रशासन को देकर फाईनल कर दी गई है लेकिन हम लोग अपने प्रदेश के मुखिया को जितना देखते और समझते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के पद्चिन्हों पर चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि जिसका फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, उसको अपने हाथों से जनता को समर्पित भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित भी अपने हाथों से करें। मैं इसी भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहती हूं कि वे जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखें ताकि

हम इसी कार्यकाल में उसे जनता को समर्पित कर सकें। मैं इसके साथ कुछ और चीजें जोड़ना चाहती हूं जैसे कि मॉडल संस्कृति स्कूल्ज हैं। इन स्कूल्ज की वजह से जनता का हमारी तरफ विश्वास व रूझान और अधिक बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि हमारे सरकारी स्कूल्ज में लगभग 3 लाख से अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया है। सरकारी स्कूल्ज में बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मांग करना चाहती हूं कि मेरे एसजीएम नगर में लगभग 2 लाख की जनसंख्या है, इसलिए वहां पर 10+2 तक का को– एड स्कूल बनना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी कृप्या करके इसे ध्यान में रखें और इसे पूरा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ–साथ एक चीज यूक्रेन के छात्रों के बारे में भी बोलना चाहती हूं, जोकि सबके लिए बहुत ज्वलंत विषय है। हम लोगों ने देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्योंकि जब नैया डूबने लगती है तो हर व्यक्ति नेतृत्व पर सवाल उठाता है लेकिन जब नैया तैरती है तब भी हमें शुक्राने की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं सोचती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जितना हम धन्यवाद करेंगे, उतना ही कम है। अगर मैं इस सदन में यह बात करूं तो मैं समझती हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उन बच्चों की माताओं और परिवारजनों से पूछा जाये तो वे अपने घरों में बैठे हुए भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को 100–100 बार आर्शीवाद देते हैं परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी बात सदन में रखना चाहती हूं कि हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यह इतना बड़ा चैलेंज है कि मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के शहर में इन बच्चों के घरों में गई और मेरा इन बच्चों के घरों में जाने का मकसद यह था कि मैं इन बच्चों से जाकर यह पूछुं कि आप यूक्रेन क्यों गये थे? मुझे इस बारे में एक बार पता तो चले कि, जब हमारा देश शिक्षा के मामले में इतना तरक्की कर रहा है तो फिर ये बच्चे यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए क्यों गये तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिकतर लोगों से यही जवाब सुनने को मिला। उन बच्चों ने मुझे एक जवाब यह दिया था कि यूक्रेन में 17 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये के बीच में एम.बी. बी.एस. हो जाती है और उनका दूसरा जवाब यह था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं करना चाहती हूं। हम लोग जात–पात से ऊपर उठकर 36 बिरादरी और समुचित देश को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। मैं एक महिला हूं, मां हूं और एक बेटी भी हूं। मैं सोचती हूं कि शायद भगवान की एक

यही कीर्ति ऐसी है, जो जात–पात के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर यह बात केन्द्र सरकार तक पहुंचाई जाये। यहां से जब हमारे बच्चे पैसे के अभाव में यूक्रेन पढ़ने जा रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नारा यही है कि चुनौती में से अवसर और समाधान कैसे निकालना है। उन बच्चों ने मुझे दूसरी बड़ी वजह यह बताई कि हम लोग रिजर्वेशन से बाहर के कोटे में आ गये हैं तो मैं सदन को यह बात ध्यान दिलाना चाहती हूं कि ये जो बाहर के बच्चे हैं ये कहीं माइनोरटी में आकर न शामिल हो जाये। मेरे कहने का मतलब यही है कि हम बच्चे की काबिलियत को महत्व दें। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।

श्री चिरंजीव राव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश पर 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है और जो अनुमान लगाया गया है कि हमारे ऊपर 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो जायेगा। इस हिसाब से वर्ष 1966 से वर्ष 2014 तक करीबन 48 साल के अंदर हमारा जो कुल कर्ज 70 हजार करोड़ रुपये था। आप देखिये और पिछले 7 सालों में इन्होंने उसको बढ़ाकर 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और इस प्रदेश सरकार ने हमारे प्रदेश पर कर दिया है। अब आप यह बताईये कि हमें तो पिछले 3 बार का बजट तो मैंने ही पढ़ लिया। मैं तीनों वर्षों की बजट के अभिभाषण की कॉपी भी अपने साथ लेकर आया हूं। हमें चार दिन इस बजट को पढ़ने के लिए मिले थे तो मैंने इस बजट को पढ़ने की बहुत कोशिश की कि हमारे जिले का नाम इस बजट में मिल जाये। बड़े अफसोस की बात है कि रेवाड़ी जिले का नाम इस पूरे बजट में दिखाई नहीं दिया। क्या रेवाड़ी जिला क्या इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? आज से 2 साल पहले भी जब बजट पेश किया गया था तब उसमें एम्स की बात कही गई थी लेकिन इस बार के बजट में एम्स की कोई चर्चा नहीं की गई है। हमें यह बता दें कि वह एम्स बनेगा या नहीं बनेगा?

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एम्स बनेगा।

श्री चिरंजीव राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही पूछा है कि एम्स बनेगा या नहीं लेकिन ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वर्ष 2015 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एम्स बनेगा लेकिन 7 साल बीत चुके हैं एम्स के नाम पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई है।

डॉ. बनवारी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का माननीय सदस्य को भी पता है कि एम्स को लेकर जमीन का भी कुछ इशू था और वह अब सोल्व हो गया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एम्स बनेगा।

श्री चिरंजीव राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे ज्यादा अतिउत्साहित न हों क्योंकि चार राज्यों का परिणाम आया है उसको लेकर अतिउत्साहित हो चुके हैं परन्तु यह हरियाणा प्रदेश की जनता है और यह सब देख रही है कि महंगाई के अंदर सरकार ने इस प्रदेश को नम्बर–वन कर दिया है। भ्रष्टाचार के अंदर इस सरकार ने इस प्रदेश को नम्बर–वन कर दिया है और बेरोजगारी के अंदर सरकार ने इस प्रदेश को नम्बर–वन कर दिया है। चाहे डीजल और पैट्रोल के दाम देख लो। अस्पतालों की जो हालत है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रदेश के अंदर नशे का जो कारोबार है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज के बाद जो भी बच्चा पैदा होगा उस हर बच्चे पर 85000 रुपये का कर्ज होगा। अब ऐसे हालात में सरकार यह बतायें कि उन आने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सरकार उस बच्चे को कर्जवान बना रही है। इस सरकार के कार्यकाल का तीन साल का समय तो बीत चुका है और दो साल का समय सरकार के पास और बचा हुआ है। मुझे आप लोगों का भविष्य भी ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है । हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर जिले में मैडीकल कालेज खोलेंगे लेकिन रिवाड़ी में न तो कालेज खोला गया है और एम्स की बात भी इसमें नहीं हुई है । बस स्टैंड की बात हुई थी, माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि रिवाड़ी और धारूहेड़ा का बस स्टैंड कब बनेगा । इन्होंने घोषणा की थी कि एक साल के अंदर इनका काम चालू हो जाएगा लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं और उनका काम अभी तक भी शुरू नहीं हुआ है । खेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि

हमारा जो राव तुलाराम स्टेडियम है उसके लिए एथलैटिक ट्रैक के लिए पिछले दो साल से हर बार टैण्डर निकलता रहता है लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है । शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं इनके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी यूनीवर्सिटी दक्षिणी हरियाणा के अंदर है । इंदिरा जी के नाम से इस यूनीवर्सिटी को बनाया गया था । उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है । पिछली बार का जो सरकार का बजट था उसमें उसके लिए आप लोगों ने पैसा दिया लेकिन अब की बार उसके लिए कोई चर्चा नहीं की गई है । जो आपका पहला बजट आया था उसके अंदर 63 पन्ने थे फिर 68 और अब की बार 74 पन्ने हैं । पन्ने तो बजट के बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जमीन पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है । मैं तो यही कहूंगा कि आपको प्रदेश की जनता ने काम करने के लिए बनाया था पर काम करने की बजाय मुझे लगता है कि आपका ध्यान लूट और खसोट में ज्यादा रहता है इसलिए आप इस तरफ ध्यान दें । इस गठबंधन की सरकार के हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि बुढ़ापा पैंशन 5100 रूपये करेंगे । ये चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं, मुझे पता है कि उन्होंने ही यह बुढ़ापा पैंशन शुरू की थी । ये पैंशन तो सम्मान के रूप में दी गई थी । मुझे लगता है उनको अपना वायदा याद करना चाहिए लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है । अब की बार मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोग चौधरी देवीलाल जी के परिवार से यहां आए हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को भी इसके लिए सहयोग करना चाहिए ताकि सरकार यह बुढ़ापा पैंशन 5100 रूपये करने का काम करे । उपाध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि एक नारा गरीबी खत्म करने का था लेकिन इस सरकार का नारा दूसरा है कि गरीबी खत्म न करते हुए गरीब को ही खत्म कर दो ताकि उसके लिए कुछ करना ही न पड़े । अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाते कहीं कि इस बजट में न एस.सी. की चर्चा की गई और न बी.सी. की चर्चा हुई, क्या हम लोगों के बारे में सोचना आप लोगों का हक नहीं है। आप लोग इनके नाम पर वोट तो मांग लेते हो लेकिन इनके लिए करते कुछ नहीं हो । यह प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है कि आप लोगों की सच्चाई क्या है और आप लोगों के चेहरे उजागर होते जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के बारे में कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और इस बारे में बहुत सारे लोगों ने भी अपनी बात रखी लेकिन किसानों की हालत तो यह हो गई है कि उसको समय पर खाद नहीं मिलती और मिलती है तो उसके लिए लम्बी–लम्बी

लाइनें लगती हैं और उसके बाद आखिर में उनके उपर लाठियां बरसाई जाती हैं । ये किस प्रकार उनकी आय को दोगुनी करेंगे । आज किसानों की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए । सरकार ने जो इतने बड़े–बड़े वायदे किए हैं उनको पूरा भी करना चाहिए । सरकार ने हाउसिंग फार ऑल कहा था । हर गरीब को छत देने की बात कही गई थी लेकिन मुझे लगता है कि आज तक किसी गरीब को छत नसीब नहीं हुई है । इस बारे में भी सरकार को देखना चाहिए । आज बिजली की हालत प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है । बिजली मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत सारी ढाणियां ऐसी हैं जिनके पास बिजली नहीं पहुंची है । खेल मंत्री जी, आपके संज्ञान में भी मैं एक बात लाना चाहूंगा कि पिछली बार 1100 स्पोर्टस नर्सरीज खोलने की बात आपने कही थी । यह बात फिर से अब की बार रिपीट हो गई है इसलिए आप बता दीजिए कि वे नर्सरीज खुली हैं या नहीं खुली हैं या दोबारा उसको रिपीट कर दिया गया है । बिजली मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप हर ढाणी तक लाइट पहुंचाने का काम करें ।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि पहले ढाणियों में बिजली नहीं थी लेकिन अब पैट ट्रांसफार्मर्ज आए हैं इसलिए अब सब ढाणियों में पहले से ज्यादा काम हुए हैं इसलिए राव साहब आप जो बोलें वह फैक्टस पर ही बोलें ।

श्री चिंरजीव रावः मंत्री जी, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे । रोजगार के मामले में 75 परसैंट आरक्षण देने की बात कही गई थी । आज आप देखिए बेरोजगारी के मामले में हमारा हरियाणा नम्बर एक पर है । हमारे मुख्यमंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नौकरियों में 75 परसैंट आरक्षण का बिल लाए थे । मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 75 परसैंट आरक्षण इस प्रदेश के युवाओं को मिल गया है । पूरा प्रदेश आज आप लोगों की तरफ देख रहा है । ड्रग्स की जो समस्या है वह इस हरियाणा प्रदेश में पंजाब से भी ज्यादा है और हालत पंजाब से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं ड्रग्स और ओलावृष्टि के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आया था। पिछले दिनों भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण हमारे एरिया में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। उसकी गिरदावरी करवाकर किसानों को सही तरीके से मुआवजा दिया जाये। अब तो

किसानों की फसल भी कट चुकी है। उसकी सही तरीके से जानकारी लेकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन हरियाणा में अपराध भी बहुत बढ़ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन प्रदेश में हत्या, रेप, डकेती न होती हो। सरकार ने बड़ी अच्छी शुरूआत डायल 112 की थी और सोचा था कि इसकी शुरूआत से प्रदेश में बदलाव आयेगा लेकिन पहले दिन जैसा श्री वरूण चौधरी जी ने कहा उस पर 7 लाख कॉल आयी । इससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रदेश में अपराध किस सीमा तक बढ़ा हुआ है। आज प्रदेश में आये दिन बहन–बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं इसलिए कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी बैठें हुए हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने सैक्टर–20 रिवाड़ी में लड़कों का कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। वह घोषणा ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। सरकार द्वारा कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर पर सरकारी कॉलेज खोले जायेंगे इसलिए उसकी तरफ शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी रिवाड़ी जिले के क्षेत्र में आता है। इस बारे में दो साल पहले जवाब मिला था यह गंदा पानी रिवाड़ी जिले की तरफ नहीं आयेगा। दो साल बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए इसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य सभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा जी ने संसद में अहीर रेजीमैंट बनाने का मुद्दा उठाया था। मैं यहां मांग करता हूं कि सदन द्वारा प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाये कि देश के लिए अहीर रेजीमैंट बनाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में बहुत सारे लोग धरने पर बैठें हुए हैं, चाहे वे आंगनबाड़ी वर्कर्ज हैं या दूसरे लोग बैठे हैं उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाला जाये। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर रखा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे कोई वर्ग अछूता रह गया हो यानी हर वर्ग के लिए यह बजट कल्याणकारी साबित होगा। मेरे मित्र चौधरी लीला राम जी ने बिजली की बात की थी। मैं भी कहना चाहूंगा कि आज से पहले लोग वोट लेने के लिए 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया करते थे। उनकी सरकार भी आई लेकिन वोट

लेने के बाद वे लोग 24 घंटे बिजली नहीं दे पाये पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता के आधार पर हरियाणा प्रदेश में ''मेरा गांव, जगमग गांव'' योजना के माध्यम से 5570 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया गया है। मैं डिटेल देख रहा था इसमें 10 जिले कवर होते हैं। वर्ष 2022–23 में बचे हुए जिले भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और वहां 24 घंटे बिजली सरकार द्वारा दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल के पैंडिंग कनैक्शंज के बारे में भी यहां बार–बार विषय उठाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि ट्यूबवैल के पैंडिंग कनैक्शंज मेरे इलाके में दिये गये हैं और दिसम्बर, 18 तक प्रदेश में 21 हजार कनैक्शन जारी कर दिये गये हैं। मैं सरकार से यही अर्ज करना चाहूंगा कि किसानों ने अब तक ट्यूबवैल के जितने कनैक्शन एप्लाई किये हैं उनको जल्दी से जल्दी देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसी तरह से हाल ही के वर्षों में किये गये बिजली के सुधारों में वाणिज्य घाटे में निरंतर गिरावट के कारण भारत की रैंकिंग के आधार पर डी.एच.वी.पी.एन. को A+ श्रेणी की रैंकिंग का सम्मान मिला है और बिजली वितरण लिमिटिड को A श्रेणी का सातवां स्थान मिला है। तीन वर्ष पहले यह 24 वां स्थान था। आज कितनी तेजी से व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यह उसी के कारण संभव हो पाया है। आज पंचायती राज को ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके प्रतिनिधियों को अधिकारियों की ए.सी.आर. लिखने का कार्य दिया है । ऐसा करके जिला परिषद पंचायती राज को ताकत देने का काम किया है। मेरा एक सुझाव है कि हमारा मार्केटिंग बोर्ड चार और पांच करम के रास्ते प्रदेश में बनाता था। यह पावर उन्हीं के पास रहनी चाहिये क्योंकि इनके पास सभी मशीनरी और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को ताकतवर बनाना अच्छी बात है लेकिन यदि पांच करम के रास्ते जिला परिषद में चले गये तो काम में विलंब हो जायेगा और इसमें काफी समय लगेगा। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।**) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह पांच करम के रास्ते बनाने की पावर मार्केटिंग बोर्ड के पास ही रहनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि झाड़ली में एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजना लगी हुई है। उसके लिए इस्तेमाल कोयले को जिस पानी से धोया जाता है उससे आस–पास के गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। उसके द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़े गये पानी के कारण आस–पास के गांवों में सेम की समस्या पैदा हो गई है। झाड़ली, गोरिया, लिलोड़, सुधराणा आदि गांव में बहुत ज्यादा सेम की

समस्या है और इनमें पानी भरा रहता है। इनमें लिलोड और सुधराणा गांव तो मेरे हल्के के ही हैं। इन गांवों में सेम की समस्या के बारे में एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों से मैं मिला था और उनसे विस्तार से चर्चा भी हुई लेकिन एन.टी.पी.सी. के अधिकारी कहने लगे कि उनके प्लांट के पानी की वजह से यह सेम की समस्या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी को स्टोर करने के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा तीन बड़े टैंक लगाये गये हैं। एन.टी.पी.सी. द्वारा उस पानी से जो कोयला धोया जाता है उसका पानी बाहर निकलता है। उस कारण से यह सेम की समस्या पैदा हो रखी है। वर्ष 2016 से पहले भी इस समस्या के कारण किसानों ने वहां धरना प्रदर्शन किया था। जिसके कारण 2016 में किसानों को एन.टी.पी.सी. ने मुआवजा भी दिया था। अब फिर एन.टी.पी.सी. के अधिकारी किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि वे फिर से धरने पर बैठें। मेरो अनुरोध है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और एन.टी.पी.सी. से उन किसानों को मुआवजा दिलवाये। अध्यक्ष महोदय, किसानों की दुनिया खेती है और वे उसके बाहर नहीं जा सकते। इस प्लांट के कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम किसानों के फायदे की बात करते हैं। इस विषय पर किसानों के साथ न्याय किया जाये या तो सरकार उस भूमि को किसी एजैंसी द्वारा अधिग्रहण करवाये या उन किसानों को मुआवजा दिलवाने का काम करवाये। अध्यक्ष महोदय, अब मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि कोसली उप मंडल को नये विकास खंड का दर्जा दिया जाये। यह बात मैंने पहले भी सदन में रखी थी। मैं देख रहा था कि हरियाणा में ऐसा कहीं भी नहीं है कि सबडिवीजन हो और वहां पर खंड न हो। कोसली पहला पंचायत सब डिवीजन है जहां पर खंड कार्यालय नहीं बना है इसलिए इसको जल्द बनवाने का काम किया जाए। इसी तरह से कोसली विधान सभा क्षेत्र में कृष्णा नगर गांव में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का रीजनल सैंटर खुला हुआ है। उस रीजनल सैंटर की जमीन पर अच्छे से बिल्डिंग बनी हुई है और वहां के लोग यूनिवर्सिटी की बाट देख रहे हैं। मेरी मांग है कि वहां पर यूनिवर्सिटी बना दी जाये क्योंकि वहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी यूनिवर्सिटिज है। अगर वहां यूनिवर्सिटी बना दी जाती है तो यह वहां के लोगों के लिए वरदान साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कोसली से महेन्द्रगढ़ सड़क को हमारी सरकार चारमर्गी बनाये। वह रोड आज टूटा हुआ है उसकी मुरम्मत का काम तुरंत करवाया जाये। मेरे हल्के के तीन छोटे–छोटे रोड हैं जाटूसाना से गुड़यानी रोड की रिपेयर

का कार्य करवाया जाये। इसी तरह से भैठेड़ा से देवलावास गुलाबपुरा रोड़ का पैसा भी सैंक्शन है लेकिन पता नहीं सरकारी अधिकारी वह काम स्पीड से क्यों नहीं करवा रहे हैं। पैसा न हो तो लाचारी हो सकती है लेकिन पैसा होते हुए भी वह कार्य स्पीड से क्यों नहीं करवा रहे हैं। कभी कह देते हैं कि एन.टी.पी.सी. की प्रॉब्लम आ रही है कभी बरसात की प्रॉब्लम कह देते है। इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये और यह कार्य तेजी से करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 33 के.वी. पॉवर हाउस गुरावड़ा तथा 33 के.वी. पॉवर हाउस पालावास, दोनों 132 के.वी. पॉवर हाउस, गंगायटा जाट की एक ही बिजली लाइन से जुड़े हुए हैं जिसके कारण इन पर अधिक लोड रहता है इसलिए इन दोनों को अलग–अलग लाइन बिछाकर चलाया जाये ताकि इन पर अधिक लोड न पड़े। हमारे विपक्ष के एक साथी कह रहे थे कि बजट में रेवाड़ी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि बजट में रेवाड़ी में फ्लोर मिल तथा ऑयल मिल खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर रेवाड़ी की सड़कों की बात की जाये तो रेवाड़ी–वाया पटौदी–नारनौल सड़क का बजट में प्रावधान दिया हुआ है। इसके साथ–साथ रेवाड़ी में बस स्टैंड के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। हमारे विपक्ष के साथी 35 साल से सत्ता में रहे लेकिन इनको रेवाड़ी के बस स्टैंड की याद नहीं आई और अब जब यह बस स्टैंड बनने लग गया है तो अब उसका क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। इसी तरह से उन्होंने रेवाड़ी में मैडिकल कॉलेज की बात उठाई कि रेवाड़ी में मैडिकल कॉलेज बनना चाहिए तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब रेवाड़ी में एम्स बन रहा है तो मैडिकल कॉलेज की जरूरत कहां है क्योंकि एम्स मैडिकल कॉलेज से बड़ा होता है। अंत में मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि –

साथ–साथ चलने का इरादा जब जमा हो जायेगा,
आदमी से आदमी का कारवां बन जायेगा,

तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन,

तू भी किसी के लिए आसमां बन जायेगा। धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी (कालका) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। वित्त वर्ष 2022–23 का जो बजट पेश हुआ है उस पर बहुत से सदस्यों द्वारा चर्चा की गई है। जब भी बजट पेश होता है तो युवा, किसान, व्यापारी और हर वर्ग की बजट पर निगाह होती है और सभी को बजट से बहुत उम्मीद होती है। यहां सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से

बजट के बारे में कहा गया है कि सभी की भलाई और सभी को खुशी प्रदान करने वाला बजट है। आज प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी आज दुखी और परेशानी झेल रहा है क्योंकि अगर मैं रोजगार की बात करूं तो 200 रोजगार मेले लगाने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को कोई रोजगार देना है या कोई अपना छोटा–मोटा कारोबार करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाये, या फिर सरकार उसको नौकरी दे या कोई इंडस्ट्री लगाने में मदद करे। आज अगर इंडस्ट्री लगानी होती है तो किसान अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता। हमारे क्षेत्र में एच.एम. टी. की 800 एकड़ से ज्यादा जमीन पड़ी है जहां पिछले दिनों कुछ एकड़ में सेब मंडी बनाने का काम किया गया। इसी तरह से सब्जी मंडी भी बनाई जा रही है। लगभग 750 एकड़ जमीन एच.एम.टी. की पड़ी हुई है। पहले जहां एच.एम.टी. में 7 से 8 हजार वर्कर थे आज वह ट्रैक्टर प्लांट बंद हो गया और मात्र 130 लोग उसमें काम कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारी मशीनरी ऐसे ही पड़ी हुई है। उसमें कौशल विकास केन्द्र बना हुआ है। वहां पर लुधियाना की तरह कोई स्पेयर पार्ट्स का हब बनाया जा सकता है या कोई और इंडस्ट्री वहां पर स्थापित करके उस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा सकता है क्योंकि आज बेरोजगारी के कारण युवा नशे या दूसरे अपराधिक मामलों में संलिप्त होते जा रहे हैं इसलिए एच.एम.टी. की खाली जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा कर उस जमीन का सदुपयोग किया जाये। आज महंगाई आसमान छू रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर चण्डीगढ़, पंजाब में डीजल के भाव कम हो सकते हैं तो डीजल और पैट्रोल पर टैक्स कम करके हरियाणा में भी इनके भाव कम किये जाने चाहिएं ताकि आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके। इसी तरह से अगर मैं सड़कों की बात करूं तो सड़कों की हालत बहुत बुरी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूरजपुर से सुखो माजरी बाईपास 7 किलोमीटर का एरिया है जिसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। यह वर्ष 2016 में एच.एस.वी.पी. ने पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपा था लेकिन 5–6 साल से यह काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें रेलवे से परमिशन लेनी है। रेलवे से परमिशन लेकर उस काम को सिरे चढ़ाया जाए ताकि हमारे पिंजौर व कालका की जाम की समस्या का हल हो सके। इसी तरह से हमारे पिंजौर में जो आर.यू.बी. बन रहा है उसको बनते हुए कई–कई वर्ष हो गये हैं अर्थात वह वर्ष 2018 से चलता आ रहा है। उसके बनने में अभी भी रूकावट आ रही है। उसके लिए वहां कहीं शोरूम के

आगे क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं जिससे वहां पार्किंग की असुविधा हो रही है। उसकी वजह से लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से नालागढ़ रोड पर जो आर.ओ.बी. बन रहा है वहां भी लोगों का कहना है कि उस आर.ओ.बी. को पिलर्स पर बनाया जाए। जैसे जिरकपुर में बना हुआ है ताकि उसके नीचे पार्किंग की सुविधा मिल सके। रिटेनिंग वाल न बनाई जाए। इसके लिए लोग वहां धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर अब डिजाईन ही पिलर्स पर बनाने का आ रहा है तो उसको पिलर्स पर ही बनाना चाहिए। इसी तरह अगर मैं बुजुर्गों के मामले की बात करूं तो जैसे बुजुर्गों को 5100 रुपये पैंशन देने का वायदा किया गया था। उस संबंध में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर बुजुर्गों को 5100 रुपये पैंशन नहीं दी जाती है तो कम से कम उनको प्रताड़ित तो न किया जाए और उनकी पैंशन काटने का काम तो न किया जाए। जो पैंशन उनके सम्मान में मिली थी वह पैंशन उनको उनके सम्मान में मिलनी चाहिए। इसी तरह से जो विकलांगों और विधवाएं हैं उनमें कई विकलांग ऐसे भी हैं जो 100 प्रतिशत दिखाई देते हैं लेकिन उनको यह कहा जाता है कि इनकी वैरिफिकेशन होकर पैंशन लगाई जाएगी जिसकी वैरिफिकेशन हैड ऑफिस से होगी। इस प्रकार से जिन विकलांग की पैंशन नहीं लगी हैं उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो सरकार व मंत्री जी का यह कहना है कि हम किसी के कहने से कोई पी.एच.सी. या होस्पिटल नहीं बनाएंगे। हम खुद चिन्हित करेंगे लेकिन हमारी मोरनी की जो पी. एच.सी. है उसके नियम पूरे नहीं होते हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जहां पी. एच.सीज. के नियम पूरे नहीं होते हैं उन पी.एच.सीज. को भी सी.एच.सी. बनाने का काम किया जाए। जहां तक स्कूल अपग्रेड करने की बात है हमारे कुतबेवाला के स्कूल को अपग्रेड करने के लिए मैं मंत्री जी से भी मिला था। ऐसे और भी कई स्कूल्ज हैं जिनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा का विस्तार हो और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर न जाना पड़े। इसी तरह से मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। जैसे हमारे मोरनी में भी एक मॉडल संस्कृति स्कूल खोला गया है। वहां पर बहुत बच्चे भर्ती हो गये हैं इसलिए वहां पर स्टाफ व बाकी सभी सुविधाएं देने का काम भी किया जाए। इसी तरह जहां तक कॉलोनीज की बात है और जिनको 100–100 गज के प्लॉट दे रखे हैं उनको अभी तक कब्जा नहीं मिल पा रहा है। वहां जो कॉलोनीज हैं वे भी रेगुलराईज नहीं हो रही हैं। यह तीसरा बजट पेश हो गया है लेकिन जो कॉलोनीज रेगुलराईज नहीं हुई हैं उनको

मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जबकि उनकी रजिस्ट्रियां हो रखी हैं, बिजली कनैक्शंज हो रखे हैं। अगर वहां हम पीने के पानी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम पीने का पानी नहीं दे सकते हैं। हम पीने के पानी के लिए हैंड पम्प जरूर लगा सकते हैं। इसी तरह से पब्लिक हैल्थ के लिए पता नहीं इस बजट में हमारे एरिया के लिए कुछ रखा है या नहीं क्योंकि मैं तीन साल से देख रहा हूं कि हमारे पिंजौर, कालका और मोरनी में उसी तरह पीने के पानी की समस्या है। अगर वहां पर कम से कम 15–20 ट्यूबवैलज लगाए जाएं तब जाकर वहां पीने के पानी की समस्या का हल होगा क्योंकि अभी सर्दी है और गर्मी आने वाली है। इसी तरह यहां राशन कार्ड की बात भी आई है जिसका मैंने क्वैश्चन भी लगाया था। उसमें उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि अभी साईट बंद है। इसको जल्दी ही खोल दिया जाएगा। आज बहुत ऐसे पात्र परिवार हैं जिनको राशन चाहिए लेकिन उनके बी.पी.एल. कार्ड नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वे बंद पड़े हैं। इसी तरह से आवारा पशुओं की रोकथाम और किसानों की आय को दुगुनी करने की बात की जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के लोग आज सुबह भी मेरे पास आए थे जो कह रहे थे कि हमने तो फसल बीजनी ही बंद कर दी है क्योंकि जंगलों से जो आवारा पशु आते हैं वे फसलों को नष्ट कर जाते हैं। हौर्टिकल्चर की एक सोलर फैंसिंग लगाने की स्कीम थी। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि इन चीजों की ओर ज्यादा ध्यान दें ताकि किसानों की परेशानी व दिक्कतों का कोई हल हो सके। धन्यवाद।

श्री राम कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना अच्छा और बढ़िया बजट प्रस्तुत करके हर क्षेत्र व हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाने का काम किया है। निश्चित तौर से आगे चलकर यह बहुत ही कल्याणकारी बजट सिद्ध होने जा रहा है। वैसे तो इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण घोषणायें की गई हैं लेकिन जो दो महत्वपूर्ण घोषणायें हैं, मैं सबसे पहले उनका जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पहली घोषणा पर्यावरण के बारे में है और दूसरी घोषणा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के बारे में है। 50 साल पहले जो हमारा खान–पान हुआ करता था आज उस खान–पान में बदलाव आ गया है। आज हमारा खान–पान दूषित हो गया है। इसका कारण यह है कि जो हम उत्पादन करते जा रहे हैं चाहे वह गेहूं है या

चावल है उसमें भारी मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी वजह से छोटी उम्र में बीमारियों बढ़ रही है। कैंसर की समस्या भी दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, छोटी उम्र में ही डायबिटीज बढ़ रही है, बी.पी. बढ़ रहा है, थॉयराईड बढ़ रहा है और अगर हम इनकी रोकथाम करना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतने गंभीर विषय पर चिंता जाहिर की है और यही कारण है कि उन्होंने बजट में प्राकृतिक और जैविक खेती को विशेष तौर पर बढ़ावा देने की बात की है। जब एक किसान प्राकृतिक खेती करता है जैविक खेती करता है तो निश्चित तौर से तीन साल तक तो उसकी इंकम तो कम होगी ही होगी और इस अवधि के दौरान जबकि किसान की इंकम कम होगी तो उस अवधि के लिए किसान का घाटा पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में उचित प्रावधान करने का भी काम किया है जोकि बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ ही जो भिवानी में मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए एक अनुसंधान केन्द्र खोलने का काम किया गया है, यह अनुसंधान केन्द्र विशेष रूप से बाजरा या अन्य मोटे अनाजों पर अनुसंधान करने का काम करेगा और इनका उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर भी काम करेगा। स्पीकर सर, मैं एक बात यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि डाक्टर खेदर वाली जोकि पिछले 25 साल से मिलेटस के उपर रिसर्च कर रहा है, वह रिसर्च करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा और उसने मिलेटस को तीन सीरीज में बांटने का काम किया। पहला पोजेटिव मिलेटस, दूसरा नैगेटिव मिलेटस और तीसरा न्यूट्रल मिलेटस। नैगेटिव मिलेटस की श्रेणी में गेहूं और चावल को रखने का काम किया गया क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता है और गलूकोज ज्यादा होता है। फाइबर की मात्रा गेहूं में 1.25 परसेंट होती है, धान में .0 परसेंट होती है इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान कर रहे हैं और बीमारियों को बढ़ाने का काम करते है। अगर इंसान इनको खायेगा तो वह स्वस्थ नहीं रह पायेगा और उसकी बीमारी दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी। जो न्यूट्रल मिलेटस होते हैं, इनके अंतर्गत जौं–बाजरा–रागी और मक्की को रखा गया है। डाक्टर खेदर वाली का कहना है कि जो इन अनाजों को खायेगा अगर वह स्वस्थ है तो बीमार नहीं होगा और अगर बीमार है तो उस व्यक्ति में ये रोग नहीं आयेंगे। जो पोजेटिव मिलेट्स होते हैं इनका नाम उसने श्री धान्य देते हुए इसके अंदर पांच मिलेटस शामिल किए हैं

जिनका नाम है होदरा, कंगनी, हरी कंगनी, कुटकी तथा स्वांख और इनकी विशेषता यह है कि जो आदमी इनको खायेगा अगर वह बीमार है तो उसकी बीमारी भी दूर हो जायेगी चाहे कैंसर की बीमारी ही क्यों न हो। कैंसर को भी खत्म करने की क्षमता इन अनाजों में होती है क्योंकि इनमें फाइबर 8 परसेंट से 12 परसेंट तक होती है और ग्लूटेन तो इनमें होता ही नहीं है इसलिए यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताये गए हैं। अतः इसके ध्यानार्थ सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सरकार ने जो अनुसंधान केन्द्र भिवानी में खोला है, इसमें इन अनाजों को भी शामिल किया जाये और सरकार को इन अनाजों को पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह खेती पंजाब ने तो शुरू कर दी है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में भी लोग इनको यूज कर रहे हैं और इनकी कीमत 170—175 रूपये प्रति किलो के हिसाब से तय की गई है। अध्यक्ष महोदय, इन अनाजों का भी अनुसंधान करके, इनकी खेती को प्रोत्साहन देने का काम किया जाये ताकि हम सब स्वस्थ रह सके। यह जो खेदर वाली है इसको मिलेट्स मैन भी कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यू.एन.ओ. ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और इससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 को भी भारत वर्ष का मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था। वर्तमान समय में इसकी महता बहुत ज्यादा बढती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्यावरण की बात करता हूँ। यह भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि संबंधित विषय के लिए स्वर्गीय दर्शन लाल पुरस्कार का प्रावधान किया गया है तो इस विषय के साथ मैं यह बात जोड़ना चाहूंगा कि इस पुरस्कार के लिए एक निश्चित क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए। जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है तो ऐसे मौसम में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो देखने में आता है कि जो हमारी सड़कें है या लिंक रोड हैं, इनके साथ साथ आग लग जाती है, वैसे तो इस आग को बुझाने का कोई न कोई प्रोविजन होना चाहिए लेकिन बावजूद इसके जो व्यक्ति इस तरह की आग को बुझाने में योगदान करे तो उनको भी इस पुरस्कार को दिए जाने में यदि शामिल किया जाये तो बहुत अच्छा होगा। हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड का गठन नहीं हुआ है और न ही हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से यह कहना है कि यह बोर्ड और कमीशन पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं। यह प्रदेश के लिये कल्याणकारी सिद्ध होंगे, इसलिए इनका गठन होना

चाहिए। अध्यक्ष महोदय, करनाल से लाडवा वाया इंद्री जो चारमार्गीय सड़क जाती है उसका काम शुरू हो चुका है। करनाल से लेकर खानपुर तक काम कम्पलीट हो गया है, लेकिन 8 किलोमीटर का एक टुकड़ा जो लाडवा को कनैक्ट करना था, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कर रखी है। अब लाडवा से इंद्री तक लगभग 4 किलोमीटर तक तो काम शुरू हो गया है लेकिन बीच का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का फिर से रूक गया है। अभी पेडों की कटाई का काम है और एन.ओ.सी. का भी काम है तो 2 किलोमीटर के रास्ते का काम भी इसके साथ सरकार को करना चाहिए क्योंकि यह सड़क लाडवा, यमुनानगर को कनैक्ट करने का काम करेगी। एच.एस.ए.एम.बी. की सड़कों को जिला परिषद् को नहीं दिया जाये बल्कि ये सड़कें बोर्ड के पास ही रहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हरियाणा सरकार महापुरूषों व ऋषि मुनियों की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाने का काम करती है, इसके लिये मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग यह है कि इसी तरह से महर्षि कश्यप जयंती जो 5 अप्रैल, 2022 को आने वाली है, उसे भी प्रदेश स्तर पर मनाने का काम हरियाणा सरकार को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सत्र के दौरान जब आवारा कुत्तों के बारे में चर्चा हो रही थी। उसके दो–चार दिन पहले मेरे हल्के का एक गांव कलरी नन्हेड़ा में पाल गडरिया समाज के श्री बसी लाल व श्री सुखराज की लगभग 70 भेड़ों को आवारा कुत्तों ने मारने का काम किया था। उनको बड़ी संख्या में घायल कर दिया है, जिसके चलते उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाये ताकि उनकी कुछ न कुछ भरपाई हो सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कलरी जागीर गांव के पास आवर्धन नहर चलती है, नहर की वजह से श्मशान घाट 4 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है, यदि उस आवर्धन नहर के ऊपर पुल बन जायेगा तो उनका डिस्टेंस केवल 700 मीटर तक रह जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कलरी जागीर गांव के पास आवर्धन नहर पर पुल बनाने का काम जल्दी शुरू करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इंद्री विधान सभा की सड़कें बहुत खराब है, इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गढ़ी बीरबल से हिनोरी तक, शेरगढ़ से हिनोरी रोड तक, नेवल से गुमथला राव तक, ब्याना से इंद्री तक, इंद्री से उमरी कुरूक्षेत्र तक, गढ़ी बीरबल से यमुना घाट तक, रंबा से संगोही तक, खुखनी से धनोरा पुल तक, हिनोरी पुल से कैहरबा तक, कुराली से रंबा तक,

माखू माजरा से बड़ा गांव तक, रैतखाना से गढ़ी सदान तक, कलरी नन्हेड़ा से गढ़पुर खालसा तक, नेवल से जड़ौली तक और धनोरा से बड़शामी मैन रोड कुरूक्षेत्र यमुनानगर तक रिपेयर की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सुधीर कुमार (गुरूग्राम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोलने से पहले सदन में एक बात कहकर हंसी मजाक का माहौल बनाता हूँ। अभी श्री चिरंजीव राव जी कह रहे थे कि तुम्हारी चार स्टेट में सरकार आ गई है तो ज्यादा उत्साहित न हो। मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वाले ज्यादा उत्साहित थे, हमें तो पहले से ही पता था। इस बारे में मेरा कहना है कि यमराज एक आदमी को कहता है कि आपका समय समाप्त हुआ, अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बताइये। वह आदमी यमराज को कहता है कि एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार देखना चाहता हूँ। इस पर यमराज ने कहा कि चालाक प्राणी अमर होना चाहता है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022 के बजट पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा कि जिनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश दिन प्रतिदिन नई–नई ऊंचाइयों को छू रहा है और ज्यादा समृद्ध होता जा रहा है। इसके साथ–साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का पुनः धन्यवाद करता हूँ जो मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का मौका दे रहे हैं। इस बजट में हमारे गुरूग्राम के लिए काफी प्रोविजंस किये गए हैं और हमारे गुरूग्राम में काफी काम हो रहे हैं । इस बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने का भी प्रावधान किया गया है । गुरूग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल और पानीपत में बाल श्रम केन्द्र खोले जाएंगे । अरावली की पहाड़ियों में जल संरक्षण के लिए एक चैक डैम का भी निर्माण किया जाएगा । गुरूग्राम के खेड़की दौला में एक बस पॉर्ट बनेगा । इसके अलावा गुरूग्राम में एक हैलीपैड भी बनेगा । अतः गुरूग्राम में इतनी सारी सुविधाएं और सौगात देने के लिए मैं गुरूग्राम की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं दो लाइनें पढ़ना चाहूंगा –

चलो चलकर हम भी अपना आशियाना बना लें,

जिंदगी जीने का एक सहारा बना लें ।

अध्यक्ष महोदय, रोटी कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की प्राथमिक जरूरतें होती हैं। रोटी और कपड़े का तो व्यक्ति किसी तरह इंतजाम कर लेता है परंतु जब मकान बनाने की बात आती है तो वह उसके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है । हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह कम से कम दाम पर अच्छे से अच्छा मकान बना ले लेकिन हर व्यक्ति मकान खरीदते वक्त जमीन की बारीकियों को नहीं समझ पाता । इस कारण कई बार कुछ लोग अपने जीवन की पूंजी से मकान तो बना लेते हैं परंतु उन्हें बाद में पता चलता है कि जहां पर उसने मकान लिया है वह कॉलोनी तो अनाधिकृत है । इस विषय पर मेरा एक सुझाव है कि अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिससे लोगों को गम्भीर समस्याओं का सामना न करना पड़े । अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी सदन में इस बात को उठाया था कि गुरूग्राम में वायु सेना के आयुध डिपो बहुत पुराने समय से है परंतु बदलते समय के साथ और बढ़ते शहरीकरण की वजह से उसके आसपास जो जगह पहले खाली थी अब वह भी भर गई है । इसकी वजह से डिपो के आसपास तोड़–फोड़ चलती रहती है और यह मामला भी काफी पुराना है । इसका दायरा 900 मीटर है । मैं आग्रह करूंगा कि जब तक माननीय अदालत का वायु सेना के प्रतिबंधित दायरे को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस समस्या को सुलझाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे गुरूग्राम में शीतला माता मंदिर के पास, भीमगढ़ खेड़ी के पास, डी.एस.डी. कॉलेज के पास और सिलोखरा के पास जलाशय हैं । इन जलाशयों का पुनरूद्धार किया जाए ताकि आस–पास के क्षेत्र में जल की कमी दूर हो जाए और इनके माध्यम से बरसात के समय भूमिगत जल रिचार्ज हो सके । इस कार्य से जल का भूमिगत लैवल जो कम हो गया है वह भी समय के साथ ठीक हो सके । इससे हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने में हमें आसानी होगी । गुरूग्राम में विश्व की प्रसिद्ध मल्टी नैशनल कम्पनीज व अनेक कार्यालय हैं । इनके कारण देश–विदेश से व कई राज्यों से लोगों का गुरूग्राम में आना–जाना लगा रहता है । गुरूग्राम का बस स्टैण्ड शहर के बिल्कुल केन्द्र में स्थित है । इस कारण बस स्टैण्ड के आस–पास के क्षेत्रों में सुबह–शाम जाम लगा रहता है । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि गुरूग्राम के बस स्टैण्ड पर

जाम से मुक्ति के लिए एक इंटरसिटी बस स्टैण्ड बनाया जाए और इंटरडिस्ट्रिक्ट बस स्टैण्ड शहर से बाहर स्थापित किया जाए । अध्यक्ष महोदय, नये गुरूग्राम की तरफ मैट्रो की कनैक्टिविटी काफी अच्छी है । वहां पर दिल्ली और एन.सी.आर. से मैट्रो द्वारा यात्रियों का आना–जाना काफी सुगम व सुविधाजनक है । नये गुरूग्राम में रैपिड मैट्रो भी चलती है जोकि साइबर सिटी और गोल्फ कोर्स रोड को कवर करती है । पुराने गुरूग्राम में एक भी मैट्रो लाइन या कनैक्टिविटी नहीं है जिससे गुरूग्राम के निवासियों को नए गुरूग्राम की साइड आकर दिल्ली या अन्य स्थानों पर जाने के लिए मैट्रो का उपयोग करना पड़ता है । यहां के निवासियों ने कई बार मुझसे आग्रह किया है कि मैट्रो की लाइन यहां भी होनी चाहिए जिससे गुरूग्राम के निवासियों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिले । इस मैट्रो प्रोजैक्ट के तैयार होने के बाद लाखो लोगों को फायदा होगा । रोजगार के लिए गुरूग्राम से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले और दिल्ली से गुरूग्राम आने वाले यात्रियों के लिए तो यह बहुत बड़ी सौगात होगी । अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी सदन का ध्यान गुरूग्राम में चिकित्सा सेवाओं में कमी की ओर दिलाया था । मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुराना गुरूग्राम व छोटी बस्तियां अधिक हैं । वहां पर 15 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं । इसके बावजूद वहां पर केवल एक ही सरकारी सामान्य अस्पताल सैक्टर–10ए में स्थित है । इस बारे में मेरा सुझाव है कि राजीव नगर, शीतला कॉलोनी, अशोक विहार, लक्ष्मण विहार, राजेंद्रा पार्क, देवी लाल नगर, प्रताप नगर, आदि कॉलोनियां में सरकार द्वारा मोबाइल चिकित्सा शुरू की जानी चाहिए। इसके द्वारा आप मोबाइल चिकित्सा सेवा की 5 बसें चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित तथा अनुभवी चिकित्सकों के साथ रोटेशन के आधार पर इन कॉलोनियों में ओपीडी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करवाने की मेरी प्रस्तावना है। इसके अतिरिक्त गुरूग्राम के व्यापारिक संगठन के व्यापारी कुछ समय पहले मुझसे मिले और अपनी लिखित मांग मुझे दी। उन्होंने मुझे बताया कि दौलताबाद इंडस्ट्रीयल एरिया तब से काम कर रहा है जब हरियाणा एक प्रदेश नहीं था, इस एरिया में 4,000 से अधिक स्मॉल स्केल, माइक्रो और मीडियम इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। इनकी बहुत पुरानी मांग है जो बहुत समय से एम.सी.जी. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. के पास लंबित है। इस संगठन की मांग है कि दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया बहुत लम्बे समय से मांग कर रहा है कि इसको बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विसेज दी जाएं। इस इंडस्ट्रीयल एरिया को अभी तक एप्रूव्ड स्टेट्स भी नहीं मिला है जबकि बिल्डर्ज

की कॉलोनी और फलैट्स बनाने की परमिशन दी जा चुकी है। इस इंडस्ट्रीयल एरिया में 2 से 3 लाख लोग काम करते हैं जिन्हें बेसिक सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन एरियाज को विकसित किया जाए और सभी लोगों को उचित सुविधाएं दी जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए 75 साल हो गये हैं। हमने इन 75 वर्षों में अंग्रेजी इतिहास को खत्म करके भारत को फिर से उसी स्वर्णिम पटल पर पहुंचाने का प्रयास किया है, जिस पर पहले कभी भारत देश हुआ करता था लेकिन जब मैं सैक्टर– 55 के आसपास से गुजरता हूं तो वहां की सड़कों का नाम सैंट जांन्स मार्ग और सैंट गबरिल मार्ग पड़ा मिलता है। आज भी मुझसे काफी युवा मिले थे और वे कहते हैं इन सड़कों का नाम बदल दिया जाए। हमारे यहां पर इतने महानुभाव महान योद्धा हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी सदन के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इन सड़कों का नाम जल्दी से जल्दी बदलकर किसी भी देशभक्त के नाम पर रख दिया जाए। आपकी अति कृपा होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

श्री सीता राम यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी के रूप में 1 लाख 77 हजार 255 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और कोई दूसरा बजट नहीं हो सकता। इस बार किसान, कृषि, पशुपालन और डेयरी, खेल तथा अन्य दूसरे विभागों के लिए पिछले बजट की अपेक्षा ज्यादा राशि का प्रावधान करने का काम किया है, यह बजट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किया गया और इस बजट में महिलाओं और हमारी बेटियों के लिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जैसे कि सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र व 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने का समावेश किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत– बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन बनाने, शहरों के सामाजिक सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विकास के लिए दिव्य नगर योजना शुरू करना, जिला परिषदों को दिये जाने वाले बजट में वृद्धि करना, 300 किलोमीटर नयी सड़कें बनाने, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए समर्थन निधि योजना के तहत 3,00,000 रुपये के कर्ज का प्रावधान करना, राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी राज्य खेल संस्थान स्थापित करना, पी.डी.एस.

योजना को पीपीपी मोड पर तैयार करना, शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250 करोड़ रुपये आबंटित करना, मेधावी छात्र योजना का दायरा बढाना, संस्कृति मॉडल स्कूल्ज की संख्या बढाना, लड़कियों के लिए परिवहन सुविधा सुलभ कराने के लिए योजना शुरू करना, प्रदेश में 10 हाईटेक नर्सरियों को स्थापित करना, कृषि क्षेत्र के लिए 5988 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान करना तथा कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा पंचकुला में महिला हॉस्टलों का निर्माण करना, अनेकों प्रकार के वह महत्वपूर्ण बिन्दू हैं जिन पर आने वाले समय में काम होगा और हरियाणा प्रदेश विकास की गति पर आगे बढता हुआ नजर आएगा। अध्यक्ष महोदय, कोविड– 19 महामारी के बाद यह बजट निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट साबित होगा। यह बजट आने वाले वर्षों में विकास की नयी इबारत लिखने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा प्रदेश का योगदान 3.4 प्रतिशत है।

————————

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

————————

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सीता रामः अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने की अवधारणाा को मूल रूप देने की कोशिश में बहुत मददगार साबित होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बिजली व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक पारदर्शी कदम उठाकर सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शी शासन देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को स्पष्ट करने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार बनकर जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली सरकार बनेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ''हरियाणा एक, हरियाणवी एक'' की अवधारणा पर काम करते हुए शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे की कड़ियों को और मजबूत करने की दिशा में काम

किया है। अध्यक्ष महोदय अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगें सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। यह मांग इस प्रकार हैं कि अटेली तहसील को उपमंडल बनाने की मांग 16 फरवरी 2020 को प्रगति रैली के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष रखी थी। मुझे यह भी पता लगा है कि हमारी कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है और जनगणना होने के बाद बहुत जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जायेगी। दूसरा गांव दौंगड़ा अहीर को उप तहसील का दर्जा दिया जाये क्योंकि 16 फरवरी 2020 को प्रगति रैली के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ग्रामीणों को इसके लिए आश्वस्त किया था कि हम आपकी इस मांग को पूरा करेंगे। खेत खलिहान की स्कीम के तहत जो 25 किलोमीटर के रास्ते पक्के किए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में ये 25 किलोमीटर रास्ते हर साल हर विधान सभा में किये जायें। पौंड अथॉरिटी योजना के तहत नहरों का साफ पानी, जोहड़ों का सौंदर्यकरण करने के काम में तेजी लाई जाये तथा गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर कृषि के उपयोग के लिए पानी को साफ करने के कार्य में भी तेजी लाई जाये क्योंकि काम बहुत ही धीमी गति से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि अहीर रैजिमैंट को सदन में रिकमंड करके सैंटर गवर्नमैंट के पास भेजने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अटेली व कनीना नगरपालिकाओं में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रिहायशी मकान बने हुए हैं लेकिन वहां पर पानी व सीवर की सुविधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि दोनों नगर पालिकाओं का एरिया बढ़ाया जाये ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कनीना के बस स्टैंड का भवन जर्जर हो चुका है उस भवन को नया बनाया जाये। इसके अलावा अटेली बस स्टैंड की भी हालत ठीक नहीं है इसलिए इस बस स्टैंड के रोड को भी ठीक करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए पुनः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 16 मार्च, 2022 बुधवार, प्रातः 10:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

*18:33 बजे

(तत्पश्चात् सभा बुधवार दिनांक 16 मार्च, 2022 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)